R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 05
01 से 15 दिसम्बर 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

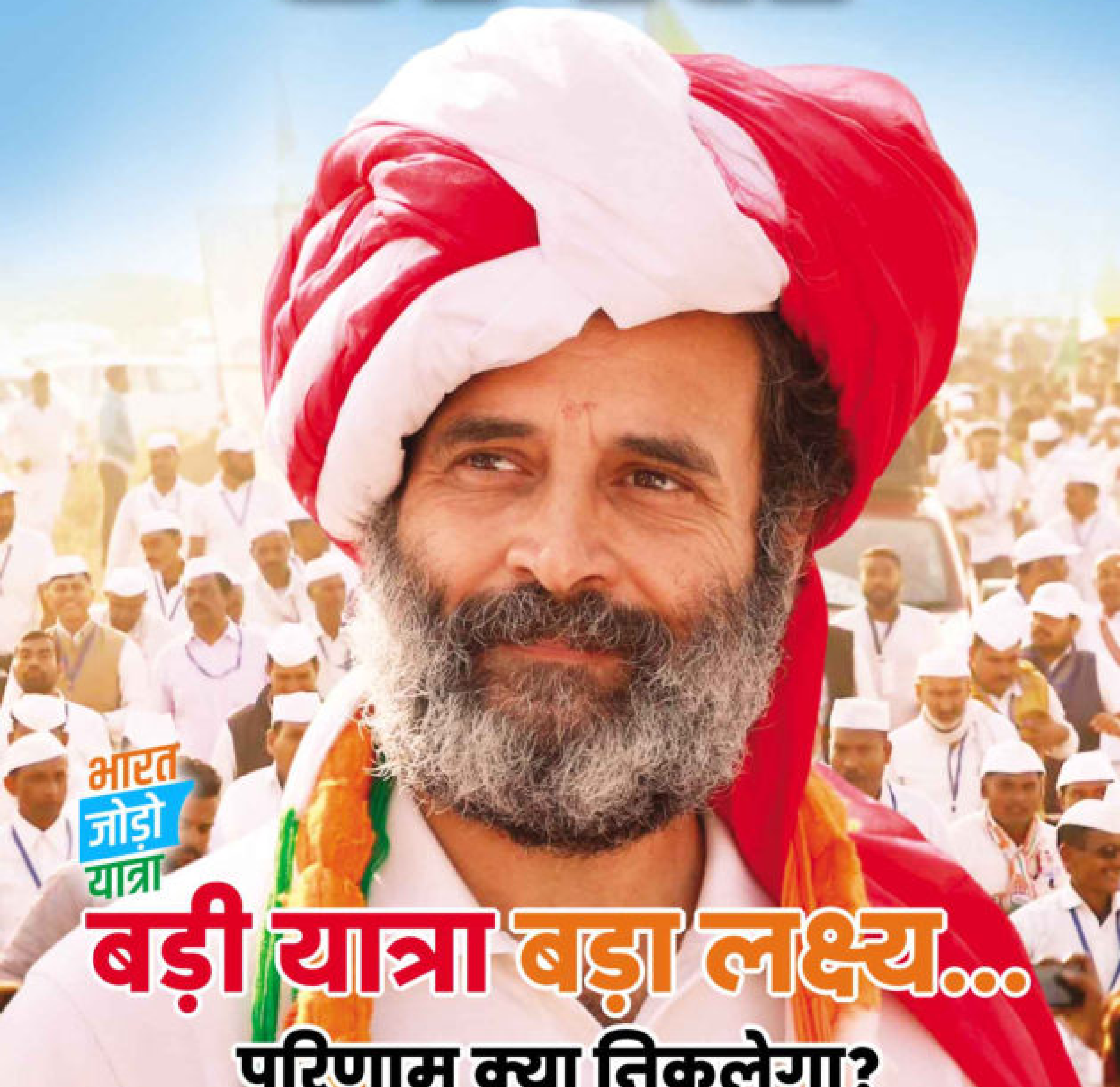

भारत जोड़ो यात्रा

बड़ी यात्रा बड़ा लक्ष्य...

परिणाम क्या निकलेगा?

बिगड़े समीकरणों को सुधार रही भारत जोड़ो यात्रा

क्या कांग्रेस उमड़ रही भीड़ को बदल पाएगी वोट में?

एन सी एल
NCL

Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)
A Subsidiary of Coal India Limited
Singrauli (M.P.) India - 486889

www.nclcil.in

/northerncoalfields
@NCL_SINGRAULI
YouTube /northerncoalfields

इस अंक में

वल्लभगाथा

9 | अब 6 माह की पारी

मप्र के मुख्य सचिव को लेकर अटकलें खत्म हो गई हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ही अगले 6 माह तक प्रदेश के मुख्य सचिव बने रहेंगे। बैंस 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे, जिसके बाद नए सीएस...

राजपथ

10-11 | शिव 'राज' का मप्र...

मप्र देर से ही सही अपने गठन के समय बुझी संभावनाओं को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खासतौर से पिछले डेढ़ दशक का अरसा इस बात का गवाह रहा है कि मप्र विकास के पथ पर अब आगे ही आगे है।

विधानसभा

15 | शीतकालीन सत्र में बजट की झलक

मप्र की 15वीं विधानसभा का अंतिम शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होगा। पांच दिवसीय इस सत्र में सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही नगर पालिक विधि संशोधन, लोक सुरक्षा विधेयक सहित अन्य...

पहल

18 | ग्रीन फील्ड योजना में शामिल होगा...

केंद्र सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 15वें वित्तीय आयोग के तहत देश के 8 शहरों को ग्रीन फील्ड योजना में शामिल किया जाना है। इस योजना में शामिल होने वाले शहर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। देश में 8 नए शहर विकसित करने की प्रतियोगिता...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू होकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से होकर अब मप्र की धरती पर पांव रख चुकी है। इस यात्रा में जैसे हर प्रदेश के अलग-अलग रंगों, विविध लोगों-लोकाचार को अपने में समाहित करने का जोश दिलचस्पी जगाता है। यह यात्रा अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक यात्रा है, तो इसका लक्ष्य भी बड़ा है। इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के अभेद गढ़ कहे जाने वाले मालवा-निमाड़ क्षेत्र में चल रही है।

20

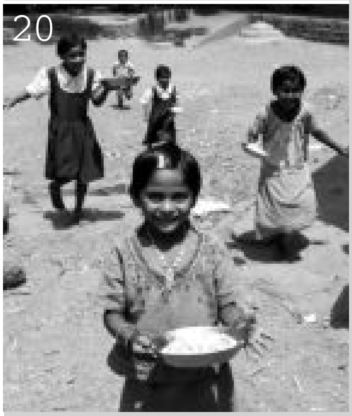

29

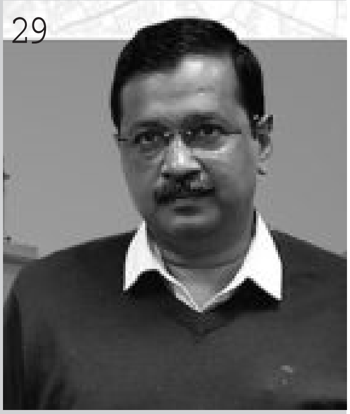

44

45

राजनीति

30-31 | चेहरे बदल जाएंगे...!

लोकसभा चुनाव में अभी भले ही डेढ़ साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी ताना-बाना बुना जाने लगा है। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बनने के लिए नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन बिखरे हुए विपक्ष की एकता का सूत्रधार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।

महाराष्ट्र

35 | महापुरूषों की राजनीति

राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान से उद्धव ठाकरे कैंप नाराज है। इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी को बीते कल की बात कहकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब महाराष्ट्र की राजनीति इन्हीं दो बयानों के चारों तरफ चक्कर लगाती नजर...

झारखंड

38 | फंदे में सरकार

खिरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दरवाजे पहुंच ही गया। उनके खिलाफ खुद के नाम खनन पट्टे का नवीकरण कर पद के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में चुनाव आयोग की राय दो महीने से राज्यपाल के पास...

6-7	अंदर की बात
41	महिला जगत
42	अध्यात्म
43	कहानी
44	खेल
45	फिल्म
46	व्यंग्य

प्यार का ये कैसा सिला...?

शायर ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर है...

नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तिरी हरगिज
गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो

ये पंक्तियां हाल ही में प्यार और फिर शादी या लिवइन के बाद हो रही हत्याओं पर सटीक बैठती हैं। पुरुष हो या महिला प्यार में वे दुनिया-जहान को दरकिनार कर प्रेमी या प्रेमिका के साथ रहने की कसमें खाते हैं, लेकिन इन कसमों का परिणाम अभी हाल ही में जघन्य हत्याओं के रूप में सामने आया है। देश की राजधानी दिल्ली में मुंबई की श्रद्धा वालकर की उसके लिवइन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला द्वारा खौफनाक तरीके से हत्या ने अनेक गंभीर प्रश्नों को खड़ा कर दिया है। देशभर में लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस आक्रोश को संकीर्णता करार करने वाले यह तर्क दे सकते हैं कि ऐसी घटना स्वधर्मी से प्रेम संबंध रखने पर भी तो घटित हो रही हैं। प्रश्न यह है कि बीते एक दशक में ऐसी लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी क्यों हुई है, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लड़कों से विवाह किया और फिर जो या तो मारी गईं या मतांतरण के लिए विवश हुईं अथवा जिनकी जिंदगी तबाह हो गई? प्रेम और विवाह एक नितांत निजी मामला है। इस पर किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है, परंतु उस स्थिति में नहीं जब उसका अप्रत्यक्ष रूप से संबंध मतांतरण से हो। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि **प्रेम जाति और समुदाय** के बंधन को स्वीकार नहीं करता या फिर लड़कियां भावुक, कोमल और संवेदनशील होती हैं और सहजता से प्रेम बंधन के प्रति विश्वास रखकर अन्य जाति-पंथ के युवा से विवाह करने से नहीं हिचकतीं। अगर यह सत्य है तो फिर यह भाव और समर्पण मुस्लिम समुदाय की लड़कियों में अधिकांशतः विलुप्त क्यों मिलता है? जिस प्रेम के बलबूते लड़कियां इस विश्वास के साथ अंतर-धार्मिक विवाह करती हैं कि विवाह के बाद उनकी धार्मिक आस्था का संरक्षण उनके जीवन साथी द्वारा किया जाएगा, वह विश्वास अधिकांश मामलों में ढह क्यों जाता है? यह किसी से छिपा नहीं कि देश के तमाम थानों में विवाह के बाद मतांतरण के लिए दबाव के मामले दर्ज हैं। हाल में उच्चतम न्यायालय ने मतांतरण को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि जबरन या छल-कपट से मतांतरण रोकने के लिए केंद्र सरकार को प्रयास करने चाहिए। जबरन मतांतरण से कहीं अधिक घातक भावनात्मक दबाव बनाकर मतांतरण कराना है। अमूमन देखने में आता है कि सनातन संस्कृति से संबंध रखने वाली लड़की जब अन्य समुदाय-संस्कृति से जुड़े लड़के से विवाह करती है तो उसके अपने रक्त संबंधी उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। इससे पति और ससुराल पक्ष के लिए उस पर उनकी इच्छानुसार जीवन पद्धति अपनाने का दबाव बनाना आसान हो जाता है। आखिर अंतर धार्मिक विवाह की उन्नायक बहुसंख्यक समाज की लड़कियां ही क्यों बनती हैं? इसके पीछे जो कारण दृष्टिगोचर होता है, वह स्पष्टता सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास की खोखली होती जड़ों की ओर इशारा कर रही है। आधुनिक सोच के नाम पर सनातन संस्कृति की आस्था, विश्वास और मूल्य न केवल पिछड़ेपन का प्रतीक समझे जाने लगे हैं, बल्कि अभिजात वर्ग की पहचान भी। नतीजतन मध्यमवर्गीय भारतीय परिवार इस परिपाटी को अपनाकर स्वयं को अभिजात वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित करने को आतुर दिखाई दे रहे हैं और अंततोगत्वा एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, जो दिग्भ्रमित है और जिसके लिए प्रेम देह आकर्षण से अधिक कुछ भी नहीं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 5, पृष्ठ-48, 1 से 15 दिसंबर, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

महंगाई का दंश

महंगाई की मार से लोगों का हाल बेहाल है। जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ऐसा लगता है जैसे किसी को जनता की चिंता नहीं है। जबकि आलम यह है कि आटे, दाल से लेकर तेल-मसाले तक महंगे हो गए हैं। जिससे आम जनता परेशान है।

● **त्रिलोक वर्मा,** शिवपुरी

सड़कों की राजनीति

इस समय भोपाल सहित सभी जिलों में सड़कों की स्थिति खराब है। मप्र में सड़क हमेशा से चुनावी मुद्दा रही है। भाजपा हर चुनाव में 2003 के पूर्व सड़कों की खराब स्थिति का हवाला देकर कांग्रेस को घेरती रही है। इस बार कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने की तैयारी की है।

● **जितेंद्र राठौर,** ग्वालियर (म.प्र.)

बिजली चोरी से चपत

मप्र में राजधानी भोपाल हो या फिर प्रदेश का दूर दराज का इलाका, बिजली चोरी निर्बाध रूप से हो रही है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि मप्र की तीनों बिजली वितरण कंपनियां बिजली चोरी रोकने और बिलों की वसूली में उप्र, बिहार, छत्तीसगढ़ से भी बहुत पीछे हैं।

● **राम सिंह,** आगर (म.प्र.)

भाजपा-कांग्रेस की तैयारियां तेज

मप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसके लिए भाजपा लगातार रणनीतिक मोर्चे पर काम कर रही है। पार्टी मैदानी सक्रियता के साथ ही टिकट वितरण के लिए फॉर्मूलों पर भी चिंतन-मनन कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा दी है। इसके अलावा अन्य पार्टियों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा के 41 मंत्री चुनाव हार गए थे। इनमें मप्र के 13, राजस्थान के 20 और छत्तीसगढ़ के 8 मंत्रियों ने अपनी सीट गंवाई थी। इसलिए 2023 के चुनाव में भाजपा कोई रिस्क नहीं लेगी।

● **रानी राजपूत,** इंदौर (म.प्र.)

किसान की आत्मनिर्भरता

वर्तमान में करीब 9 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें 7 हजार करोड़ की परियोजनाएं तो वर्ष-2021 के दौरान ही शुरू की गई हैं। इसके अलावा आगामी सालों में करीब 8 हजार करोड़ की परियोजनाएं और शुरू होंगी। सिंचाई क्षमता में तेजी से बढ़ोत्तरी होने पर राज्य सरकार को दोहरा फायदा है। एक ओर इससे सिंचाई बढ़ने पर किसान की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, दूसरी ओर नर्मदा जल के वर्ष-2034 तक उपयोग करने के डैडलाइन में भी फायदा होगा।

● **प्रीतम दांगी,** सीहोर (म.प्र.)

विपक्ष की दरकार

देश में इस समय जिस प्रकार के हालात हैं, उससे तो यही लगता है कि देश को इस समय एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। देश की बढ़ती महंगाई से लेकर अन्य मुद्दों को उठाकर जनता के सामने रखकर विपक्षी पार्टियों को एकसाथ आना चाहिए। देश में सशक्त विपक्ष की दरकार है, जो भाजपा को दमदार चुनौती दे सके। लेकिन जनता का दुर्भाग्य है कि विपक्ष खंड-खंड बंटा हुआ है। सब के सब महत्वकांक्षी हैं, जो प्रधानमंत्री पद के मंसूबे पाले हुए हैं। आम जनता को विपक्षी दलों से ही आशा है। विपक्ष को इस बारे में सोचना चाहिए।

● **रवि माथुर,** अलीराजपुर

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

पिता के पैमाने पर

उप्र के तीन उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए कड़ी चुनौती हैं। रामपुर और खतौली की विधानसभा सीटों का उपचुनाव पिछले विजेताओं मोहम्मद आजम खान और विक्रम सैनी के अयोग्य घोषित हो जाने और मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण हो रहा है। मैनपुरी और रामपुर सीटें सपा के पास थी जबकि खतौली भाजपा के। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल को उतारा है तो रामपुर में आजम खान की पसंद के असीम रजा खान को। रामपुर में असीम रजा का भाजपा के आकाश सक्सेना से मुकाबला है तो मैनपुरी में डिंपल का भाजपा के रघुराज शाक्य से। जो पहले सपा में ही थे। खतौली सीट अखिलेश ने सहयोगी रालोद को दी है। जिसने पूर्व विधायक बाहुबली मदन भैया को तो भाजपा ने निवर्तमान विधायक की पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है। गनीमत है कि अखिलेश ने नाराज चाचा शिवपाल की मनुहार कर ली। उपचुनाव में इससे पहले आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें भाजपा ने सपा से छीन ली थीं। रामपुर विधानसभा सीट पर भी आह्यजम खान का मनोबल कमजोर दिख रहा है। अब अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पसंद भी बता दी कन्नौज।

खामोशी के मायने

भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे खामोश हैं। कहने को भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठहरी। पर राष्ट्रीय राजनीति में न उनकी दिलचस्पी है और न कोई पूछ। पार्टी आलाकमान ने एक तरह से हाशिए पर पहुंचा रखा है राजस्थान की सियासत में दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी महारानी को। उन्हें अपनी उपेक्षा का तो दर्द है ही अपने बेटे दुष्यंत को भी केंद्र में मंत्रिपद नहीं दिए जाने की शिकायत भी होगी। पार्टी के सूबेदार सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से छत्तीस का आंकड़ा है उनका। पूनिया उन्हें पार्टी कार्यक्रमों में बुलाते ही नहीं। उल्टे आलाकमान से उनकी शिकायत जरूर करते हैं कि वे समानांतर संगठन चलाती हैं और गुटबाजी को बढ़ावा देती हैं। वसुंधरा अपनी तरफ से आलाकमान की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और चाहती हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। लेकिन, सूबे के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह कई बार कह चुके हैं कि चेहरा पेश किए बिना लड़ेगी पार्टी। हद तो तब हो गई जब हिमाचल और गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की पार्टी की सूची से भी महारानी का नाम गायब दिखा। जबकि सूबेदार सतीश पूनिया गुजरात में जुटे हैं।

खत्म होती प्रियंका की पावर

मुकाबला चाहे खेल के मैदान का हो या चुनाव के मैदान का, जो खिलाड़ी होता है वह पूरी ताकत लगाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है। वह अपनी ताकत बचाकर रखने में विश्वास करती है। पता नहीं कांग्रेस नेताओं को लगता है कि बचाकर रखने से ताकत बढ़ेगी। चुनाव के मैदान में ताकत के अधिकतम इस्तेमाल से ताकत बढ़ती है। इस बात को कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर सीखना चाहिए। वे हर चुनाव में ऐसी मेहनत करते हैं, जैसे इस चुनाव पर उनकी किस्मत दांव पर लगी है। दर्जनों रैलियां, सभाएं, रोड-शो, चुनाव की रणनीति की बैठकें, नेताओं से बातचीत जैसे सारे काम वे प्रधानमंत्री रहते हुए करते हैं। इसके उलट कांग्रेस हर चुनाव आधे-अधूरे तरीके से लड़ती है। मिसाल के तौर पर अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा की चार दिन रैलियां हुईं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी यात्रा रोककर गुजरात के प्रचार में जा रहे थे तो क्या वे एक दिन हिमाचल नहीं जा सकते थे? सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं है लेकिन वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने कर्नाटक गई थीं। मगर वे एक भी सभा करने हिमाचल नहीं गईं और न उन्होंने हिमाचल के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी या अपील जारी की।

महाविकास अघाड़ी में दरार

इस वक्त शिवसेना आंतरिक कलह से परेशान है। पार्टी के अस्तित्व पर पहले से ही खतरा है। भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट लगातार उद्धव ठाकरे गुट को हिंदू विरोधी बताने में जुटे हैं। ऐसी स्थिति में चर्चा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी लोग वीर सावरकर को आजादी का नायक मानते हैं। ऐसे में राहुल के बयान से कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में दरार पड़ने के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिवसेना से सांसद संजय राउत भी इसका जिक्र कर चुके हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। अभी शिवसेना उद्धव गुट आंतरिक कलह से परेशान है। ऐसे में वह गठबंधन तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। वह किसी तरह इस बयान से बचकर निकलने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर ज्यादा टिप्पणी न करते हुए वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग करके गेंद भाजपा के पाले में ही कर दी है।

उमर को मिलेगी कमान!

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब यह वक्त नई पीढ़ी को कमान सौंपने का है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है और 85 वर्षीय अब्दुल्ला पार्टी संरक्षक की भूमिका में आगे अपने राजनीतिक कैरियर को जारी रख सकते हैं। दरअसल एक प्रोग्राम में फारूक ने कहा, 'मैं अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके साथ ही उन्होंने अगली पीढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि 'अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी इस जिम्मेदारी को संभाले।' अब्दुल्ला ने अपने पद से हटने की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि जल्द ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। लोकतंत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी सदस्य इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।

खेल-खेल में काम का निपटारा

मप्र की तरह यहां के ब्यूरोक्रेट्स भी अजब-गजब हैं। इनके किस्से प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में अक्सर सुने जाते हैं। इन दिनों 1990 बैच के एक वरिष्ठ आईएएस काफी चर्चा में हैं। इसकी वजह यह है कि साहब खेल-खेल में ही काम का भी निपटारा करते रहते हैं। साहब टेनिस खेलने के काफी शौकीन हैं। पौ फटते ही साहब टेनिस खेलने के लिए राजधानी के एक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। खेल के दौरान जब उन्हें ब्रेक मिलता है तो वे मोबाइल फोन से जिलों का काम निपटाने में जुट जाते हैं। उनके साथी खिलाड़ी कोर्ट पर पसीना बहाते हैं, उसी दौरान साहब अफसरों को हड़काते रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब की कोशिश रहती है कि मंत्रालय में बैठकर काम करने की बजाय सुबह-सुबह खेल के दौरान मिले ब्रेक में ही शासकीय काम का निपटारा कर लिया जाए। इसलिए वे जिलों में पदस्थ अपने अधीनस्थ अधिकारियों को फोन लगाकर दिशा-निर्देशों का फीडबैक लेते रहते हैं। इस दौरान किसी अधिकारी ने तनिक भी ना-नुकुर की तो साहब उस पर पिल पड़ते हैं। यह एक तरह से साहब की दिनचर्या का अंग बन गया है। साहब खेल-खेल में अपने शासकीय काम निपटा लेते हैं और वहीं से घर चले जाते हैं। गौरतलब है कि साहब के पास एक बड़े और महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी है। साहब हाल ही में अपने एक बयान के कारण विवादों में भी रह चुके हैं।

चर्चा में साहब का मकान

राजधानी में इन दिनों एक अधिकारी का मकान चर्चा में है। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इस मकान की खूब चर्चा हो रही है। इसकी वजह है मकान की भव्यता। दरअसल, यह मकान ऐसी जगह बनाया जा रहा है, जहां पर भूखंड की कीमत करोड़ों की होगी। अनुमानत: मकान की कीमत 2.5-3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर साहब पर लक्ष्मीजी कैसे इतनी मेहरबान हो गई हैं कि उन्होंने करोड़ों का मकान बनवाना शुरू कर दिया। यहां बता दें कि जिन साहब का यह मकान है, वे प्रमुख सचिव हैं। साहब जहां पदस्थ हैं, उसकी निगहबानी प्रदेश के 230 माननीय करते हैं। ऐसे में चर्चा यह है कि साहब को इतनी आमदनी कहां से हो गई कि उन्होंने इतना भव्य और आलीशान मकान बनाना शुरू कर दिया है। वैसे यहां बता दें कि साहब रसूखदार परिवार से संबंध रखते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि यह मकान साहब की अपनी निजी कमाई से बन रहा है। सूत्रों का कहना है कि साहब के कई करीबी इसकी पड़ताल में जुट गए हैं कि साहब ने इस मकान को बनाने के लिए लक्ष्मीजी की व्यवस्था कहां से की है।

रकम ले गए... साहब को छोड़ गए

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों आयकर विभाग द्वारा हाल ही में की गई एक छापामार कार्रवाई काफी चर्चा में है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने प्रदेश में तेजी से उभरते एक व्यावसायिक घराने के ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापामार कार्रवाई में एक ऐसी डायरी आयकर विभाग वालों के हाथ लगी है कि उसमें कई लोगों की काली कमाई का राज छिपा हुआ है। इन्हीं में से एक ने व्यावसायिक घराने के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट में अपनी काली कमाई का निवेश किया है। उस निवेश का पूरा विवरण यह है कि उन्होंने 60 फीसदी राशि ब्लैक में और 40 फीसदी राशि रिकॉर्ड में दी है। बताया जाता है कि उक्त डायरी के आधार पर पुलिस ने परिवहन विभाग के एक आरटीआई के घर छापा मारा। बताया जाता है कि छापामार कार्रवाई में पुलिस को करोड़ों रुपए की नगदी मिली। करोड़ों हाथ आने के बाद पुलिस ने उक्त अधिकारी के साथ मोल-भाव किया और पूरी रकम लेकर उन्हें छोड़ दिया। बताया जाता है कि अगर उक्त अधिकारी के साथ गहनता से पूछताछ होती तो प्रदेश के सबसे कमाऊ विभाग में चल रहे बड़े घालमेल का पर्दाफाश हो सकता था। लेकिन काली कमाई के घालमेल में मिलीभगत कर बड़े घपले-घोटालों पर पर्दा डाल दिया गया। बताया जाता है कि जिस व्यावसायिक घराने पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की थी, उसके कई प्रोजेक्ट में प्रदेश के नेताओं और अधिकारियों का निवेश है।

बिना लाइसेंस छलक रहा जाम

राजधानी में एक तरफ पुलिस प्रशासन ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों की नाक में दम कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक पूर्व माननीय के होटल में बिना लाइसेंस के जाम छलकाया जा रहा है। माननीय का रसूख ऐसा है कि आबकारी और पुलिस विभाग को जानकारी होते हुए भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने नहीं हो रही है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ पार्टी के जिस पूर्व माननीय के जिस होटल में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही है, वह शहर की सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी के पास स्थित है। बताया जाता है कि माननीय के इस रेस्टोरेंट में न तो शराब पीने की व्यवस्था है और न ही इसके लिए कोई लाइसेंस लिया गया है, फिर भी यहां शराब परोसी जा रही है। यहां शराब पीने के लिए शहर के रसूखदार भी पहुंचते हैं। रहवासी क्षेत्र में स्थित इस रेस्टोरेंट में परोसी जा रही शराब के खिलाफ स्थानीय लोग आवाज उठाने से भी घबराते हैं। उनका कहना है कि जब सैय्या भए कोतवाल तो डर काहेका की तर्ज पर माननीय के रसूख के आगे प्रशासन पस्त पड़ा हुआ है। ऐसे में हम अपना मुंह खोलकर शासन-प्रशासन से पंगा क्यों लें।

आपस में कर ली हिस्सेबांटी

प्रदेश में सत्तापक्ष के नेताओं में समन्वय ऐसा है कि उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। हर कोई प्रदेश के नेताओं के समन्वय का बखान करता है। यह समन्वय इस बार विंध्य क्षेत्र के एक विश्वविद्यालय में की गई प्रोफेसरों की भर्ती में भी देखा गया। सूत्रों का कहना है कि इस विश्वविद्यालय में हुई प्रोफेसरों की भर्ती के लिए प्रदेशभर से हजारों योग्य अभ्यार्थी कतार में थे। लेकिन विंध्य के नेताओं ने आपस में हिस्सेबांटी कर ली। यानी नेताओं ने अपने-अपने चहेते लोगों को नौकरी दिलवा दी। नेताओं की इस हिस्सेबांटी की प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में खूब चर्चा हो रही है। आलम यह है कि इसको लेकर जमकर बवाल भी मचा है। गौरतलब है कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया हर बेरोजगार को रोजगार देने के अभियान में जुटे हुए हैं। इसके लिए 1 लाख पदों के लिए नौकरियां निकाली जानी हैं। इससे बेरोजगार युवाओं में आशा की किरण देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ निकल रही सरकारी नौकरियों में किस तरह की बंदरबांट हो रही है, उसका उदाहरण विंध्य में देखने को मिला है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के लिए किया है वह उनकी मानसिकता ही नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की मानसिकता का परिणाम है।

● **राजनाथ सिंह**

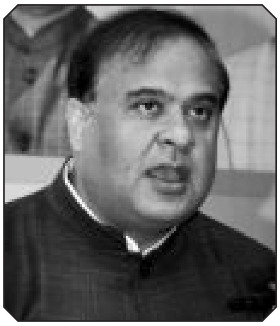

हिंदू शांतिप्रिय होते हैं और वे जिहाद में विश्वास नहीं करते हैं। 2002 के बाद से गुजरात सरकार ने राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कई कार्रवाई की। अब राज्य में स्थायी शांति है। इस तरह की कार्रवाई हर राज्य में होनी चाहिए, ताकि गुजरात जैसी शांति कायम रहे। कुछ लोग इस तरह की कार्रवाई को धार्मिक रूप देना चाहते हैं, जो गलत है।

● **हिमंत बिसवा सरमा**

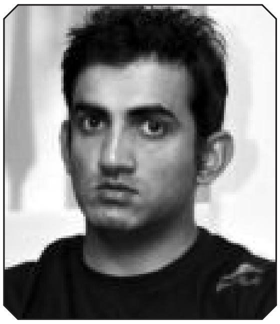

भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय जिस तरह प्रयोग हो रहे हैं यह ठीक नहीं है। भारतीय टीम आज विश्व की सबसे मजबूत टीम है और हमारे पास प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह फार्म में होने के बावजूद खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाया जा रहा है, उससे उनके मनोबल में गिरावट आ रही है, जिसका असर टीम पर पड़ रहा है।

● **गौतम गंभीर**

रूस-यूक्रेन युद्ध दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। मैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस मसले पर बात करना चाहता हूं। मेरी कोशिश है कि दोनों देशों के बीच शांति का माहौल निर्मित हो, ताकि जनहानि रोकी जा सके।

● **जो बाइडेन**

आज जिन्हें लोग सुपरस्टार मान रहे हैं, उस सलमान खान ने मेरे साथ फिजिकल एब्यूज किया है। उन सभी फीमेल एक्ट्रेस को भी शर्म आनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले आदमी का सपोर्ट करती हैं। उन्हें सपोर्ट करने वाले मेल एक्टर्स पर भी लानत है। अब मैं आर-पार की लड़ाई में उतर गई हूं। अभी बहुत कुछ होगा। मेरे शो को इंडिया में बैन करा दिया है और वकीलों से मुझे धमकाया है। लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। अब मैं भी उन्हीं के नक्शेकदम पर चलते हुए यह दिखाऊंगी कि एक लड़की अगर चाह ले तो वह क्या कर सकती है।

● **सोमी अली**

वाक्‌युद्ध

भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्य में कामयाब हो रही है। यात्रा के दौरान लोग मुझसे मिल रहे हैं और यह बता रहे हैं कि वे किस तरह नफरत की राजनीति के शिकार हो रहे हैं। देश में किस तरह महंगाई और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश के पीएम अपने आप में मस्त हैं।

● **राहुल गांधी**

राहुल गांधी ने यह मान लिया है कि वे देश को नहीं समझते हैं। भारत को समझने के लिए एक जन्म कम पड़ेगा। इसलिए वे पहले भारत को ठीक से समझ लें उसके बाद प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएं। उनकी यात्रा में जनता नहीं, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे हैं। यह बात पूरे देश की समझ में आ रही है, राहुल के नहीं।

● **स्मृति ईरानी**

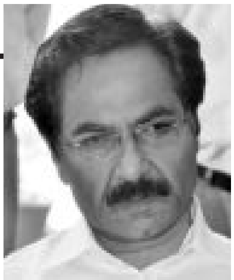

अब 6 माह की पारी

जैसा कि अनुमान था मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की 6 माह की सेवावृद्धि हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद भी बैंस को और सेवावृद्धि दी जाएगी। वह सेवावृद्धि दो चरणों में 6-6 माह की होगी। दरअसल, सरकार की मंशा है कि इकबाल सिंह बैंस के मुख्य सचिव रहते ही 2023 का विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराया जाए। सरकार बैंस के प्रशासनिक अनुभव का फायदा उठाना चाहती है।

मप्र के मुख्य सचिव को लेकर अटकलें खत्म हो गई हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ही अगले 6 माह तक प्रदेश के मुख्य सचिव बने रहेंगे। बैंस 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे, जिसके बाद नए सीएस को लेकर अटकलों का दौर चल रहा था। उनके रिटायरमेंट के दिन ही केंद्र सरकार ने 6 माह के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस 6 माह के कार्यकाल के बाद उनको 6-6 माह के दो एक्सटेंशन और दिए जा सकते हैं। बताया जाता है कि बैंस की सेवावृद्धि में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बताया जाता है कि तोमर ने बैंस की सेवावृद्धि के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया था। उसके बाद उन्हें यह एक्सटेंशन मिला है।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस अब 30 मई तक पद पर बने रहेंगे। बता दें यह पहली बार हुआ है कि मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति के एक दिन तक असमंजस बना रहा। इससे पहले 15 दिन पहले ही नए सीएस के नाम के आदेश हो जाते थे या फिर मौजूदा सीएस के बने रहने का ऐलान कर दिया जाता था। नए सीएस के नाम को लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक अटकलें लगती रहीं। इसमें 1989 बैंच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन का नाम भी चर्चा में आया था। मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते थे कि इकबाल सिंह बैंस ही मुख्य सचिव रहें, ताकि जो कार्ययोजना तैयार की गई है, उस पर तेजी से अमल हो सके। अगले माह संभाग स्तर पर विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरण के कार्यक्रम होने हैं। 8, 9 और 10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुनियाभर से 3 हजार से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। आयोजन के लिए गठित विभिन्न समितियों के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं। वहीं, 11 और 12 जनवरी को इंदौर में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है। चुनाव के पूर्व यह शिवराज सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निवेशकों का भरोसा है और वे प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। फरवरी-मार्च 2023 में बजट प्रस्तुत होगा, जो पूरी तरह से चुनावी होगा। इसमें सभी वर्गों को साधने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी होने हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इकबाल सिंह बैंस पर ही भरोसा जताया और केंद्र सरकार से 6 माह की सेवावृद्धि करा ली।

● कुमार राजेंद्र

बिक्री बढ़ी... आमदनी नहीं

प्रदेश में सरकारी राजस्व का बड़ा माध्यम आबकारी विभाग है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवैध शराब की बिक्री पर रोक और अधिक राजस्व के लिए शराब की कीमतों में कमी कर दी थी। सरकार की इस नीति से प्रदेश में शराब पीने वालों की संख्या 33 फीसदी पहुंच गई है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी है। उधर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त विभाग ने आबकारी विभाग को 20 फीसदी राजस्व बढ़ाने का टारगेट दिया है। अब आबकारी विभाग के सामने राजस्व बढ़ाने के लिए एक ही माध्यम है, वह है शराब की कीमतों में बढ़ोत्तरी। माना जा रहा है कि आगामी वित्त वर्ष में आबकारी विभाग नई शराब नीति में शराब की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। माना जा रहा है कि इससे राजस्व में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

खराब सड़कों पर साहब का फोकस

प्रदेश में इस बार की मानसून से करीब 8,000 किमी सड़कें खराब हो गई हैं। खराब सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। अब लोक निर्माण विभाग में नए प्रमुख सचिव पदस्थ हुए हैं। बताया जाता है कि पदस्थापना के बाद से ही साहब ने खराब सड़कों की पड़ताल शुरू कर दी है और अभी तक करीब 2,000 किमी की सड़कों को चिन्हित किया जा चुका है। बताया जाता है कि साहब ने इंजीनियरों को इन चिन्हित सड़कों की मरम्मत और निर्माण का प्रपोजल तैयार करने का निर्देश दे दिया है। बताया जाता है कि जल्द ही खराब हुई सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए सरकार की प्राथमिकता में सड़कें हैं।

पुलिस में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण कहां?

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। वहीं वे हर मंच से महिला संरक्षण, आरक्षण और सम्मान की बात करते हैं। लेकिन अगर पुलिस विभाग में देखा जाए तो महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिशत आरक्षण कहीं नजर नहीं आता है। पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या तो कम है ही उनकी महत्वपूर्ण पदों पर भागीदारी भी कम है। प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र 1 जिले की आईजी महिला (दीपिका सूरी) हैं। वहीं सिमाला प्रसाद और मोनिका शुक्ला के रूप में दो एसपी हैं। जबकि प्रदेश में कई महिला आईपीएस इन पदों के लिए योग्य हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसी तरह चित्रा एन, कृष्णावेनी देसवातु, रूचिका जैन को डीआईजी बनाया गया है। जबकि अन्य महिला आईपीएस भी महत्वपूर्ण पदों के लिए पात्र हैं, लेकिन सरकार की महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने में रूचि नहीं दिखाई दे रही है।

मप्र देर से ही सही अपने गठन के समय बुझी संभावनाओं को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खासतौर से पिछले डेढ़ दशक का अरसा इस बात का गवाह रहा है कि मप्र विकास के पथ पर अब आगे ही आगे है। सुविचारित सोच, सुचिंतित नीतियों, फैसलों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रेरणादायी नेतृत्व ने सरकार की नीति और नीयत के फर्क को मिटाकर सच्चे अर्थों में प्रदेश के विकास और लोगों की बेहतरी के कामों की तस्वीर में नए रंग भर दिए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सेवा, समर्पण, सक्रियता के कारण मप्र ने पिछले सालों में विकास के जो अध्याय लिखे हैं उससे कई राज्य सीख ले रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि प्रदेश की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर 19.7 प्रतिशत तक पहुंच गई जो देश में सर्वाधिक है। सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ है। पूंजीगत व्यय भी 48 हजार करोड़ हो गया है। प्रदेश सरकार ने स्थायी विकास और आत्मनिर्भर मप्र की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। करीब 20 साल में प्रति व्यक्ति आय 13 हजार से बढ़कर अब 1 लाख 23 हजार रुपए हो गई है। औद्योगिक निवेश, मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ाना है। रोजगार मेलों के जरिए अभी तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 10 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया गया है। बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास, पानी, बिजली और सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 33 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। माफिया से 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। इस पर सुराज कॉलोनी बनाकर गरीबों को आवास दिलाए जाएंगे।

शिव'राज' का संकल्प है कि आत्मनिर्भर मप्र की थीम की मदद से मप्र 2023 के अंत तक देश का सबसे विकसित राज्य बनेगा। इसमें सुदृढ़ अधोसंरचना के साथ औद्योगिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश ने वर्ष 2003 के बाद अधोसंरचना के साथ-साथ कृषि, सिंचाई, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं लेकिन विकास एक सतत् प्रक्रिया है। नई तकनीकों के ईजाद हो जाने पर संसाधनों को बेहतर बनाने का क्रम लगातार जारी रहता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण देश को दिया तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मप्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मप्र की रूपरेखा तैयार की गई और उस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। वर्ष 2023 तक मप्र में सभी लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जाएगी। औद्योगिक विकास गतिविधियों के साथ-साथ औद्योगिक संस्थाओं को सामाजिक क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। नागरिकों में भी अपने सामाजिक दायित्व बोध जगाने की आवश्यकता है। तभी हम आत्मनिर्भर मप्र से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

आज मप्र मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में न केवल अपनी बल्कि भारत सरकार की भी लोक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में अग्रणी बनकर उभरा है। मप्र की इन्हीं उपलब्धियों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मप्र को भारत की अर्थव्यवस्था की ड्राइविंग फोर्स बनने की पूरी क्षमता वाला बताया है। भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्र अग्रणी राज्य है। यहां स्वामित्व योजना, एनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जल जीवन मिशन, कृषि अधोसंरचना निधि, नगरीय विकास, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मनरेगा, स्वसहायता समूहों का सशक्तीकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, ट्रांसजेंडर पहचान-पत्र, दिव्यांगजन पहचान-पत्र, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सौर ऊर्जा, कौशल विकास, ईज ऑफ डूईंग

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मप्र आज देश में तेजी से विकास कर रहा है। विकासशील राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए शिवराज सरकार ने ऐसा प्लान बनाया है कि 2023 में मप्र विकास प्रदेश बन जाएगा। इसकी झलक अभी से दिखने लगी है। शिव'राज' का ही प्रयास है कि आज मप्र चौतरफा विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

शिव'राज' का मप्र के विकास पर फोकस

डिफाल्टर किसानों का ब्याज भरेगी सरकार

कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में कर्ज माफी योजना के कारण जो किसान डिफाल्टर हो गए थे, उनके ऋण का ब्याज शिवराज सरकार भरेगी। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित प्रदर्शन स्थल पर जाकर किसानों के बीच घोषणा कर दी। मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय प्रांगण में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की सहमति से ही उसकी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। किसानों की मांगों का निपटारा करते हुए उन्होंने कहा कि किसान पम्प योजना का अनुदान अगले बजट में आ जाएगा। गन्ना किसानों का बकाया मिल मालिकों से बात कर वापस कराएंगे। जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलवाएंगे।

बिजनेस में मप्र सभी राज्यों से आगे है।

मप्र में पेसा कानून लागू कर दिया गया है। पेसा कानून लागू कर चुकी सरकार अब जनजातीय बहुल प्रदेश के 89 विकासखंडों में मास्टर ट्रेनर भेजकर कानून के फायदे बता रही है। वहीं मास्टर ट्रेनर गांवों में जाकर बताएंगे कि पेसा कानून से उन्हें क्या अधिकार मिले हैं और इससे उनका जीवन कितना आसान होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जिलों में जाकर पेसा एक्ट जागरूकता और ग्रामसभा कार्यक्रम में लोगों को एक्ट की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान उनका कहना है कि अब प्रदेश की सरकार भोपाल से नहीं बल्कि गांव की चौपाल से चलेगी। अक्ल का चक्का नेता-अफसर के पास ही नहीं गरीब के पास भी है। इसलिए अब वह वनोपज, तेंदुपत्ता खुद बेच सकेगा। यहां तक कि ग्रामसभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकेगा। अब अनुसूचित गांवों में जनता के बीच पटवारी और वन विभाग के अफसर जाएंगे। हर साल खसरा नकल ग्रामीणों के सामने रखकर बताएंगे कि यह जमीन किसकी है। ताकि ऐसा न हो कि धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई हो और धन्ना को मालूम ही न हो। अब सरकारी निर्माण कामों में आदिवासी क्षेत्रों की जमीन उनकी बगैर अनुमति के नहीं ली जाएगी। मालिक के अलावा ग्रामसभा की अनुमति भी ली जाएगी, तभी जमीन का अधिग्रहण हो सकेगा। कोई बिना मर्जी या जबरदस्ती के जमीन नहीं हड़प पाएगा। इसके अलावा धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने दिया जाएगा। क्योंकि आदिवासी बहन-बेटियों से शादी करवाकर जमीन उनके नाम करवा ली जाती है। आदिवासी की जमीन पर खदान की अनुमति के लिए ग्रामसभा का अप्रूवल लगेगा।

आदिवासी ग्रामों में बने तालाबों में मछली पालन आदि का जिम्मा ग्रामसभा के पास रहेगा। उसकी परमिशन भी ग्रामसभा देगी, न कि भोपाल से मिलेगी। इसके अलावा 100 एकड़ जमीन तक के तालाबों से सिंचाई व्यवस्था का जिम्मा भी ग्रामसभा के पास रहेगा। जो लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं, उन्हीं ग्रामसभा को जानकारी देना होगी। ताकि, बाहर के जिले या प्रदेश में उनके साथ अनहोनी हो तो मदद की जा सके। कोई भी व्यक्ति उन्हें बंधक बनाकर काम नहीं करवा सकेगा। अभी मनरेगा में भ्रष्टाचार होता है। 100 मजदूरों के नाम से राशि निकाली जाती है और काम सिर्फ 50 लोग ही कर रहे होते हैं। ऐसे में मस्टर रोल यानी हाजिरी रजिस्टर को ग्रामसभा में रखकर जनता को बताना पड़ेगी। अनुसूचित गांवों में शराब और भांग की दुकान के लिए ग्रामसभा तय करेगी कि दुकान खुलेगी या नहीं। कई किसान लोग साहूकार से कर्ज लेते हैं, इसके लिए साहूकार के पास लाइसेंस होना चाहिए। ब्याज की दर सीमित होना चाहिए। गांवों में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी, जो छोटे विवादों को सुलझाएगी ताकि मामला पुलिस थाना तक नहीं पहुंचे। दरअसल, साल 2018 के चुनाव से सबक लेते हुए भाजपा आदिवासियों को साधने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रदेश में 23 फीसदी से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। 47 सीटें जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जनजातीय वर्ग का वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता रहा है। साल 2018 के चुनावों में भाजपा को आदिवासी वोटर वाली सीटों पर शिकस्त मिली थी। पेसा एक्ट के जरिए अब भाजपा ने इसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। आदिवासी वोट बैंक के जरिए ही सत्ता तक पहुंचना आसान माना जाता रहा है। पेसा एक्ट आदिवासी वोट बैंक के लिहाज से सरकार के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है।

प्रदेश में सरकार अगस्त 2023 तक 1.12 लाख सरकारी खाली पदों पर भर्ती करेगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगने के काफी पहले भर्ती करने की तैयारी है। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है। रोजगार सरकारी क्षेत्र में हो या निजी में, योग्यतानुसार कार्य मिल जाए, यह जरूरी है। पर्याप्त अमले से संस्थानों, विभागों की कार्य-प्रणाली सहज, आसान होती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रतिमाह रोजगार दिवस के फलस्वरूप बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। औद्योगिक संस्थानों में स्थानीय युवाओं की सेवाएं लेने को महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने दृढ़ संकल्पित है। इसी की पूर्ति के लिए अभियान संचालित कर शासकीय विभागों में रिक्त पद भरे जा रहे हैं। जीएडी एसीएस विनोद कुमार ने बताया कि 15 अगस्त से शुरू हुआ भर्ती अभियान 12 महीने चलेगा। अगले अगस्त तक 1 लाख 12 हजार 724 खाली पद भरेंगे। नवंबर में लगभग 60 हजार पद भरने प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह विभाग में ही 6 हजार आरक्षक पदों पर नियुक्ति देने की पहल हुई है। प्रयास यह है कि किसी एक दिन सभी को समारोह पूर्वक नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों के पदों को भरने की कार्रवाई के साथ ही राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में भी पदों की पूर्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है।

● कुमार विनोद

समय सीमा में पूरा होगा टारगेट

आत्मनिर्भर मप्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों, अधिकारियों को एक ही मंत्र दिया है कि टारगेट को समयसीमा में पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और इसमें मप्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रखना है। आत्मनिर्भर मप्र देश की आत्मनिर्भरता में बड़ा सहयोग देगा। उन्होंने मंत्री, अधिकारियों से कहा कि हमारी योजनाओं का खाका ऐसा हो जो जनोपयोगी और आसानी से सुलभ होने वाला रहे। जहां जरूरत हो, वहां नियमों में बदलाव भी जनहित के हिसाब से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए वसूली पर फोकस कराएं। अधिकारी इस बात का ध्यान भी रखें कि किस योजना में केंद्र से कितना पैसा आया है, उसका कितना उपयोग हुआ है। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भेजकर केंद्र से योजनाओं पर अमल के लिए आगे भी राशि लेने की तैयारी रखनी है। जहां जरूरत है वहां विभाग के मंत्री या फिर उनके जानकारी में बात सामने लाकर इस काम को पूरा करना है। केंद्र की योजनाओं को पूरा करने के मामले में भी अधिकारियों से लगातार मॉनीटरिंग करने के लिए कहा गया।

संघ भी आया चुनावी मोड में

मप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के साथ ही आरएसएस भी चुनावी मोड में आ गया है। एक तरफ संघ के स्वयंसेवक पहले से ही सक्रिय हो गए हैं, वहीं संघ का बड़ा आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित संघ के कई पदाधिकारी शामिल होंगे। इस अवसर पर संघ के नेता सत्ता, संगठन और संघ को चुनावी टिप्स देंगे और आगे की रणनीति का खाका तैयार करेंगे।

2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मप्र में संघ सक्रिय हो गया है। 11 दिसंबर को राजधानी के लाल परेड मैदान में संघ का बड़ा आयोजन होगा। जिसमें प्रदेशभर के दो हजार से अधिक स्वयंसेवक शामिल होंगे। इसके साथ ही संघ के सहायक संगठनों के साथ बैठकें करने के अलावा दंड प्रदर्शन कार्यक्रम में भी होसबोले शामिल होंगे। संघ के सर कार्यवाह के प्रवास को देखते हुए मोहल्लों से ऐसे स्वयंसेवकों की टीम तैयार की जा रही है, जो इस कार्यक्रम के लिए पूरी तरह फिट हों। दंड प्रदर्शन कार्यक्रम में युवा संघ का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। संघ ने बस्तियों में संघ के स्वयंसेवकों की टीम तैयार करने का निर्णय लेने के बाद अब यहां नियमित शाखा लगाने का काम तेज कर दिया है। संघ के सर कार्यवाह भोपाल में संघ के अनुषांगिक संगठनों की वन टू वन बैठक लेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले 11 दिसंबर से तीन दिनी प्रवास पर भोपाल में रहेंगे। होसबोले भाजपा समेत संघ से जुड़े अनुषांगिक संगठनों के साथ समन्वय बैठक लेंगे। इसमें सत्ता से समन्वय पर भी चर्चा होगी। होसबोले भाजपा के कुछ आला नेताओं से अलग से भी मुलाकात कर सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख जबलपुर आए थे। यहां उन्होंने संघ के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अनुषांगिक संगठनों के नेताओं से भी चर्चा की थी। भागवत की प्रदेश यात्रा के बाद अब होसबोले राजधानी आ रहे हैं। प्रदेश में सत्ता और संगठन के चुनावी तैयारियों में लगे होने के बीच होसबाले की यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार्यवाह संघ के दो दर्जन से अधिक अनुषांगिक संगठनों के प्रमुखों के साथ समन्वय बैठक करेंगे। इसमें भाजपा के शीर्ष संगठन नेता भी शामिल होंगे। होसबोले की पिछली राजधानी यात्रा संघ पदाधिकारियों से मेल मुलाकात और बैठकों तक ही सीमित रही थी पर इस बार वे ज्यादा से ज्यादा लोगों से चर्चा करेंगे। वे इन अनुषांगिक संगठनों के एक साल के कामकाज और आगामी तीन महीनों की कार्ययोजना पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही प्रबुद्ध नागरिकों के साथ उनके संवाद का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस दौरान लाल परेड ग्राउंड पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर संघ का नगर में एक पथसंचलन भी निकलेगा जो विभिन्न रास्तों से होता हुआ लाल परेड ग्राउंड पर समाप्त होगा।

प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ समन्वय बैठक भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनुसूचित जाति, जनजाति और कोर वोटरों को लेकर बात होगी। जो पिछले चुनाव में भाजपा का साथ छोड़ गए थे। अब फिर से उनका दिल कैसे जीता जाए बैठक में इस पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि विगत महिलों में दिल्ली में हुई समन्वय बैठक में भाजपा नेताओं से राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर्स के बीच काम करने को कहा गया था। मप्र में यह भाजपा के परंपरागत वोटर माने जाते थे, लेकिन पिछले चुनाव (2018) के विधानसभा चुनाव में ये वोटर्स भाजपा का साथ छोड़कर चले गए थे। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी फीडबैक दिया जाएगा कि किन क्षेत्रों में भाजपा को ज्यादा काम करने की जरूरत है। सूत्रों का कहना है कि सत्ता और संगठन के पदाधिकारियों को संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मप्र में 2023 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा को हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनाव में उतरने के लिए रणनीति बताएंगे।

● जितेंद्र तिवारी

महाकौशल प्रांत में भागवत कर चुके हैं फील्डिंग

गौरतलब है कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 18 नवंबर से 20 नवंबर तक जबलपुर में महाकौशल प्रांत से आने वाले संघ कार्यकर्ताओं की बैठक कर 2023 के विधानसभा चुनाव की फील्डिंग की। सरसंघचालक ने इस दौरान जबलपुर के राजनीतिक ताप का भी आंकलन किया। कभी संघ का गढ़ माने जाने वाले जबलपुर में इस वक्त भाजपा और कांग्रेस के आधे-आधे विधायक हैं। महाकौशल के प्रमुख नगर जबलपुर को प्रदेश के आदिवासी जमात की राजनीति का केंद्र भी माना जाता है। इस दौरान भागवत ने स्वयंसेवकों द्वारा संगठन की दृष्टि से किए जा रहे कार्यों, सामाजिक कार्यों और नूतन प्रयोगों की जानकारी ली। साथ ही देशभर में स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न रचनात्मक कार्यों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। मप्र की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों समुदाय के लिए आरक्षित हैं। करीब 22 फीसदी वोट आदिवासियों के हैं। पिछले कई चुनावों से आदिवासी समुदाय मप्र की राजनीति के केंद्र में रहा है। 2003 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा की जीत में आदिवासी समुदाय का कांग्रेस से मोहभंग होना बड़ा कारण था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ना केवल 6 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, बल्कि आदिवासी सीटों पर कांग्रेस के वोट भी काटे थे। आदिवासी वोट 2013 तक के चुनाव में भाजपा के साथ बना रहा। इस चुनाव में जहां भाजपा को 31 सीटें मिली थीं, वहीं कांग्रेस को 16 सीट पर संतोष करना पड़ा था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस का भाग्य बदलने की बड़ी वजह आदिवासी समुदाय के वोट थे। इस चुनाव में आदिवासियों का भाजपा से मोह भंग हो गया। कांग्रेस के खाते में आदिवासी समुदाय की 31 सीटें गईं तो 16 सीटें भाजपा को मिली। भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी, जो उसकी चिंता की बड़ी वजह है।

पानी की सुरंगों वाला शहर

आपने सुना होगा कि शहरों के नीचे नदियां होती हैं, लेकिन रीवा ऐसा पहला शहर होगा, जिसके नीचे पानी की सुरंगें होंगी। इसे वॉटर टनल कहा जाता है। रीवा के तराई अंचल और पहाड़ी इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए त्योंथर टनल और बहुती टनल का काम अंतिम चरण में है। पहाड़ियों को हैवी मशीनरी से काटकर टनल को बनाया गया है। इन टनल से न सिर्फ पीने के पानी की समस्या खत्म होगी, बल्कि किसानों की जमीन को भी भरपूर पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों का कहना है कि सारी नहरों का काम लगभग पूरा हो चुका है। छोटे-छोटे काम बाकी हैं। इनके पूरा होते ही इन सुरंगों से पानी की सप्लाई होने लगेगी। इन सुरंगों से किसानों को ही नहीं शहरी लोगों को भी फायदा होगा। विंध्य में रीवा और सतना के किसानों को नए साल के बाद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि बाण सागर बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना के तहत बहुती नहर परियोजना का सबसे अहम काम पूरा हो गया है। बाणसागर बांध का पानी बहुती नहर परियोजना में पहुंचाने के लिए छुहिया घाटी गोविंदगढ़ में बनाई जा रही वॉटर टनल का काम पूरा हो चुका है। अब महज 6 महीने के भीतर ही इससे वॉटर सप्लाई शुरू हो जाएगी। इस परियोजना से रीवा की पांच तहसीलों और सतना की दो तहसीलों के 65 हजार हेक्टेयर में खेती कर रहे 3 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, नई टनल बनने से नलों में वॉटर प्रेशर भी ठीक से आएगा।

अब जान लेते हैं रीवा की तीन अहम टनल्स के बारे में, कॉमन वॉटर कैरियर (सीडब्ल्यूसी) टनल का काम एक दशक पहले पूरा हो चुका है, त्योंथर और बहुती टनल का निर्माण अंतिम चरण में है। 1978 में बाणसागर बांध परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। परियोजना पूरी होने के बाद 2006 में इसका लोकार्पण किया गया। 7वीं शताब्दी में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट विंध्य के शहडोल जिले के निवासी थे। 14 मई 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बांध की आधारशिला बाणसागर डैम के रूप में रखी। मप्र, उप्र और बिहार सरकार ने मिलकर 28 साल बाद शहडोल जिले के देवलौंद में सोन नदी का पानी रोककर बांध बनाया। तब शहडोल, सतना, कटनी और उमरिया जिले के गांवों का भू अधिग्रहण किया गया था। 25 सितंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बाणसागर बांध राष्ट्र को समर्पित कर दिया। बाणसागर बांध से मप्र में 2,490 वर्ग किलोमीटर, उप्र में 1500 वर्ग किलोमीटर और बिहार राज्य में 940 वर्ग किलोमीटर की सिंचाई की जाती है। बाणसागर बांध एक अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहां के पानी से 435 मेगावाट बिजली भी बनाई जाती है। कॉमन वॉटर कैरियर नहर का विस्तार साल 2006 के बाद से किया जा रहा है। 36.57 किलोमीटर की नहर से सीधे सिंचाई नहीं होती है। सीधी जिले के बघवार से 4 किलोमीटर की सुरंग बनाकर रीवा की छोर पर नहर से पानी लाया जाता है। यहां से सीडब्ल्यूसी कैनाल तीन भागों में विभाजित हो जाती है। एक कैनाल उप्र, दूसरी सीधी जिले के सिहावल और तीसरी सिलपरा तक आती है। सिलपरा में बिजली तैयार कर पानी को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग बिछिया नदी पर टीकर के पास गिरा दिया जाता है, जबकि दूसरा भाग पूर्वा मुख्य नहर बन जाती है। रीवा के आगे बिछिया नदी का नाम बदलकर बीहर हो जाता है। यही पानी बीहर बराज में जाकर टीएसपी के लिए नहर से प्रवाहित किया जाता है। फिर 26वें किलोमीटर में टी बनाकर यानी की कट लगाकर त्योंथर कैनाल में विभाजित हो जाती है। फिर सुरंग के रास्ते फोरवे तक पानी जाता है। विंध्य की त्योंथर टनल अभी तक की सबसे बड़ी सुरंग है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमएल सिंह ने बताया कि सिरमौर-गोदहा मोड़ के मध्य पडरी गांव के 26वें किलोमीटर से सुरंग शुरू होती है, जो फोरवे सिरमौर टोंस जल विद्युत परियोजना के नजदीक जाकर खत्म होती है। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। घाटीनुमा पहाड़ में सुरंग बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। यहां पहले से बीहर और बकिया बराज की ओपन नहर थी, लेकिन कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए सुरंग 5 साल में तैयार की गई है। 2022 की शुरुआत में ही ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। इस नहर को बाणसागर, बीहर बराज और बकिया बराज से कनेक्ट किया गया है। सुरंग का पानी घाट से उतारकर तराई के त्योंथर और जवा आदि क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है।

पहले बहुती टनल को बाणसागर बांध के झिन्ना गांव के पास प्रस्तावित किया था। इसमें से करीब 14 किलोमीटर की नहर के साथ 45 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जाना था। नई डिजाइन में सतना जिले के रामनगर तहसील के गुलवार गुजारा गांव से नहर का मुख्य प्रवाह बनाने को मंजूरी मिली। इतना ही नहीं, नहर का विस्तार 18 किलोमीटर तक किया गया। 3.790 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई। इस सुरंग से पानी का प्रवाह भी 10 लाख क्यूबिक मीटर तक बढ़ने की उम्मीद है। गर्मी के मौसम में जब बाणसागर परियोजना में पानी का स्तर कम हो जाता है, उस समय भी नहर में प्रवाह बनाए रखने के लिए आमघोरी रामादीन गांव के पास एक फीडर पंप भी लगाया जा रहा है। इसके कारण नहर और सुरंग सहित करीब 21 किलोमीटर तक पानी का प्रवाह 54 लाख क्यूबिक मीटर बना रहेगा।

● **राजेश बोरकर**

पेयजल की व्यवस्था के लिए 158 करोड़ मंजूर

रीवा नगर निगम को हर घर शुद्ध पानी पहुंचाने हेतु अमृत योजना क्र.2 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने स्वीकृति प्रदान की। योजना के तहत रीवा नगर निगम को 158 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे जिससे नए फिल्टर प्लांट, टंकी, पाइप लाइन और नगर के हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। अमृत योजना क्र.2 की स्वीकृति मिलने पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार ज्ञापित करते हुए कहा है कि रीवा के भविष्य को ध्यान मे रखकर वर्तमान संवारने की योजना है। इस योजना के तहत आगामी 30 वर्षों के लिए कार्य योजना बनाकर नई टंकी और पाइप लाइन सहित अधोसंरचना का विकास किया जाएगा और आने वाले 30 वर्षों तक हर घर में कनेक्शन से जल आपूर्ति होती रहेगी।

सहकरिता की हालत खराब

कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के कारण कंगाली में पहुंची सहकारिता को बचाने के लिए प्रदेश सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। लेकिन अधिकारियों की कमी और बढ़ते भ्रष्टाचार से सहकरिता की हालत खराब होती जा रही है। प्रदेश में यूं तो सहकारी आंदोलन की जड़ें गहरी हैं, पर भ्रष्टाचार का दीमक इसे खोखला करने में लगा है। आए दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के घोटाले सामने आते रहते हैं। घोटालों के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की फाइल तो चलती है, पर उनकी गति धीमी होती है। ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाती, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव कर सके या बदलाव का माहौल बना सके। दरअसल सहकारी बैंकों और समितियों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों की जांच सहकारिता विभाग के वे अधिकारी ही करते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुप्रबंध के लिए जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि छिटपुट कार्रवाइयों के बावजूद भ्रष्टाचार का सिरा खत्म नहीं होता। इसी कुप्रबंध का नतीजा है कि राज्य की सैकड़ों सहकारी समितियां कंगाल हो चुकी हैं।

दरअसल, प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए विभाग और शासन स्तर पर बनी रणनीति मूर्त रूप नहीं ले पाई है। साल के शुरुआत में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाले सहकारी बैंकों को वित्तीय दृष्टि से स्वायत्ता एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा और नई सहकारिता नीति लाई जाएगी। ये दोनों काम अब तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं विभाग में लगातार घट रहे सहकारी अफसरों के कारण करोड़ों के भ्रष्टाचारों की जांच कार्रवाई भी ठप है। 5 हजार से अधिक समितियों का ऑडिट भी प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य आदि नए क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने की योजना बनाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण औद्योगिक सहकारी समिति गठित करने और प्रदेश में खराब स्थिति वाले पैक्स को पुनर्जीवन और प्रभावी बनाने की योजना तैयार करने निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने फरवरी 2022 तक नई सहकारिता नीति लाने को भी कहा था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य समय पर पूरे करने, सहकारी कब तक आएगी। गृह निर्माण समितियों में प्लॉट आवंटन को लेकर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए दीर्घकालिक बनाने, कंप्यूटरीकरण आदि कार्यों को छह माह में पूरा करने को कहा गया था।

अफसरों की कमी से जांच प्रभावित

सहकारिता में अफसरों की कमी का खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। अफसरों की कमी के कारण भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों की जांच प्रभावित हो रही है। करीब तीन साल पहले शिवपुरी के कोलारस में 80 करोड़ का वित्तीय घोटाला सामने आया था। इसके 14 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। शुरुआती दौर में जांच हुई और कई लोग निलंबित किए गए। लेकिन इस पूरे मामले का अंतिम निचोड़ अब तक नहीं आया है। जानकारी मिली है कि जांच के नाम पर सहायक आयुक्त चुरा रहे हैं। कई तो अवकाश लेकर जांच से दूरी बनाए हुए हैं। जिला सहकारी बैंक गुना की साधारण सभा की बैठक में दो संचालकों ने बैंक के डूबने की आशंका जताई थी। उन्होंने बताया था कि 148 पैक्स पर कम से कम 700 करोड़ रुपए बकाया है। बैंक के जीएम ने भी किसानों पर 400 करोड़ से ज्यादा बकाया होने की बात मानी थी लेकिन उन्होंने 300 करोड़ के बारे में चुप्पी साध ली थी। इस मामले की जांच हुई न कार्रवाई। छिंदवाड़ा के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कृषि शाखा में हुए गबन की परतें खुलीं। जांच रिपोर्ट में 4 करोड़ 15 लाख 78 हजार 250 रुपए का गबन होना सामने आया है। गबन से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य एसपी को सौंपे गए। जांच की गई लेकिन अंतिम रिपोर्ट अटकी है। बालाघाट में भी कृषक पत्रिका के नाम पर घोटाला हो चुका है।

आलम यह है कि कई जिले सहकारिता अफसरों से खाली हैं। भोपाल, रायसेन, आलीराजपुर, अशोकनगर, जबलपुर, बालाघाट और नरसिंहपुर जिले में उपायुक्त नहीं हैं। सीहोर, विदिशा, बैतूल, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सिंगरौली, अनूपपुर, जबलपुर, बालाघाट, डिंडौरी और नरसिंहपुर में सहायक आयुक्त अंकेक्षण और श्योपुर तथा डिंडौरी में सहायक आयुक्त सहकारिता नहीं हैं। कई अफसर वीआरएस भी ले चुके हैं। यही कारण है कि सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति की पहल की है। सहकारी लोकपाल स्वतंत्र निकाय की तरह काम करेगा। उसका ढांचा इस तरह तैयार किया जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए वह निष्पक्ष ढंग से जांच एवं त्वरित कार्रवाई कर सके। लोकायुक्त पुलिस की तर्ज पर सहकारी लोकपाल की टीम का भी जिला स्तर पर विस्तार किए जाने की योजना है।

मप्र में साढ़े चार हजार से ज्यादा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। उन्हें 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के माध्यम से किसानों को ब्याजरहित अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए राशि मिलती है। खरीफ और रबी सीजन में हर साल 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण 25 लाख से अधिक किसानों को दिया जाता है। समितियां ही किसानों को खाद और बीज भी देती हैं। इनके माध्यम से 5 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

● **प्रवीण सक्सेना**

शीतकालीन सत्र में बजट की झलक

मप्र की 15वीं विधानसभा का अंतिम शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होगा। पांच दिवसीय इस सत्र में सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही नगर पालिक विधि संशोधन, लोक सुरक्षा विधेयक सहित अन्य संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा। दिसंबर में 16वीं विधानसभा का गठन होगा। सदस्यों की शपथ के लिए सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन इसमें अन्य कोई शासकीय कार्य नहीं होगा। फरवरी-मार्च 2023 में होने वाले बजट सत्र से विधिवत कार्य प्रारंभ होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि चुनाव होने के बाद नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया में कुछ समय लगता ही है। उधर, सरकार ने 19 दिसंबर से होने वाले शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले द्वितीय अनुपूरक बजट की तैयारी को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इसमें अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग किराएदारी अधिनियम विधेयक, गृह विभाग भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, बिजली के पर्याप्त प्रबंध के लिए लोक सुरक्षा अधिनियम, ऑनलाइन गेम्स पर नियंत्रण के लिए विधेयक प्रस्तावित हैं। सत्र के अंतिम दिन 23 दिसंबर को अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय ने सदस्यों को पत्र लिखकर कहा है कि कार्य संचालन नियम के अनुसार कोई भी सूचना विधानसभा सचिवालय को दी जाए। अभी देखने में यह आया है कि कई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सूचनाएं देते हैं जो नियमानुसार सही नहीं है। डाक से भी सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। सत्र के दौरान ऐसा कोई विषय भी नहीं उठाया जाएगा, जो न्यायालय में विचाराधीन हो।

सरकार ने मार्च में प्रस्तुत होने वाले बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह उत्साहित दिख रहे हैं, उससे तो यह साफ हो गया है कि प्रदेश का बजट आत्मनिर्भर मप्र पर आधारित होगा। शिवराज सरकार का आगामी बजट निश्चित रूप से प्रदेश की दिशा तय करने वाला होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट शिवराज सरकार के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इस मायने में कि राज्य में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके मुकाबले आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। जनता को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य को संकट से उबारने में मदद मिली है। हालांकि वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत अभी भी है।

प्रदेश का बजट इस बार तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। स्वयं का राजस्व बढ़ाने पर सरकार द्वारा जोर दिया जाएगा। साथ ही विभागों को बजट से अतिरिक्त भी वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में तीन प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से प्रविधान रखे जाएंगे तो महंगाई भत्ते के लिए वेतन मद में कुल प्रस्तावित राशि का 32 प्रतिशत हिस्सा रखा जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब तक की तैयारियों से माना जा रहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट के जरिए सरकार बड़ा संकल्प जाहिर कर सकती है। सरकार के लिए यह बजट चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी है। माना जा रहा है कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मप्र का खाका खींचने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस बार का बजट अवसर सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि जोखिम लेकर अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं, वे सभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित हुए हैं। कोरोना संकट से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। लगभग सभी क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो रही है। यह शुभ संकेत हैं, क्योंकि सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, उसके लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक जरूरत होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को अतिरिक्त आय सृजित करने के लक्ष्य भी दिए हैं। जीएसटी के बाद राज्य के पास टैक्स लगाने का दायरा सीमित हो गया है। ऐसे में उन विकल्पों पर विचार करना होगा, जिनके माध्यम से सरकार जनता पर कर का बोझ बढ़ाए बगैर आय बढ़ा सकती है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

नई योजना लाने का बताना होगा औचित्य

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यदि विभाग कोई नई योजना लाना चाहते हैं तो उन्हें औचित्य बताना होगा। वे अपने स्तर से कोई निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। उन्हें प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजना होगा और उस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। वहीं, कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में आगामी वर्ष में होने वाली संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग 46 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को बजट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन पर चर्चा 5 जनवरी से प्रारंभ होगी। शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए और प्रथम अनुपूरक बजट 9 हजार 784 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया था। 19 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अगले साल चुनाव हैं। इसे देखते हुए बजट तीन लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। सरकार ने आय में वृद्धि के लिए राजस्व संग्रहण पर जोर देने के साथ अन्य विकल्प भी अपनाए हैं। अनुपयोगी सरकारी परिसंपत्तियों की नीलामी की जा रही है तो विभागों को अन्य माध्यमों से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कहा गया है।

मप्र की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट आयोजित होने जा रही है। समिट की औपचारिक शुरुआत से पहले इंदौर में ग्लोबल सीईओ कॉनक्लेव भी आयोजित होगा। इसमें देश और दुनिया के टॉप बिजनेस टायकून खाने की मेज पर मप्र में निवेश पर चर्चा करेंगे। समिट से एक दिन पहले 10 जनवरी की रात को कॉनक्लेव आयोजित किया जाएगा।

इंवेस्टर्स समिट से पहले निवेश की भरमार...

जनवरी माह के 5 दिन इंदौर के लिए अहम होने जा रहे हैं। 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। यह आयोजन इंदौर में ही होगा। हालांकि, इसकी कमान केंद्रीय विदेश मंत्रालय के हाथों में रहेगी। 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन खत्म होते-होते ही ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का बिगुल बज जाएगा। मप्र सरकार और शासन-प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के खत्म होते-होते ही उन्हें ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट शुरू करना है।

सीआईआई को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में शामिल होने वाले उद्योगपति मेहमानों की अगवानी, मेजबानी से जुड़ी व्यवस्थाएं देखने की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मेहमान 10 जनवरी को होटल से चेकआउट करें वैसे ही ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के मेहमानों को होटलों में जगह दे दी जाए। 10 तारीख को एक आयोजन के बाद मेहमानों की विदाई और उसी बीच नए मेहमानों की अगवानी करना और ठहराना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। शहर के सभी सितारा होटलों में लगभग पूरे कमरे ही इन दोनों आयोजनों के लिए बुक किए जा चुके हैं।

10 जनवरी की शाम 7 बजे से ग्लोबल सीईओ कॉनक्लेव शुरू होगा। इसी दौरान एक खास डिनर होगा। इसमें सीईओ शामिल होंगे और मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेजबानी करते नजर आएंगे। मप्र औद्योगिक विकास निगम के अनुसार समिट के लिए अब तक कुल 17 देशों को पार्टनर कंट्री के रूप में जोड़ा और न्योता दिया गया है। इसके साथ ही 15 अन्य देशों के उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। तीन देश अमेरिका, ब्रिटेन और कोरिया प्रमुख भागीदार के रूप में चर्चा में शामिल होंगे।

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में कन्फर्म निवेश पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अधिकारी निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्र, नीति और निवेश सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं, ताकि निवेशक समिट से पहले प्रदेश में जगह सुनिश्चित कर लें। इस रणनीति के तहत शहरों के प्रमुख सेक्टर के उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश को भी सेक्टर वाइज प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। अब तक निवेशकों से चर्चा के आधार पर लगभग 5 हजार करोड़ का निवेश प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने की उम्मीद है। फार्मा, गारमेंट, टेक्सटाइल्स व इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्यूफेक्चरिंग के क्षेत्र में करीब 2500 करोड़ का निवेश इंदौर क्षेत्र में आएगा।

इस बार निवेश की राशि से ज्यादा जोर रोजगार जनरेशन पर है। बेंगलुरू गई टीम को गारमेंट में अच्छे संकेत मिले हैं। बड़ी संख्या में निवेशक यहां आ सकते हैं। एमडी मनीष सिंह ने बताया कि कई कंपनियों के साथ वन-टू-वन चर्चा हो चुकी है। गारमेंट कारोबारियों का रूझान प्रदेश की ओर है। गारमेंट सेक्टर में 1 करोड़ निवेश से 70 लोगों को रोजगार मिलता है। अब यूरोप की स्थिति में सुधार आ रहा है। इससे छोटे जिलों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस सेक्टर में निवेश भले ही छोटा आएगा, लेकिन रोजगार ज्यादा लोगों को मिलेगा। खासकर महिला उद्यमियों को भी अवसर मिलेंगे।

रूचि लेने वालों में साही एक्सपोर्ट, लैगूना, गोकुलदास एक्सपोर्ट, हेमअप व अन्य हैं। सिंह ने बताया कि मेंटर साइमेन के रूचित दीक्षित ने इन्क्यूबेशन तो ईएसडीएम के जयराज श्रीनिवास, ज्योति खंडास्वामी ने टेक्सटाइल्स सेक्टर के लिए मुलाकात की है। मुख्यमंत्री अलग-अलग शहरों में सेक्टर के अनुसार निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। अब तक वे दिल्ली, मुंबई, पुणे व बेंगलुरू जा चुके हैं। इंदौर रीजन के लिए फार्मा, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक में अच्छी संभावना बन रही है। उन्होंने बेंगलुरू में आईटी, स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्यूफेक्चरिंग व डिजाइन, टेक्सटाइल्स-गारमेंट के उद्यमियों से

बेंगलुरु में शिवराज ने दिया उद्योगपतियों को न्योता

मप्र देश का स्वच्छतम राज्य है। प्रदेश लगातार छठवीं बार स्वच्छता में उपलब्धियां अर्जित कर देश का सिरमौर बना है। प्रदेश में 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। अटल एक्सप्रेस-वे, नर्मदा एक्सप्रेस-वे से जहां एक ओर अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहीं दिल्ली और गुजरात से भी आवागमन सुगम और कम समय में होगा। इंदौर और भोपाल के बीच में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। मप्र में उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है। मप्र पावर सरप्लस राज्य है, दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी मप्र के सोलर प्लांट से चल रही है इसलिए निवेश के लिए मप्र आइए। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेंगलुरू में मप्र में निवेश के अवसर विषय पर संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। स्किल्ड मेन पावर के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, प्रदेश के लोग शांति से कार्य करने में विश्वास रखते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी प्रो-एक्टिव है। यह सब बिंदु औद्योगिक विकास और निवेश के लिए हमारी ताकत है। राज्य सरकार उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार अपनी विभिन्न नीतियों में जरूरी बदलाव करने के लिए सहमत है। प्रदेश में सभी क्षेत्रों के उद्योग और निवेश के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं।

चर्चा की। हैदराबाद में आईटी सेक्टर के साथ हेल्थ केयर पर जोर रहेगा। मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के निवेशक भी आगे आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों से चर्चा कर रहे हैं। यहां से ज्योति लैबोरेटरीज इंदौर आने में रूचि ले रही है।

दिल्ली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने ऑटो एनसिलरिज और इंजीनियरिंग प्रॉडक्ट पर जोर दिया। इसके अलावा प्लास्टिक उपकरण, खिलौना व इलेक्टॉनिक्स मेन्यूफेक्चरिंग से जुड़े निवेशकों के साथ चर्चा की। सीआईआई और कुछ एमएनसी के प्रमुखों से भी बातचीत हुई है। मुंबई से फार्मा, लॉजिस्टिक और मल्टी प्रॉडक्ट कंपनियों के प्रमुखों से चर्चा चल रही है। फार्मा सेक्टर की चार कंपनियों का कंफर्म निवेश मिला है। टेक्सटाइल्स कंपनियों में भीलवाड़ा की यूनिट्स नीमच व रतलाम आने के लिए लालायित है। पुणे से ऑटो मोबाइल, इंजीनियरिंग और हायर एजुकेशन के लिए चर्चा चल रही है। दो-तीन निजी विवि इंदौर-देवास के आसपास रूख कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल व इंजीनियरिंग, फार्मास्युटिकल, हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइस, एग्रो व फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स-गारमेंट, लॉजिस्टिक व वेयरहाउसिंग, एयरोस्पेस व डिफेंस, आईटी-इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्यूफेक्चरिंग, केमिकल्स, टूरिज्म आदि सेक्टर पर फोकस किया जाएगा।

जनवरी में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। देश और विदेश के इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुटे हुए हैं। गत दिनों बेंगलुरू में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टेक्सटाइल, आईटी के दिग्गजों के साथ वन-टू-वन चर्चा की और अन्य उद्यमियों से भी मुलाकात कर उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मेलन और उसके बाद आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में आने का न्योता दिया। साही एक्सपोर्ट, गोकुलदास, लगुना सहित अन्य बड़ी कंपनियों ने अपनी सहमति भी दे दी है। वहीं आईटी के दिग्गजों, जिनमें इंटेन, माइंडफ्री, टीसीएस-इन्फोसिस सहित अन्य ने भी मुख्यमंत्री से बेंगलुरू में चर्चा की। पूरे इंदौर को सजाने-संवारने और रोशन करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप इस अतिमहत्वपूर्ण आयोजन में इंदौर के हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी भी करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अधिकारियों से कहा गया कि वे अपनी उपसमितियों का भी गठन कर लें। 8 से 10 जनवरी तक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और उसके बाद 11-12 जनवरी को इंवेस्टर्स समिट का आयोजन होना है। संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य के मामलों में भी गंभीरता बरती जा रही है। ऐसा हेल्थ मूवमेंट प्लान बनाया जा रहा है कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में प्रभावित को दो मिनट में ही मेडिकल सहायता मिल सके और निर्धारित अस्पताल में भी पहुंचाया जा सके। इसके लिए होटलों के प्रबंधकों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की मॉकड्रिल भी करवाई जाएगी। कलेक्टर इलैया राजा ने कहा कि आयोजन के दौरान फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए स्थलों का मौका-मुआयना कर संबंधित अधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार करें। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने एयरपोर्ट से लेकर ब्रिलियंट व शहर के सभी क्षेत्रों में निगम द्वारा शुरू की गई तैयारियों की जानकारी दी, जिसमें सौंदर्यीकरण के कार्य भी शुरू करवा दिए गए हैं।

इन दोनों महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान शहर को दीपावली की तरह सजाया-संवारा और रोशन किया जाएगा। शहर के सभी प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक इमारतों, शॉपिंग मॉलों में विशेष सजावट के साथ रोशनी भी करवाई जाएगी। आने वाले अतिथियों को इंदौर के साथ-साथ आसपास के धार्मिक और ऐतिहाासिक स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाएगा। इंदौर के प्रसिद्ध छप्पन दुकान, सराफा चाट-चौपाटी की भी विशेष सैर करवाई जाएगी, जिसके चलते यहां भी विशेष व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। एयरपोर्ट पर भी अतिथियों के स्वागत-सत्कार की विशेष व्यवस्था रहेगी। वीआईपी तथा यात्रियों के आने-जाने के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी और आयोजन स्थल तक के मार्ग को विशेष रूप से सुसज्जित कराया जा रहा है। पूरे सुपर कॉरिडोर पर निगम के साथ-साथ प्राधिकरण भी तैयारियों में जुट गया है। गत दिनों **प्रवासी भारतीय सम्मेलन** व ग्लोबल समिट तैयारियों के मद्देनजर मप्र औद्योगिक विकास निगम के एमडी मनीष सिंह ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समीक्षा बैठक भी ली, जिसमें सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।

● **लोकेंद्र शर्मा**

इन्वेस्टर्स समिट से स्टार्टअप को मिलेगी गति

जनवरी में होने जा रही इंवेस्टर्स समिट से बड़ी आईटी कंपनियों और उद्योगों को तो लाभ मिलेगा ही, प्रदेश के स्टार्टअप को भी गति मिलेगी। समिट में देश-विदेश के कई उद्योगों के दिग्गज आ रहे हैं, जो कई स्टार्टअप को फंडिंग कर चुके हैं। समिट में निवेशकों और स्टार्टअप संचालकों के बीच चर्चा होगी। इनमें बेहतर नवाचार वाले आईडिया और उत्पाद की जानकारी दी जाएगी। इससे संभावनाएं बनी हुई हैं कि स्टार्टअप को भी अच्छी फंडिंग मिल सकती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मप्र के उत्पादों को पहचान मिल सकती है। 2021 से अब तक इंदौर के स्टार्टअप को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिल चुकी है। इंदौर में तीन वर्ष पहले करीब 300 स्टार्टअप थे। इनमें से ज्यादा फूड और सर्विस क्षेत्र के थे, लेकिन अब संख्या 700 हो गई है। इनमें आईटी, शिक्षा, ग्रीन एनर्जी, ईकोफ्रेंडली डिस्पोजल, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के हैं। स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर शहर में ही कई उत्पाद तैयार हो रहे हैं। इनकी मांग विदेशों तक बन गई है। शहर में स्टार्टअप को तकनीक और फंडिंग उपलब्ध कराने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या भी बढ़ गई है। पहले विजय नगर क्षेत्र में एक ही इंक्यूबेशन सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब एआईसीटीएसएल, आईआईटी इंदौर, एसजीएसआईटीएस, आरआरकैट और कई शिक्षण संस्थानों में अलग से ये स्थापित हुए हैं।

ग्रीन फील्ड योजना में शामिल होगा मप्र

केंद्र सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 15वें वित्तीय आयोग के तहत देश के 8 शहरों को ग्रीन फील्ड योजना में शामिल किया जाना है। इस योजना में शामिल होने वाले शहर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। देश में 8 नए शहर विकसित करने की प्रतियोगिता में मप्र शामिल होगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तैयारी कर रहा है। साल के आखिरी माह में केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस बेस्ट चैलेंज फंड के लिए दावेदारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने देश में 8 नए शहर विकसित करने के लिए सभी राज्यों से प्लान मांगा है ये शहर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर चयनित किए जाएंगे।

दरअसल, देश में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए केंद्र सरकार देश में 8 नए शहर विकसित करेगी। 15वें वित्त आयोग ने भी 8 राज्यों में 8 नए शहर बसाने के लिए 8 हजार करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 8 नए ग्रीनफील्ड शहर बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं। यानी एक शहर बसाने पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 शहरों के विकास के लिए एक हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इस कड़ी परीक्षा में शामिल होने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इंदौर में पीथमपुर, ग्वालियर में काउंटर मैग्नेट सिटी और देवास जिले के हाटपिपलिया में नए शहर विकास का प्लान तैयार किया जा रहा है। इन शहरों को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक मूल्यांकन में उपयुक्त पाया है। नए शहर विकास के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और उद्योग विभाग के संयुक्त प्रयासों से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव भारत सरकार को दिसंबर 2022 तक भेजा जाएगा। नए शहर का चयन करने के लिए केंद्र सरकार ने कई मापदंड तय किए हैं। इनमें मुख्य तौर पर इंटरसिटी से कनेक्शन सुविधा हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वगवन सुविधा, सड़क संपर्क, हवाई संपर्क सहित अन्य प्रमुख सुविधाओं के होने को देखा जाएगा।

केंद्र सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 15वें वित्तीय आयोग के तहत देश के 8 शहरों को ग्रीन फील्ड योजना में शामिल किया जाना है। इस योजना में शामिल होने से ग्वालियर के काउंटर मैग्नेट सिटी के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतने पैसों से साडा काउंटर मैग्नेट सिटी का पूरा विकास कर सकेगा जिससे वहां पर रहवासी क्षेत्र विकसित हो पाएंगे। अभी फिलहाल वहां पर बने मकानों में एक भी परिवार नहीं रहता है। इसके कारण यह पूरा मिनी शहर भूतह शहर बन चुका है।

ग्रीन फील्ड योजना में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ग्वालियर का नाम इस योजना में शामिल होने के लिए भेजने की बात कही थी। केंद्र सरकार की इस योजना में पुराने शहर के पास नए शहर को बसाया जाना है, इस योजना में शहर के विकास की थीम औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है जिससे शहर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। शहरों के शामिल होने के बाद 1,000 करोड़ रुपए की पहली किश्त मार्च 2023 तक दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि श्रीमंत माधवराज सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी के लिए 8065 वर्ग किलोमीटर भूमि नोटिफाइड की जा चुकी है। इसमें से 90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आधारभूत सरंचनाएं हैं। जिसमें सड़क, बिजली, पानी सीवर लाइन पार्क आदि हैं। इसके साथ ही यहां पर आवासीय क्षेत्र के साथ ही आईटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क आदि भी हैं। इसलिए केंद्र सरकार की ग्रीन फील्ड योजना में शामिल करने के लिए यह काफी उपयुक्त है। आर्थिक अभाव के कारण वर्तमान में यहां पर कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही जो विकास कार्य हो चुके हैं उनके रखरखाव एवं साडा के कर्मचारियों की सैलरी निकालने में भी परेशानी हो रही है। अगर ग्वालियर ग्रीन फील्ड में शामिल हो जाता है तो यहां का विकास काफी तेजी से हो सकेगा।

वित्त आयोग की मंशा है कि एक हजार करोड़ के फंड से अलग शहर विकसित करके उद्योग बढ़ाए जाएं और रोजगार के अवसर बढ़ें। इसी उद्देश्य से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 50 हेक्टेयर से अधिक अलग स्थान की तलाश की गई है। यहां निवेश के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। जबकि ग्वालियर के मैग्नेट सिटी को टूरिज्म की नजर से देखा जा रहा है। यहां अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाएं और इंफ्रास्टक्चर पर फोकस किया गया है जबकि हाटपिपलिया में भी निवेश के रूप में अलग शहर बनाने का प्लान है। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव का कहना है कि हमारा पूरा प्रयास है कि नया शहर विकास की प्रतियोगिता में मप्र पहले नंबर पर हो। तीन शहरों के लिए योजना बना रहे हैं। करीब 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है। प्लान मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेजेंट किया जाएगा। दिसंबर माह में केंद्र को पूरा प्लान भेज दिया जाएगा।

● अरविंद नारद

8000 करोड़ की मंजूरी

भारत सरकार की ग्रीनफील्ड सिटी योजना देश में एकदम नए शहर बसाने की योजना है। ये 8,000 रुपए नए शहरों की योजना, फ्रेमवर्क और प्लान को हकीकत में बदलने पर खर्च किए जाएंगे। ये 8 शहर किन 8 राज्यों में बनेंगे, यह अभी तय नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा है कि देश में शहरीकरण की जरूरत को देखते हुए नए और पूरी तरह से प्लान किए शहरों की जरूरत है। चंडीगढ़, नवीन रांची देश के पूरी तरह से प्लांड शहर हैं। 15वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। इसमें एयर क्वालिटी में सुधार के लिए 12,139 करोड़ रुपए और पेयजल, सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 26,057 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नए शहरों की कल्पना और बजट आवंटित कर इनको हकीकत बनाने के प्रयास से साफ है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और बेहतर बनाना है।

21 साल का आतंक 40 मिनट में खत्म

ग्वालियर-चंबल में डकैत गुड्डा का पिछले 21 साल से आतंक था। गुड्डा ने हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट जैसी वारदातों को पिछले 21 साल में अंजाम दिया था। 9 नवंबर को साढ़े सात बजे डकैत गुड्डा और उसकी गैंग का पुलिस से आमना-सामना हो गया। आमना-सामना होने पर दोनों तरफ से गोलियां चलीं। लेकिन 40 मिनट में ही गुड्डा का आतंक खत्म हो गया। जैसे ही उसके पैर में गोली लगी और वह पुलिस की गिरफ्त में आया। वैसे ही अंचल के लोगों ने उसके आतंक से राहत की सांस ली।

ग्वालियर पुलिस की टीम एके-47 जैसे आधुनिक हथियार से लैस थी, जैसे ही गुड्डा और उसकी गैंग ने फायर किए, जवाब में पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बसोटा के जंगल में स्थित पहाड़ी की आड़ लेकर गुड्डा और उसकी गैंग फायरिंग कर रही थी। महज 300 मीटर दूर ग्वालियर पुलिस की टीम थी, जिसने करीब 40 मिनट में 90 राउंड फायर किए। इसमें से एक गोली गुड्डा को तब लगी, जब वह तलहटी से भागते समय फायरिंग कर रहा था। गोली लगते ही वह चीखा, तब पुलिस ने उसे दबोच लिया। लेकिन उसके साथी जोगेंद्र गुर्जर, कल्ली गुर्जर और जोगेंद्र सिंह भाग निकले, जिनकी तलाश में लगातार सर्चिंग चल रही है। गुड्डा के पास से 315 बोर की रायफल और 40 कारतूस का पूरा बेल्ट बरामद हुआ है, लेकिन जो राउंड उसकी ओर से फायर हुए हैं, उसमें कुछ राउंड अलग हैं। जिनकी पड़ताल पुलिस कर रही है।

चंबल एडीजी राजेश चावला डकैत गुड्डा की धरपकड़ की योजना बनाने के लिए बॉर्डर मीटिंग लेने पहाड़गढ़ आए थे। पहाड़गढ़ के थाने में मुरैना एसपी आशुतोष बागरी, श्योपुर एसपी आलोक कुमार सिंह के साथ एडीजीपी चावला बैठक कर रहे थे, इसी दौरान साइबर सेल के अफसरों ने बताया कि डकैत गुड्डा गुर्जर पहाड़गढ़ की सीमा से निकलकर ग्वालियर जिले के घाटीगांव-बसोटा के जंगलों में निकल गया है। डकैत गुड्डा के एक साथी की मोबाइल लोकेशन स्पष्ट होने के बाद एडीजीपी चावला ने ग्वालियर एडीजीपी को तत्काल सूचना दी, उसके बाद ग्वालियर पुलिस सक्रिय हुई। मुरैना पुलिस से इनपुट मिलने के बाद ग्वालियर पुलिस की टीम को यहां लगाया गया। डकैत गुड्डा गुर्जर के विरोधी इस गांव में हैं, जिन्हें पुलिस ने सक्रिय कर दिया। ग्वालियर में पदस्थ सीएसपी रत्नेश सिंह तोमर एंटी डकैत टीम में लंबे समय तक रहे, जिसका फायदा उन्हें मिला। सबसे पहले उन्हें इनपुट मिला, इसके बाद उन्होंने एडीजी और एसएसपी अमित सांघी को बताया। दोपहर 1.30 बजे पहला इनपुट मिला कि गुड्डा और उसके साथी जोगेंद्र गुर्जर, कल्ली गुर्जर, जोगेंद्र सिंह बसोटा आए हैं। यहीं से पूरी प्लानिंग शुरू हुई। एडीजी वर्मा, एसएसपी अमित सांघी ने एएसपी राजेश दंडोतिया, डीएसपी ऋषिकेष मीणा, सीएसपी रत्नेश तोमर, क्राइम ब्रांच प्रभारी दामोदर गुप्ता के साथ मिलकर ऑपरेशन प्लान किया। इस टीम में एसआई मनोज परमार, हवलदार नवरीर राणा, भगवती सिंह के अलावा अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। ब्रीफिंग होने के बाद पूरी टीम के निजी नंबर बंद कराए गए, 5 बजे टीम रवाना हो गई। क्योंकि सूचना थी, रात में गैंग यहां से मूव करेगी। 6 बजे से सर्चिंग शुरू हो गई। गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी थी, उसने वह ठिकाना बता दिया, जहां गैंग फरारी काट रही थी। 7.30 बजे आमना-सामना हो गया और करीब 8.10 बजे गुड्डा पकड़ लिया गया।

गौरतलब है कि पहले पुलिस ने गुड्डा के छह सहयोगियों को दबोचा है। 3 नवंबर को नूराबाद पुलिस ने जरदान सिंह का पुरा सुरहेला, ग्वालियर निवासी रिंकू पुत्र बुलाखी गुर्जर और भूपेंद्र उर्फ रामसेवक पुत्र रामअवतार गुर्जर को पकड़ा जो गुड्डा गुर्जर का राशन लेकर जा रहे थे। 5 नवंबर को पहाड़गढ़ पुलिस ने रकेरा के जंगल में पूरन गुर्जर को पकड़ा। डकैत गुड्डा गुर्जर जब पकड़ा गया तो वह हाथ जोड़कर पुलिस के सामने खड़ा है, उसके चेहरे पर हंसी है। यह तस्वीर सामने आई है, जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वह स्ट्रेचर पर था। इस तस्वीर को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी चर्चा है कि गैंग से ही पुलिस को इनपुट मिला। ग्वालियर पुलिस ने गैंग से जुड़े एक सदस्य को तोड़ लिया था, जिससे उसका इनपुट मिल रहा था। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले के आधा दर्जन से ज्यादा थानों में गुड्डा गुर्जर पर 31 केस दर्ज हैं। इनमें 20 से ज्यादा केस मुरैना जिले के नूराबाद, बानमोर, सुमावली, पहाड़गढ़, निरार व जौरा थाने में दर्ज हैं। गुड्डा ने पहाड़गढ़ क्षेत्र की एक नाबालिग से विवाह करने के लिए नाबालिग के चाचा का अपहरण कर लिया था। एक साल में मुरैना पुलिस के साथ डकैत गुड्डा की आठ बार मुठभेड़ हुई पर भाग निकला। हत्या के दो मामलों में डकैत गुड्डा को आजीवन कारावास हो चुका है। गुड्डा पर ईनाम की राशि 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा था।

• बृजेश साहू

सरपंच से दुश्मनी पड़ी भारी, उसे सबक सिखाने आया था

डाडा खिरक के सरपंच राजेंद्र सिंह से गुड्डा गुर्जर की दुश्मनी थी। करीब 10 दिन पहले भी गुड्डा की गैंग का मूवमेंट यहां था, यहां उसने गांव के लोगों को पीटा था, रुपए छीन ले गया था। तभी से गांव वाले उसे सबक सिखाने की फिराक में थे। गांव का एक व्यक्ति उसका खास है, वही गुड्डा को पूरी मदद करता था। जैसे ही गुड्डा दोबारा यहां आया, उसकी सूचना दे दी गई। नूराबाद थाना क्षेत्र के लोहगढ़ गांव के निवासी डकैत गुड्डा गुर्जर ने साल 2001 में अपने ही गांव में पहली हत्या की थी। लोहगढ़ गांव के कुछ लोगों ने जमीनी विवाद में गुड्डा गुर्जर की बहन के साथ मारपीट कर दी थी और जमीन पर कब्जा कर लिया था, इसी विवाद में गुड्डा ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया।

पोषण से खाली थाली

भारत में निर्धारित मानकों का पालन नहीं

व्हाट इंडिया इट्स रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2.9 प्रतिशत भारतीय निर्धारित मानकों के अनुसार अनाज का, 7.2 प्रतिशत दालों का, 8.7 प्रतिशत दूध का, 8.8 प्रतिशत सब्जियों का, 15.9 प्रतिशत फलों और 97.4 प्रतिशत वसा का इस्तेमाल करते हैं। समग्रता में 90 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण भारतीय पूरा भोजन नहीं पाते हैं। शहरी भारत में लगभग 70 प्रतिशत लोगों की यही स्थिति है। क्या यह भूख की स्थिति नहीं है? वास्तव में इस बात के प्रमाण हमारे सामने लगातार आ रहे हैं कि भारत और पूरी दुनिया में भोजन में असंतुलित पोषण होने के कारण न केवल खाद्य और पोषण सुरक्षा का लक्ष्य दूर होता जा रहा है, बल्कि जाती और स्थाई बीमारियों का संकट भी अपने दायरे को बढ़ाता जा रहा है। अब बच्चों में तनाव-अवसाद, हृदय रोग, मधुमेह सरीखी बीमारियों का भी बहुत विस्तार हो रहा है। भारत में स्वास्थ्य और पोषण की नीति बनाने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि भारत के आर्थिक विकास का मतलब उपचार के बाजार को बढ़ाते जाना नहीं होना चाहिए, इसके उलट यह सुनिश्चित करना होगा कि गैर-संचारी बीमारियों को और ज्यादा फैलने से रोका जाए। वैश्विक भूख सूचकांक ने जो स्थितियां सामने दिखाई हैं, उन्हें खारिज करने का मतलब होगा भारत के लोगों को और ज्यादा कमजोर बनाना और गैर-संचारी बीमारियों के जाल में फंसने के लिए मजबूर करना।

भारत के सामने सबसे बड़ी बुनियादी चुनौती खाद्य और पोषण असुरक्षा की है। इस विषय को बहुत तार्किक ढंग से समझे जाने की जरूरत है। विश्व में भारत को मजबूत करने की शुरुआत देश को भीतर से मजबूत करने की पहल से होगी। भूख की स्थितियों को नकारने से भारत की गरिमा में कोई विस्तार न होगा। वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) यह नहीं कहता कि भारत भुखमरी की स्थिति में है। यह सूचकांक बताता है कि भारत खाद्य और पोषण सुरक्षा के मानकों पर अभी बहुत पीछे है और स्वस्थ समाज बनाने के लिए इसे भूख की स्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत ठोस और समुदाय केंद्रित पहल करने की जरूरत होगी। अक्टूबर 2022 में हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, गैलप और ग्लोबल अलायंस फार इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन (गेन) ने 41 देशों में भोजन गुणवत्ता सर्वेक्षण की रिपोर्ट-मेजरिंग व्हाट द वर्ल्ड इट्स जारी की। यह रिपोर्ट भूख के उस चित्र को उजागर करती है जो बाहर से नजर नहीं आता है। यही रिपोर्ट बताती है कि जब भोजन में विविधता नहीं होती है, तब गैर-संचारी रोगों (मधुमेह, रक्तचाप, आदि) का विस्तार भी होता है।

वैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत यह माना जाता है कि मानवीय भोजन को दस खाद्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये पांच व्यापक खाद्य समूहों में दस खाद्य वर्ग हैं- एक-अनाज (कार्बोहाइड्रेट), दो-दूध और दूध से बने पदार्थ, तीन-मांस, मछली और अंडे, चार-दालें, फलियां और तिलहन (प्रोटीन और विटामिन), पांच-आलू, शकरकंद और अन्य कंद, छः-फल, सात-हरी पत्तेदार सब्जियां, आठ-(अन्य सब्जियां), नौ-घी, तेल, मक्खन (वसा) और दस-गुड़-शक्कर (शर्करा); अगर समाज को स्वस्थ रखना हो तो यह अनिवार्य है कि इन दस समूहों में से कम से कम पांच समूहों (मुख्य रूप से अनाज, दालें, फल, सब्जियां, अंडे, तेल और वसा) का भोजन लोगों की थाली में हर रोज मौजूद होना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी ग्लोबल रिकमंडेशन्स फॉर हेल्दी डाइट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (2018) के मुताबिक एक व्यक्ति को 400 ग्राम फल और सब्जियां, भोजन में आधा हिस्सा अनाजों, दालों, बीजों-मेवों, कम से कम 25 ग्राम फाइबर हो, दैनिक ऊर्जा का 5 प्रतिशत से कम शक्कर से और 10 प्रतिशत से कम वसा से मिलना चाहिए। एक दिन में भोजन में 5 ग्राम से कम नमक और एक हफ्ते में 350 से 500 ग्राम से कम मांसाहारी उत्पाद शामिल होना चाहिए। आदर्श रूप में भोजन की थाली में 40-45 प्रतिशत ही अनाजों का होना बेहतर माना गया है। वर्तमान स्थितियों में भारत के लोगों के भोजन में दो तिहाई हिस्सा तक अनाजों का होता है और यह स्थाई गैर-संचारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन रहा है।

मेजरिंग व्हाट द वर्ल्ड इट्स अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां लोगों के भोजन में सबसे कम विविधता है। भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग (प्रजनन आयु वर्ग) की महिलाओं के समूह में केवल 41 प्रतिशत महिलाओं के दैनिक भोजन में न्यूनतम भोज्य विविधता (भोजन में 5 या 5 से ज्यादा खाद्य वर्गों का होना) मौजूद है। जबकि बांग्लादेश में 59 प्रतिशत, चीन में 86 प्रतिशत, नेपाल में 64 प्रतिशत, श्रीलंका में 82 प्रतिशत, केन्या में 69 प्रतिशत, नाइजीरिया में 48 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका में 72 प्रतिशत और पाकिस्तान में 54 प्रतिशत महिलाओं के भोजन में न्यूनतम विविधता उपलब्ध है। व्यापक समाज के स्तर पर सभी 5 खाद्य समूहों (फल, सब्जियां, दालें और बीज, पशुओं से प्राप्त उत्पाद और अनाज) का उपलब्ध होना समाज के स्वस्थ होने के लिए बेहद जरूरी होता है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत में केवल 28 प्रतिशत लोगों के दैनिक भोजन में सभी पांच व्यापक समूहों से संबंधित खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है। बांग्लादेश में 22 प्रतिशत, चीन में 54 प्रतिशत, नेपाल में 39 प्रतिशत, श्रीलंका में 58 प्रतिशत, केन्या में 38 प्रतिशत, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान में 23 प्रतिशत निवासियों के दैनिक भोजन में सभी पांच खाद्य समूह मौजूद होते हैं।

खाद्य और पोषण सुरक्षा के नजरिए से सब्जियों और फलों का उपभोग बहुत बुनियादी जरूरत के रूप में देखा जाता है। मानकों के मुताबिक 400 ग्राम सब्जियों और फलों का सेवन किया जाना चाहिए, लेकिन जिन 41 देशों का अध्ययन किया गया, उनमें आबादी का एक हिस्सा ऐसा भी है, जिसने अध्ययन के एक दिन पहले सब्जियों और फलों का बिलकुल सेवन नहीं किया था। भारत में सब्जियों और फलों का शून्य उपभोग करने वाले 22 प्रतिशत लोग थे, यह दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या है। अमेरिका में 6 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका में में 10 प्रतिशत, कीनिया में 7 प्रतिशत, बांग्लादेश में 14 प्रतिशत और पाकिस्तान में 13 प्रतिशत लोगों ने फलों और सब्जियों का सेवन नहीं किया था।

● **विकास दुबे**

केंद्र सरकार के संकटमोचक!

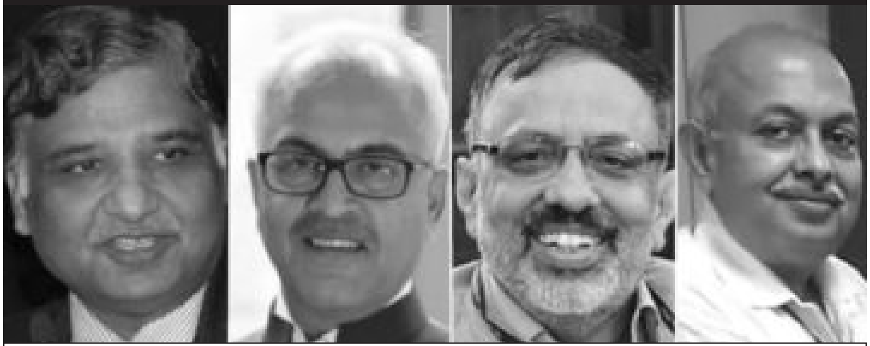

क्या इतना लंबा सेवा विस्तार देना सही है?

कैबिनेट सचिवालय से सेक्रेटरी सिक्योरिटी के पद से रिटायर हुए पूर्व आईपीएस एवं सीआईसी रहे यशोवर्धन आजाद कहते हैं, नियमों के मुताबिक एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। देश में ऐसा कौन सा आपातकाल है कि जिसके चलते सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का समय नहीं मिला। रिटायरमेंट पर बैठे किसी नौकरशाह को सेवा विस्तार देते हैं, तो उसकी जगह आने का इंतजार कर रहे व्यक्ति के हित प्रभावित होते हैं। ऐसे में कई लोगों की वरिष्ठता खत्म हो जाती है। ऐसे नौकरशाह, सरकार की ओर से मुआवजे के हकदार हैं। इनसे पहले रॉ चीफ रहे अनिल धस्माना और आईबी प्रमुख राजीव जैन को भी छह-छह माह का सेवा विस्तार दिया गया था। उसके बाद दोनों प्रमुखों को एक साथ ही एक-एक साल का एक्सटेंशन मिला था। बतौर आजाद, सरकार सेवा विस्तार किस लिए देती है। क्या उस नौकरशाह के जैसा कोई दूसरा अफसर देश में नहीं है। देश में ऐसी क्या स्थिति बनी है कि जिसमें सरकार के पास इस तरह की अहम पोस्टिंग करने के लिए समय ही नहीं है। कोई गंभीर खतरा है, लड़ाई चल रही है या कोई दूसरी विषम परिस्थिति है। ऐसा तो कुछ नहीं है। जब ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो एक्सटेंशन देने का औचित्य भी नहीं बनता। बतौर यशोवर्धन आजाद, जब किसी एक नौकरशाह को सेवा विस्तार मिलता है, तो उसकी वजह से किसी के हित तो प्रभावित होंगे ही, यह लाजिमी है। क्या राजनीतिक स्वार्थों के चलते एक्सटेंशन मिल रहा है।

केंद्र सरकार में चार टॉप नौकरशाह ऐसे हैं, जिन्हें बार-बार सेवा विस्तार मिल रहा है। मुसीबत के समय इन्हें सरकार का संकटमोचक माना जाता है। इनमें कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रॉ चीफ सामंत गोयल और ईडी निदेशक संजय मिश्रा शामिल हैं। गौबा को लगातार दूसरी बार एक वर्ष यानी 2023 तक सेवा विस्तार मिला है। अजय कुमार भल्ला को नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन अब उन्हें तीसरा सेवा विस्तार मिला है। वे 2023 तक केंद्रीय गृह सचिव बने रहेंगे। रॉ प्रमुख सामंत गोयल को पहले 2021 में एक वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद 2022 में भी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनका कार्यकाल एक साल यानी 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया है। इसके बाद नंबर आता है ईडी निदेशक संजय मिश्रा का। इन्हें नवंबर 2018 में दो वर्ष की अवधि के लिए जांच एजेंसी का प्रमुख बनाया गया था। अब इन्हें जो सेवा विस्तार मिला है, उसके तहत वे अगले वर्ष तक ईडी निदेशक बने रहेंगे।

राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव- झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह यानी कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। उसके बाद 2021 में राजीव गौबा को केंद्र सरकार ने एक साल का सेवा विस्तार दे दिया। अगस्त 2022 में उन्हें दोबारा से एक साल का सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार के कई फैसलों में गौबा की अहम भूमिका बताई जाती है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का मसौदा तैयार करने में कैबिनेट सचिव गौबा का प्रमुख रोल रहा था। इसी मसौदे के आधार पर केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था।

अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव- 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के असम-मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी अजय कुमार भल्ला को अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर भल्ला को नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में उन्हें एक साल का सेवा विस्तार देकर उनका कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया। इस साल अगस्त में उन्हें तीसरा सेवा विस्तार मिला। वे अगस्त 2023 तक केंद्रीय गृह सचिव के पद पर काम करते रहेंगे। भल्ला के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद की स्थिति, आतंकवाद से निपटना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की प्रभावी तैनाती और उत्तर पूर्व में सक्रिय रहे विभिन्न उग्रवादी समूहों से हथियार डलवा कर शांति समझौते कराना, उनके कार्यकाल की खास उपलब्धियां रही हैं।

सामंत गोयल, चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग- 1984 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी सामंत गोयल को 2019 में रॉ चीफ बनाया गया था। दो साल पूरे होने से पहले ही सामंत गोयल का कार्यकाल, एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद 2022 में भी कैबिनेट की **नियुक्ति समिति** ने सामंत गोयल का कार्यकाल एक साल यानी 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया है। गोयल को खुफिया मामलों का खास जानकार बताया जाता है। लंबे समय बाद रॉ में किसी चीफ को चार साल तक सेवा करने का अवसर मिला है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का विश्वस्त माना जाता है। गोयल ने पिछले दशक में कई अहम जिम्मेदारियों का निवर्हन किया था। रॉ के लंदन स्टेशन पर काम करना या पाकिस्तान के आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई, इनमें गोयल को खासी महारत हासिल रही है।

संजय मिश्रा, निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसके नाम से अब देश का सामान्य नागरिक भी परिचित है। विपक्षी दलों की ओर से जहां पहले सीबीआई का नाम लेकर केंद्र सरकार को घेरा जाता था, अब वह जगह काफी हद तक ईडी ने ले ली है। अब आए दिन विपक्षी नेताओं की जुबान पर ईडी का नाम रहता है। मौजूदा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा, आयकर कैडर के 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के अधिकारी हैं। उन्हें नवंबर 2018 में दो वर्ष की अवधि के लिए जांच एजेंसी का प्रमुख बनाया गया था। नवंबर 2020 में उन्हें एक साल का सेवा विस्तार मिल गया। भारत सरकार ने उनके नियुक्ति पत्र में संशोधन कर ईडी निदेशक के दो साल के कार्यकाल को बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया। 2021 में दोबारा से उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया। पिछले दिनों संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी अब वे नवंबर 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर बने रहेंगे।

● **सुनील सिंह**

मप्र में 700 से अधिक बाघ

टाइगर स्टेट कहलाने वाला मप्र बाघों की मौत के मामले में भी देश में नंबर 1 है। हालांकि पिछले 11 माह में 30 बाघों की मौत से संख्या में कमी आई है। यह बाघों को बचाने के बारे में मप्र के लिए अच्छी खबर है। मप्र ने वर्ष 2021 में जहां 42 बाघ खोए थे, वहीं इस साल 11 महीने में 30 बाघों की ही मौत हुई है। प्रदेश में बाघों की मौत के मामले में पार्क प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठते रहते हैं। वन्य प्राणी प्रेमी बाघों की मौत का कारण टाइगर रिजर्व में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को मानते हैं, जिनका वाइल्ड लाइफ प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है। वर्ष 2022 की बाघ गणना हो चुकी है। विभाग के अफसरों को भरोसा है कि जिस तरह से संजय टाइगर, सतपुड़ा, रातापानी, सतना जिला, बालाघाट आदि में बाघों की संख्या बढ़ी है, उससे कुल संख्या 700 से अधिक होगी।

जानकारों के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से उनमें टेरिटोरियल फाइट होती है। इसमें कमजोर बाघ घायल होकर या तो इलाका छोड़ देता है या मर जाता है। यह प्राकृतिक है। टेरिटोरियल फाइट रोकने के लिए सेंचुरी बनाकर नए इलाके की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। साल 2012 के बाद से भारत में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज करने वाले राज्य मप्र को अभी तक एक विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) नहीं मिला है। हालांकि 10 साल पहले केंद्र ने इस संबंध में सलाह दी थी। 2012 के बाद से देश में 1,059 बाघों की मौत हुई है। मप्र में सबसे अधिक बाघों की मौत हुई जिसे देश के 'बाघ राज्य' के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अनुसार मप्र में सबसे अधिक 270 मौतें दर्ज की गई हैं।

अवैध शिकार को रोकने के लिए डॉग स्क्वॉड 16 कर दिए हैं। इसे भी बढ़ाकर 18 तक ले जाने का प्लान है। वन्यप्राणी विभाग के अफसरों को उम्मीद है कि वर्ष 2022 की बाघ गणना रिपोर्ट में प्रदेश में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 700 तक हो सकती है। नेशनल टाइगर कंजरवेशन ऑथारिटी के आंकड़ों के अनुसार मप्र में पिछले साल यानि वर्ष 2021 में दिसंबर तक 42 छोटे-बड़े बाघों की मौत हुई थी। जबकि वर्ष 2022 में 19 नवंबर तक बाघों की मौतों की संख्या 30 है। वन्यप्राणी विभाग के अफसर कहते हैं कि दिसंबर माह में बाघों की मौत संख्या कम रहती है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल मई में सर्वाधिक 8 और इस वर्ष अप्रैल में 6 बाघों की मौतें हुई हैं। जहां तक अवैध शिकार की बात है तो पिछले 18 सालों में 48 बाघ शिकार हुआ और 35 की करंट से मौत हुई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अनुसार भारत ने 2012 के बाद से 1,059 बाघों को खो दिया। इस साल अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि मप्र में सबसे ज्यादा बाघों की मौतें हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 9 साल में 165 बाघों का शिकार हुआ। वन्यप्राणी विभाग का प्लान है कि सभी टाइगर रिजर्व में डॉग स्क्वॉड का विस्तार किया जा रहा है। अभी 16 डॉग स्क्वॉड हैं। दो और स्क्वॉड बढ़ाए जाना है। इसके साथ ही विभाग के एसटीएसएफ को और सशक्त किया जा रहा है। इनके साधनों में बढ़ोत्तरी की जा रही है। खुफिया तंत्र को भी और बढ़ाया जा रहा है। अवैध शिकार को रोकने के लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का विश्वास बढ़ाया जा रहा है। पीसीसीएफ वन्यप्राणी जेएस चौहान का कहना है कि पिछले 11 माह में प्रदेश में बाघों की मौतों में कमी आई है। इसके लिए हमने इन्वेस्टीगेशन सिस्टम को मजबूत किया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भरोसे पर लेकर शिकारियों पर नजर रखी है। खुफिया तंत्र को और मजबूत किया। जहां तक मृत्युदर में देश में आगे रहने की बात है तो प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं इसलिए आपसी संघर्ष की घटनाएं होती हैं।

साल 2012 के बाद से भारत में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज करने वाले राज्य मप्र को अभी तक एक विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) नहीं मिला है। हालांकि 10 साल पहले केंद्र ने इस संबंध में सलाह दी थी। 2012 के बाद से देश में 1,059 बाघों की मौत हुई है। मप्र में सबसे अधिक बाघों की मौत हुई जिसे देश के 'बाघ राज्य' के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अनुसार मप्र में सबसे अधिक 270 मौतें दर्ज की गई हैं। 2018 बाघ जनगणना में राज्य 526 बाघों के साथ भारत के 'बाघ राज्य' के रूप में उभरा था, इसके बाद कर्नाटक में 524 बाघ थे। 6 टाइगर रिजर्व वाले मप्र में इस साल अब तक 27 बाघों की मौत हो चुकी है। पिछले साल इसने 41 धारीदार फेलिन खो दिए। एनटीसीए ने 2009-10 में महत्वपूर्ण बाघ राज्यों को बाघों की सुरक्षा के लिए जंगलों में गश्त के लिए विशेष पुलिस कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण की सलाह दी थी।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

टाइगर स्टेट में सबसे ज्यादा बाघों की मौत!

प्रदेश के वन मंडल में लगातार हो रही बाघों की मौत के बाद वन विभाग कठघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर बीते सालों में बाघों की मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो गत 6 सालों में 175 बाघों की मौत हो चुकी है। वहीं इस साल जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 तक मप्र में 27 बाघों की मौत दर्ज की गई है जो कि देश में सबसे ज्यादा है। वहीं पेंच से पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत हुई थी। अगर मप्र में बाघों की मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो मप्र में 2021 में 44, 2020 में 30, 2019 में 29, 2018 में 19, 2017 में 27 और 2016 में 34 बाघों की मौत हुई थी। प्रदेश के 7 वन मंडल में ही 80 बाघों की मृत्यु हुई, जिसमें 16 का शिकार किया गया है। ऐसे 16 बाघों के शव मिले हैं जिनकी मौत बिजली के करंट से हुई है। प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की मौत में सबसे आश्चर्यजनक पहलु यह है कि नेशनल पार्क में रहने वाले बाघ भी सुरक्षित नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाघों की सबसे ज्यादा मौतें टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 30 और बांधवगढ़ में 25 मारे गए थे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 में 15 जुलाई तक 74 बाघों की मौत हुई जिसमें 27 बाघ मप्र के थे। वहीं वन्य प्राणी सरंक्षण को लेकर कैग ने रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2014 से 2018 के बीच 115 बाघों की मृत्यु हुई।

केन-बेतवा लिंक परियोजना पकड़ेगी रफ्तार

मप्र और उप्र की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना के कामों को शिवराज सरकार गति देगी। 4 हजार हेक्टेयर राजस्व भूमि इसी सप्ताह वन विभाग को हस्तांतरित करने की तैयारी है। भू-अर्जन के लिए भी प्रस्ताव तैयार हो चुका है। भोपाल में प्राधिकरण का कार्यालय भी स्थापित हो गया है, जो जल्द ही विधिवत कार्य प्रारंभ कर देगा। उधर, राज्य सरकार ने केंद्र से 31 अगस्त 2022 तक परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पर व्यय किए जा चुके एक हजार 175 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति करने की मांग की है। वहीं, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि आगामी केंद्रीय बजट में परियोजना के लिए ढाई हजार करोड़ रुपए का प्रविधान किया जाए।

केन-बेतवा लिंक परियोजना से मप्र और उप्र के 9 लाख 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 41 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। 45 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रभावित क्षेत्र के बदले में कोर एरिया को विस्तार दिया जाना है। इसके लिए राजस्व विभाग की भूमि वन विभाग को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की जा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन ने शासकीय और निजी भूमि चिन्हित कर ली है। लगभग 4 हजार हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जाना है। यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। पार्क से लगे पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के लोगों को विस्थापित किया जाना है, जिससे परियोजना के कामों को गति दी जा सके। इसके लिए सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है। बांध निर्माण से लेकर परियोजना से जुड़े अन्य कार्यों के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का कार्यालय भी भोपाल में स्थापित हो गया है। यह जल्द ही विधिवत कार्य प्रारंभ कर देगा। छतरपुर में भी कार्यालय खोला जाएगा। वहीं, बांध निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने की तैयारी की जा रही है। केन-बेतवा लिंक परियोजना से दोनों राज्यों में 9 लाख 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होना है। प्रदेश में सिंचाई के लिए विभाग कार्ययोजना तैयार कर रहा है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति की बैठकें हो रही हैं। सलाहकार कंपनी भी नियुक्त की गई है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के कार्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उधर, प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी) के लिए 1 हजार 706 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। इससे प्रदेश में 62 हजार 135 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। वहीं, वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व बैठक में योजना के लिए 1 हजार 23 करोड़ रुपए के केंद्रांश का प्रविधान करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि शिवराज सरकार ने प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। अभी 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है।

मप्र और उप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत छतरपुर जिले में प्रस्तावित ढोढन बांध निर्माण के लिए जल्द ही निविदा (टेंडर) निकाली जा सकती है। केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण इसकी शर्तें तय कर रहा है। वहीं छतरपुर और पन्ना जिला प्रशासन उन 21 गांवों की संपत्ति का सर्वे करवा रहा है, जिन्हें विस्थापित कर पन्ना टाइगर रिजर्व के विकास के लिए भूमि दी जानी है। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा के कारण इस काम में देरी हुई है। अब वर्षा का दौर थम रहा है। ऐसे में सर्वे को गति देने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी जल्द ही छतरपुर पहुंचेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना जल्द साकार होने की उम्मीद बंधी है। भोपाल में खोला जा रहा प्राधिकरण का कार्यालय इस माह के अंत तक काम शुरू कर देगा। इसके बाद परियोजना से संबंधित छोटे कामों के लिए अधिकारियों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। भोपाल में ही बैठकें होंगी, निर्णय लिए जाएंगे और यहीं से परियोजना के कामों की निगरानी होगी। अधिकारी बताते हैं कि जल्द ही निविदा जारी की जा सकती है। परियोजना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी-2022 में 39 हजार 317 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें से 1400 करोड़ रुपए मप्र को दे दिए हैं। जिससे सर्वे सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं।

छतरपुर में बारिश का सीजन खत्म होते ही केन-बेतवा लिंक परियोजना के काम में तेजी शुरू हो गई है। अगले सप्ताह से मुख्य बांध ढोढन के प्रभावित 10 गांवों की संपत्ति का फाइनल सर्वे शुरू होने जा रहा है। केन नदी को बेतवा से जोड़ने के लिए ढोढन में बनाए जा रहे मुख्य बांध के डूब क्षेत्र में 10 गांव आ रहे हैं। परियोजना के मुख्य बांध से बिजावर तहसील इलाके के बसौदा, भरकुआं, ढोढन, घौरारी, खरयानी, कुपी, मैनारी, पलकोंहा, शाहपुरा और सुकवांहा गांव के 1913 घर और 8 हजार 339 लोग बांध से प्रभावित होंगे। वहीं बांध बन जाने से 6 जिलों छतरपुर, पन्ना, झांसी, महोबा, टीकमगढ़, बांदा के 62 गांव के 2480 किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।

• सिद्धार्थ पांडे

बांध में पार्क बना अड़चन

बांध के निर्माण में पन्ना टाइगर रिजर्व बड़ी अड़चन है। जहां से वन्यप्राणियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए पार्क से सटे गांव खाली कराए जाने हैं। इसी का सर्वे कराया जा रहा है। इसमें गांव के प्रत्येक रहवासी की कृषि भूमि, आवासीय भूमि सहित अचल संपत्ति का आंकलन हो रहा है। यह काम पूरा होने के बाद लेंड ट्रांसफर (राजस्व से वनभूमि में परिवर्तित) की जाएगी। आगे की कार्रवाई उसके बाद ही शुरू होगी। 10 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। इनमें छतरपुर जिले के ढोढन, खरियानी, भोरखुआं, पलकौहां, सुकवाहा, कुपी, नैगुवां, शाहपुरा, मैनारी, पाठापुर शामिल हैं। सरकार इन गांवों की भूमि अधिग्रहित करेगी। डूब क्षेत्र के बाहर रहने वाले 11 गांवों में पार्क के कोर एरिया का विस्तार किया जाएगा। पार्क की 6 हजार 17 हेक्टेयर भूमि डूब रही है। इसमें से 4141 हेक्टेयर भूमि कोर एरिया की है। इसकी भरपाई छतरपुर और पन्ना जिले के गांव कोनी, मरहा, पाठापुर, कटहरी-बिल्हारा, मझौली, कोनी, गहदरा, खमरी, कूड़न, नैगुवां, डुंगरिया, घुघरी, बसुधा, कदवारा का विस्थापन होगा। इन गांवों की 4396 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।

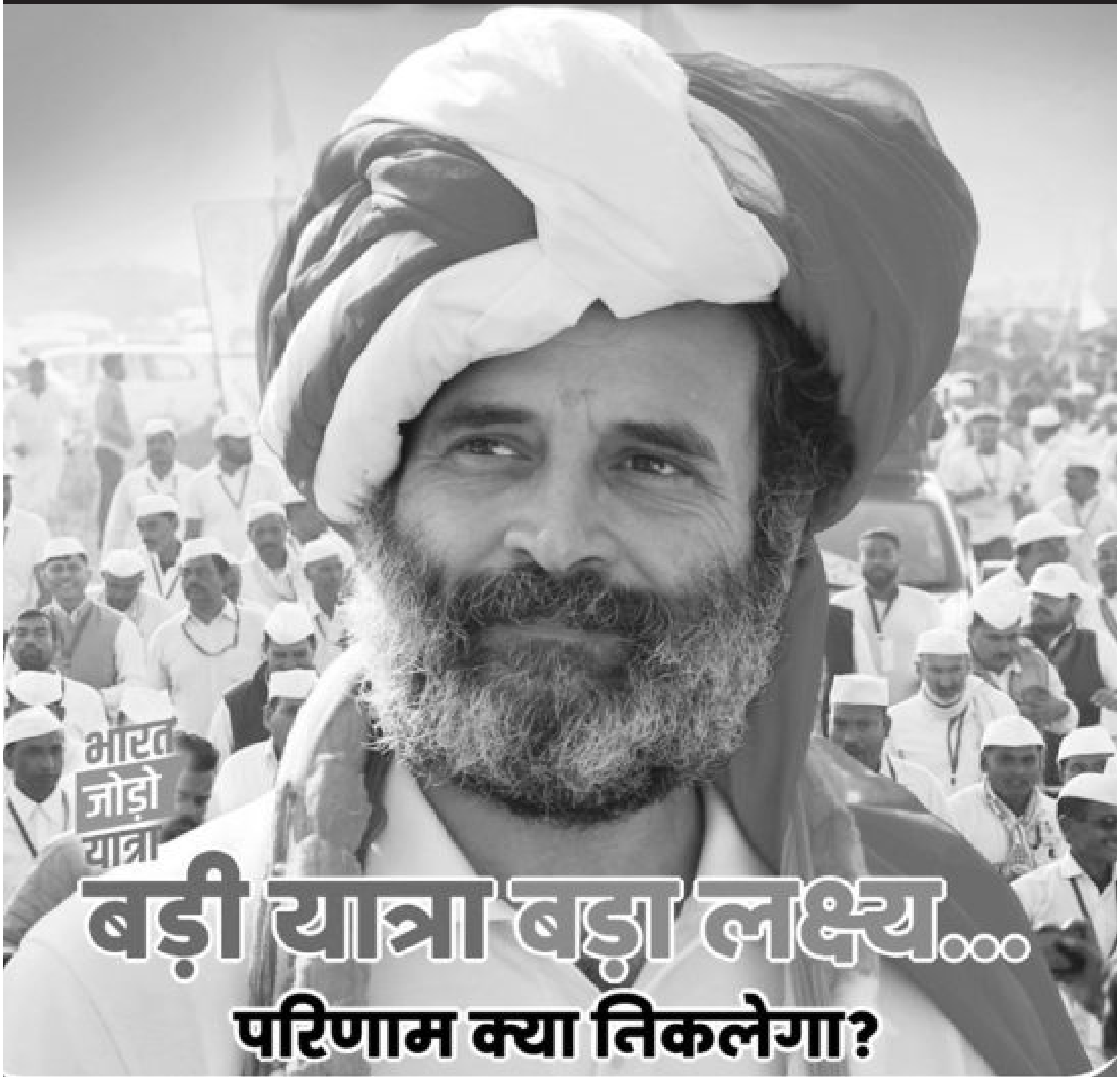

बड़ी यात्रा बड़ा लक्ष्य...
परिणाम क्या निकलेगा?

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू होकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से होकर अब मप्र की धरती पर पांव रख चुकी है। इस यात्रा में जैसे हर प्रदेश के अलग-अलग रंगों, विविध लोगों-लोकाचार को अपने में समाहित करने का जोश दिलचस्पी जगाता है। यह यात्रा अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक यात्रा है, तो इसका लक्ष्य भी बड़ा है। इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के अभेद गढ़ कहे जाने वाले मालवा-निमाड़ क्षेत्र में चल रही है।

● **राजेंद्र आगाल**

ख्यातनाम शायर मजरूह सुल्तानपुरी का यह शेर... मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया... राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सटीक बैठ रहा है। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें और यात्रा को ऐतिहासिक जनसमर्थन मिल पाएगा। राहुल गांधी तो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा मिले अपरिपक्व नेता के दाग को धोने और भारत को समझने निकले थे, लेकिन इस यात्रा ने राजनीतिक रूप ले लिया है और अभी तक 7 राज्यों में बिना बुलाए जिस तरह यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी है, उससे कांग्रेस को **संजीवनी** मिलती दिख रही है। यानी राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के लिए मैदान तैयार कर दिया है, बस जरूरत है समय पर रणनीति बनाकर दमदार मोहरे बिठाने की।

भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कांग्रेस की फिर से जीवित होने के आसार नजर आने लगे हैं। वे बार–बार यह भी बता रहे हैं कि आज देश में विपक्ष के पास अपनी बात कहने की कोई जगह नहीं बची है। मीडिया में आपकी बात आ नहीं सकती। संसद में आप सवाल करना चाहोगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे। संवैधानिक संस्थाओं में आपकी बात सुनी नहीं जाएगी तो अपनी बात पहुंचाने का सड़क ही एक जरिया बचता है। और सड़क पर भी लंबी पैदल यात्रा से बढ़कर कोई असरकारी उपाय नहीं है, जो लोगों को सीधे छुए, उनसे संवाद स्थापित करे, उनकी भावनाओं, उनके दुख–सुख को समझे और उसके अनुसार अपनी राजनीति में तब्दीली करे, बशर्ते ऐसी मंशा हो। पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर नया जोश ही नहीं फूंक रहे हैं बल्कि सियासी समीकरण को भी साधने की कवायद कर रहे हैं। युवाओं, कर्मचारियों, किसानों और कामगारों के साथ संवाद करने के बाद अब राहुल की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइलेंट वोटर पर है। साइलेंट वोटर की सियासी ताकत को देखते हुए कांग्रेस भी महिलाओं को साधे रखने की कवायद में है। लेकिन क्या कांग्रेस इस बड़े लक्ष्य वाली बड़ी यात्रा में जुटने वाली भीड़ को वोट में बदल पाएगी?

विरासत बचाने की चुनौती

आजाद भारत में पहली बार गांधी–नेहरू परिवार की विरासत को संभालने वाला कोई नेता सड़क पर है, जो सीधे जनता से संवाद बना रहा है, जिसने अपने इर्द–गिर्द के आवरण को हटा दिया है, जिसने अपनी चकाचौंध और परिवार की ताकत को दरकिनार कर दिया है। कोई बिचौलिया नहीं। कोई सलाहकार नहीं। राहुल गांधी के निशाने पर सत्तापक्ष भी है और विपक्ष भी। क्षत्रप भी हैं और खुद को राष्ट्रीय नेता मानने वाले मुख्यमंत्री भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा भी निशाने पर है और वामपंथियों की सियासत भी निशाने पर है। नफरत के माहौल में बंटते–टूटते समाज को जोड़ने की कवायद करती यह पदयात्रा कितनी राजनीतिक है? या क्या यह पदयात्रा समाज को संघर्ष करने के लिए तैयार करती है, ताकि जनता खुद तय करे कि वह कैसी राजनीति चाहती है? क्या राहुल गांधी किसी संत की भूमिका में कांग्रेस का राहुलीकरण चाहते हैं? क्या इसीलिए वे मौजूदा कांग्रेस की राजनीति से दूर हैं? चूंकि उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेसियों

ये यात्रा का चुनावी हिस्सा है

निश्चित तौर पर मप्र विधानसभा चुनाव में पिछली बार की ही तरह दिग्विजय सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन दारोमदार तो कमलनाथ पर ही होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से चले जाने और दिग्विजय सिंह के लगभग दिल्ली अटैच हो जाने के बाद कमलनाथ को तो खुला मैदान ही मिल गया है। 2020 में मप्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त कमलनाथ के एक बयान ने सत्ता के गलियारों में सबका ध्यान खींचा था, आज के बाद कल, और कल के बाद परसों भी आता है... कल तो कब का बीत चुका है, राहुल गांधी की नजर अब परसों पर ही टिकी लगती है। कांग्रेस नेताओं की पूरी कोशिश लगती है कि राहुल गांधी एक बार फिर 2018 जैसा ही चमत्कार दिखा दें, तभी तो दक्षिण भारत के बाद भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा तामझाम मप्र की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। मप्र में राहुल गांधी यात्रा के आधे रास्ते तय कर लेने के बाद दाखिल हुए हैं। ये यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 150 दिन बाद कश्मीर जाकर समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा मप्र के मालवा–निमाड़ क्षेत्र के 6 जिलों में आने वाली 17 विधानसभाओं से गुजर रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर का दर्शन भी करने वाले हैं और 26 नवंबर को अंबेडकर की जन्मस्थली महू में राहुल गांधी के रैली भी करने वाले हैं। ये इलाका कांग्रेस के लिए खास मायने रखता है क्योंकि यहीं पर मप्र की 66 विधानसभा सीटें हैं और खास बात ये है कि 2018 में कांग्रेस ने आधे से भी ज्यादा 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में भाजपा इलाके की 29 विधानसभा सीटें ही जीत पाई थी।

अब तक का सफर...

महाराष्ट्र

तेलंगाना

आंध्रप्रदेश

कर्नाटक

केरल

तमिलनाडु

साइलेंट वोटर पर फोकस

पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर नया जोश ही नहीं फूंक रहे हैं बल्कि सियासी समीकरण को भी साधने की कवायद कर रहे हैं। युवाओं, कर्मचारियों, किसानों और कामगारों के साथ संवाद करने के बाद अब राहुल की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइलेंट वोटर पर है। साइलेंट वोटर की सियासी ताकत को देखते हुए कांग्रेस भी महिलाओं को साधे रखने की कवायद में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश में 43.8 करोड़ महिला मतदाताएं थीं, जो अब बढ़कर 46.1 करोड़ हो गई हैं। महिला मतदाताओं की भूमिका चुनावों में हमेशा खास रही है। इसलिए भाजपा भी इन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी महिलाओं को साथ पदयात्रा कर आधी आबादी के बीच अपनी पैठ को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस महिलाओं के बीच अपनी पैठ इसीलिए भी गहरी करना चाहती हैं, क्योंकि देश में अब महिलाएं अपने मत का प्रयोग चुनावों के दौरान बढ़-चढ़कर कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बंगाल, बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, केरल और अरुणाचल प्रदेश के चुनावों पर ध्यान दें, तो पाएंगे कि यहां महिला मतदाताओं की संख्या, पुरुष मतदाताओं से अधिक रहती है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है और 68 में से 42 सीटों पर महिलाओं ने पुरुष के ज्यादा वोटिंग की है।

के भ्रष्टाचार को और सत्ता में रहकर कांग्रेसियों के अहंकार को भी समझ लिया है? क्या इसीलिए चुनाव-दर-चुनाव गोते लगाती कांग्रेस को संभालने से उन्होंने इनकार किया और भारत जोड़ो यात्रा की राह पकड़ना ही सही समझा क्योंकि चुनावी जीत के लिए वे कांग्रेस का भाजपाकरण या खुद का मोदीकरण नहीं करना चाहते? या राहुल गांधी पारंपरिक राजनीति के समानांतर एक नई राजनीति तैयार करना चाहते हैं क्योंकि देश की संवैधानिक तथा स्वायत्त संस्थाएं अगर सत्ता का हथियार बन चुकी हैं तो चुनाव कोई लड़े, जीत मोदी सत्ता की ही होगी? विपक्ष के विरोध के स्वर की कोई जगह मीडिया में नहीं है। कांग्रेस बतौर विपक्ष क्या करे? फिर रास्ता बदलना होगा। क्या पदयात्रा जनता का राजनीतिकरण कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को लीडर, काडर और आइडियोलॉजी तीनों दे दिया है? क्या राहुल की पदयात्रा सफल हो चुकी है? यह भाजपा या मोदी की सत्ता के लिए खतरे की घंटी है? राहुल जिस धागे में देश पिरो रहे हैं, यह धागा भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से उपजे सवालों से बना है।

रोज नया जोश

राहुल गांधी तकरीबन 83 दिनों से यात्रा कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने अब तक की यात्रा में चेहरे पर शिकन नहीं आने दी है। वह हर दिन औसत 30 किमी चल रहे हैं, फिर भी तरोताजा दिखते हैं। इसे आत्म-अनुशासन, लक्ष्य के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया जा सकता है। उनके समर्थकों के अंदर उनका सम्मान भी बढ़ा होगा। अभी तक जिन राज्यों में वह गए, वहां अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस कम से कम उन इलाकों में एकजुट रही, जहां से वह गुजरे। आम नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अपने नेता को निकट से गुजरते देख सुखद अहसास हुआ होगा। इन सबके अंदर उत्साह और स्फूर्ति उत्पन्न हुई होगी। भाजपा, संघ और नरेंद्र मोदी के विरोधियों को भी लगा होगा कि कांग्रेस में अभी उम्मीद बाकी है। लंबे समय बाद कांग्रेस अपने दृष्टिकोण से कोई व्यवस्थित कार्यक्रम कर पा रही है। यात्रा को डिजिटल और इंटरनेट मीडिया विभाग बिल्कुल सधे हुए तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। शब्दों के संयोजन, गाने, संगीत, तस्वीरें और वीडियो सबके पीछे पेशेवर तैयारी साफ दिखती है। कह सकते हैं कि गांधी परिवार के सलाहकारों और रणनीतिकारों ने यात्रा की प्रभावी प्रस्तुति के लिए कड़ा परिश्रम किया है। यात्रा के रास्ते के चयन में भी सतर्कता बढ़ती गई और रास्ते में कौन लोग राहुल गांधी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, चलेंगे उन सबका चयन पहले से किया जाता है। अगर इन सबसे राहुल की छवि बदल जाए या वह स्वयं में बदलाव कर लें तो कांग्रेस के पुनर्जीवन की संभावना बन सकती है।

लक्ष्य मिशन 2024

हालांकि यात्रा के योजनाकारों की दृष्टि 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में चमत्कार करने की है। यात्रा की दो-तिहाई दूरी की समाप्ति के बाद कहीं भी कांग्रेस के पक्ष में जनसमर्थन के व्यापक विस्तार का संकेत नहीं मिला है। केरल में उनके निकलने के बाद अंतर्कलह सतह पर आ गई। तमिलनाडु में आपसी संघर्ष इतना बढ़ा कि नेताओं का एक समूह दिल्ली आकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिला। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी शिवकुमार के बीच जो शांति-सुलह दिख रही है, वह कब तक कायम रहेगी, कहना मुश्किल है। वहां विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष होना है। इस यात्रा में राहुल गांधी ने मुख्यत: भाजपा, संघ, हिंदुत्व विचारधारा और नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक को छोड़कर भाजपा अभी शक्तिशाली नहीं है। वह तेलंगाना और तमिलनाडु में अवश्य कोशिश कर रही है। उसमें भी उन्होंने भाजपा और संघ के विरूद्ध वही बातें कहीं, जो पहले से बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में वीर सावरकर की निंदा कर राहुल ने अपने राजनीतिक साझेदारों शिवसेना (उद्धव गुट) एवं राकांपा को भी असमंजस में डाल दिया। यात्रा के आरंभ से ही दिख रहा था कि इसके पीछे उन सभी गैर-दलीय समूहों का सोच और ताकत है जो मोदी सरकार के विरूद्ध देशव्यापी वातावरण बनाकर 2024 में उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का सपना संजोए हुए हैं। एनजीओ, एक्टिविस्ट, थिंक टैंक सर्वे संस्थाएं आदि इसमें शामिल हैं। इनका संघ, भाजपा और मोदी विरोध पहले से जाहिर है और पूरी क्षमता लगाकर भी ये भाजपा की चुनावी संभावनाओं को अभी तक खत्म नहीं कर सके हैं। राहुल गांधी का इनके साथ कदमताल करना ही बताता है कि कांग्रेस भारत की बदली हुई राजनीति और जनता के बदले मनोविज्ञान को समझ नहीं पा रही है। वैसे भी अगर संगठन नहीं हो तो यात्रा से जो भी थोड़ा बहुत माहौल बनेगा, उसे सशक्त कर चुनावी लाभ में बदला नहीं जा सकता। यात्रा के उपरांत की योजना कांग्रेस के पास नहीं है। अगर देशभर के संघ, भाजपा और मोदी विरोधी एनजीओ, एक्टिविस्ट मिलकर कोई आंदोलन कर भी लें तो इससे कांग्रेस को क्या लाभ होगा?

पार्टी के साथ परिवार भी एक

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मप्र पहुंचने के बाद भरी पूरी लगने लगी है। ऐसा हल्का एहसास कर्नाटक में भी हुआ था, जब सोनिया गांधी ने यात्रा में राहुल गांधी के साथ मार्च किया था, लेकिन तभी से हर निगाह प्रियंका गांधी वाड्रा को खोज रही थीं और आखिरकार इंतजार खत्म हुआ जब यात्रा की मप्र में एंट्री हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा के अब तक यात्रा से दूर रहने की वजह हिमाचल प्रदेश चुनाव में उनकी व्यस्तता बताई गई थी, जबकि खबर ये भी रही कि सोनिया गांधी के अगले ही दिन वो कर्नाटक में ही यात्रा में शामिल होने वाली थीं। वैसे मीडिया में जो कवरेज मप्र में मिला है, कर्नाटक में कहां संभव था। और प्रियंका गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा को छप्पर फाड़ समर्थन दिया है। राहुल गांधी के स्वागत में वो अकेले नहीं बल्कि पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान के साथ पहुंची हैं। हो सकता है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को मप्र में यात्रा के पड़ावों पर सोनिया गांधी की कमी खल रही हो, लेकिन एक साथ पूरे गांधी परिवार को देखने का मौका तो काफी देर बाद मिला है। पहले ऐसा नजारा अमेठी और रायबरेली में चुनावों के दौरान ही देखने को मिला करता रहा। हो सकता है प्रियंका गांधी के बाद ये रॉबर्ट वाड्रा को भी राजनीति में लाए जाने की रणनीति हो। वैसे भी रॉबर्ट वाड्रा तो राजनीति में आने को लेकर कई बार हड़बड़ी दिखा चुके हैं। वाड्रा परिवार के अलावा यात्रा में सचिन पायलट की मौजूदगी ने भी सबका ध्यान खींचा है, और उसकी चर्चा गुजरात चुनाव में व्यस्त अशोक गहलोत की राजनीति से जोड़कर होने लगी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ को तो शुभ मौके का इंतजार रहा ही होगा, दिग्विजय सिंह को बड़े दिनों पर घर लौटना खुशगवार ही लगा होगा। मौजूदगी तो कन्हैया कुमार ने भी दर्ज कराई है, जिनके बारे में यात्रा के प्रचार-प्रसार का काम देख रहे जयराम रमेश कह चुके हैं कि राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय कन्हैया कुमार ही पूरे यात्रा में नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार की काफी डिमांड बताई जा रही है।

मप्र में भीड़ देख गदगद

मप्र में कांग्रेसियों की भीड़ देखकर गदगद राहुल गांधी खुशी से उछल उठे। और कहने लगे कि मप्र ने पहले ही दिन महाराष्ट्र की यात्रा को हरा दिया। बोले- मैं मप्र के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को ए ग्रेड देता हूं... दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने यात्रा को ऑर्गनाइज किया, साथ दिया। यात्रा के पड़ावों पर राहुल गांधी बीच-बीच में छोटे-छोटे किस्से या लोगों से हुआ बातचीत के अंश भी सुनाते रहते हैं, कमलनाथ जी ने मुझसे कहा कि आप थकते नहीं हैं? मैंने कहा- 2 हजार किलोमीटर चला हूं पर थका नहीं... बिल्कुल थका नहीं। सुबह उठता हूं... छह बजे, जिस तेजी से चलता हूं, उससे ज्यादा स्पीड से रात आठ बजे चलता हूं... यात्रा में हम आठ घंटे चलते हैं। और न थकने का राज भी बताया, जिसमें निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम नजर आया। बोले, मैं ज्यादा टाइम चुप रहता हूं... मैं आपसे दो-तीन सवाल पूछता हूं, 15 से 20 मिनट बोलता हूं... मतलब, आठ घंटे आपके मन और 15 मिनट मेरे मन की बात चलती है।

भारत जोड़ो यात्रा का मकसद समझाने के लिए राहुल गांधी ने संघ और भाजपा को निशाना बनाया और ये भी समझाया कि मप्र में कांग्रेस की सरकार क्यों और कैसे गिर गई। ये बताने का अंदाज भी ऐसा रहा कि राहुल गांधी के निशाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नजर आ रहे थे। राहुल गांधी का कहना था कि मप्र में हम चुनाव जीत गए... करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे 20-25 विधायक खरीद लिए गए और सरकार बना ली... और फिर जो बातें कही, ऐसा लगा जैसे 2018 के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक रहे हों, हमने सड़क पर उतरकर यात्रा करने का फैसला किया... कुछ विधायकों को खरीदकर भाजपा ने गलतफहमी पाल ली कि हमें लोगों के दिलों से दूर कर दिया... रुपयों में ईमान बिकता होगा... प्यार और विश्वास नहीं... जनता खुद जवाब देगी।

5 साल बाद मैदान में सक्रिय

ठीक 5 साल बाद कांग्रेस मप्र के मैदान में वैसे ही एंट्री ले सकती है जैसे 2017 में ली थी। सत्ता विरोधी फैक्टर तो एक बार फिर भाजपा के खिलाफ काम करेगा। भाजपा में भी शिवराज सिंह चौहान के ही खिलाफ होगा। हो सकता है, भाजपा चुनावों से पहले उत्तराखंड, गुजरात और

सोच के साथ बदला नजरिया... एक यात्रा राहुल के अंदर भी

चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है... कांग्रेस के युवराज ने लगता है ये लय पकड़ ली है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में इंदौर आए राहुल जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने निसंकोच यह बात स्वीकार की कि उनकी सोच और नजरिया बदला है। अब वे खुद की तरफ नहीं, सामने वाले की ओर से देखते और सोचते हैं। अब उन्हें गालियों से भी फर्क नहीं पड़ता और अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह जनता से मिल रहे हैं और उनके प्यार से अभिभूत भी हैं। वहीं इसके साथ कई तरह की सीख और समझ भी उन्हें मिल रही है। यानी 3 हजार किलोमीटर से लंबी इस यात्रा के साथ-साथ राहुल के दिलो-दिमाग में भी एक यात्रा चल रही है। बेबाकी से राहुल इस बात को भी स्वीकारते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने का एक लंबा सिलसिला चलता आया है, जिस पर विपक्ष, खासकर भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं। मगर अब उन्हें धक्के खाने, गिरते-पड़ते और हर तरह की दिक्कतों का सामना करने की आदत हो गई है। वे मीडिया, खासकर गोदी पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूकते, लेकिन विवादित मुद्दों से अवश्य बच रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों वीर सावरकर पर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर भाजपा ने बवाल मचाया और महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान वहां पर कांग्रेस की सहयोगी रही शिवसेना को भी वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल के बयानों से किनारा करना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठों ने यह बात युवराज को समझाई कि वे भारत यात्रा का फोकस, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर जनता से जुड़े मुद्दों तक ही सीमित रखें।

त्रिपुरा जैसे प्रयोग मप्र में भी करे और शिवराज सिंह चौहान को बीएस येदियुरप्पा जैसी भूमिका में लाया जाए, बशर्ते मार्गदर्शक मंडल भेजने का अभी कोई इरादा न हो तो। मप्र में भाजपा की तरफ से एक दावेदार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे ही। हिमंत बिस्वा सरमा के मिसाल बनने के बाद सिंधिया को इतनी उम्मीद तो करनी ही चाहिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अंदर ही अंदर भले ही फैसला हो चुका था, लेकिन भाजपा ने हिमंत बिस्वा सरमा को असम का मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद ही बनाया था। सिंधिया भाजपा में मप्र के मुख्यमंत्री पद की रेस में हो या न हों, लेकिन कोई दो राय नहीं कि वो राहुल गांधी के दिमाग में नहीं होंगे और ये भी मानकर ही चलना चाहिए कि आने वाले 2028 के मप्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और उनकी टीम के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे।

अभी से तैयारी

जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मप्र में कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता बना सकती है। बुरहानपुर में प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर यात्रा की अगवानी की। इतना ही नहीं, राहुल को मालवा और निमाड़ की संस्कृति से अवगत कराने के लिए अलग-अलग रंग-रूप से स्वागत किया गया। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहती है, ताकि एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनकी जनता में पकड़ का आंकलन भी हो सके। इस लिहाज से ही नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। दक्षिण में राहुल गांधी की यात्रा को उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला है, क्योंकि 1984 के बाद कांग्रेस दक्षिण में खड़ी हो पाई। फिर भी देश की निगाहें हिंदी भाषी पट्टी से गुजरने वाली यात्रा पर है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस की शुरुआत हिंदी भाषी राज्यों से हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने आप को आंतरिक कलह से दूर नहीं कर पाई। मप्र में गुटबाजी हावी है। कमलनाथ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के बारे में तो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है राज्य और खासकर स्थानीय मामलों पर ध्यान देने की। इसके लिए नेता राज्य की परेशानियों के बारे में भी बताएं, ताकि जो लोग उनकी सभाओं में आ रहे हैं, वह सुनें और अपने आप को इस यात्रा से कनेक्ट कर पाएं। पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीट कांग्रेस को ज्यादा और भाजपा को कम मिली थीं। दरअसल, आदिवासियों को लेकर बातें ज्यादा हो रही हैं। यह वर्ग अब जागरूक हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आदिवासी नेतृत्व बिक जाता है या फिर लालच में आ जाता है। राहुल गांधी यात्रा के दौरान गरीब, किसान और निचले और उपेक्षित तबके की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रदेश के नेता प्रदेश के मुद्दों को सही दिशा में उठाने और ले जाने की कोशिश करेंगे तो असर जरूर पड़ेगा। कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी हो, गांधी परिवार सर्वमान्य नेतृत्व करने वाला परिवार है। यही वजह है कि भाजपा की कोशिश होगी कि मप्र में इस यात्रा को विवादित बनाया जाए। नारे वाले वीडियो को लेकर जिस प्रकार भाजपा ने हमला बोला, उससे ऐसा माना भी जा रहा है।

कांग्रेस को यात्रा से उम्मीद

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट में उन विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस कमजोर थी। यात्रा बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा सीट से शुरू हुई। नेपानगर विधानसभा सीट पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन सुमित्रा कास्डेकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई थीं और अब भाजपा से विधायक हैं। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस भले ही राहुल गांधी की इस यात्रा को राजनीति से अलग कर रही है। फिर भी इसका असर मप्र के विधानसभा चुनावों में देखने को जरूर मिलेगा। उनका कहना है कि जब सेंट्रल लेवल का एक बड़ा नेता सीधे जनता से मिलता है, तो इसका असर पड़ता है। इतिहास बताता है कि अभी तक देश में नेताओं ने जितनी भी यात्राएं की हैं, उनका फायदा जरूर हुआ है। मालवा-निमाड़ भाजपा का गढ़ कहा जाता है। यहां कुल 66 विधानसभा सीटें हैं। साल 2013 में भाजपा ने यहां 56 और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थीं। साल 2018 में भाजपा 29 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस ने 34 सीटें जीती थीं।

राहुल के दम पर 66 में से 35 सीटों को जीतने का टारगेट

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मप्र में चल रही है। यात्रा जहां से गुजर रही है राहुल गांधी को देखने भीड़ उमड़ रही है। इसको देखते हुए मप्र कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को भुनाने की रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी ने इस यात्रा के माध्यम से मालवा-निमाड़ की 66 में से कम से कम 35 विधानसभा सीटों को जीतने का टारगेट तय किया है। पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह लोगों का राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है उससे इस क्षेत्र में कांग्रेस जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। गौरतलब है कि मप्र में 23 नवंबर को बुरहानुपर से यात्रा की शुरुआत हुई है। ये यात्रा प्रदेश के मालवा-निमाड़ के 6 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। मालवा-निमाड़ में 66 विधानसभा सीटें हैं।

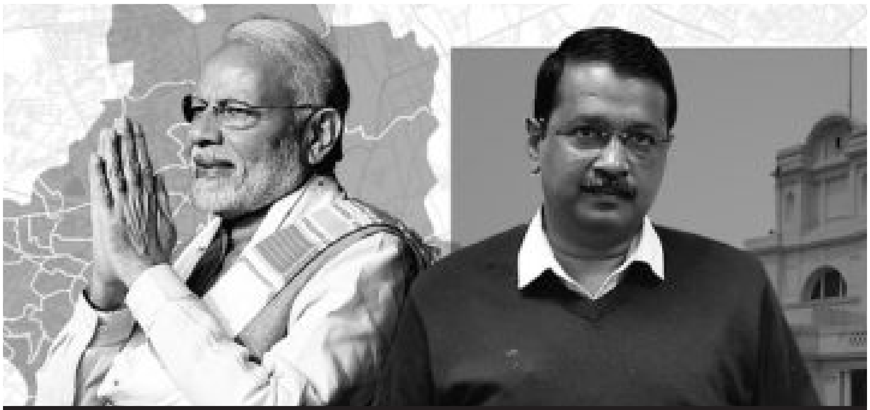

'छोटी सरकार' के लिए बड़ा दांव

क्या प्रभाव पड़ेगा भाजपा-आप की राजनीति पर?

दिल्ली निगम चुनाव में दोनों दलों की साख दांव पर लगी है। यदि भाजपा निगम चुनाव हार जाती है तो आप इसे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से जोड़ते हुए राष्ट्रीय मुद्दा बना देगी। वहीं आप की हार को भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जोड़ते हुए उनके मॉडल को छलावा साबित करेगी। कुल मिलाकर दोनों ही दलों के लिए निगम चुनाव नाक का सवाल बन गए हैं। आप जीती तो अरविंद केजरीवाल का कद राष्ट्रीय राजनीति में तो बढ़ेगा ही, दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में उसे लाभ मिलेगा। साथ ही, भाजपा के आरोपों से घिरी आप को संजीवनी मिल जाएगी। यदि भाजपा जीती तो आप के मॉडल को नकारकर वह देशभर में आप के विरुद्ध माहौल बनाएगी ताकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली तक सीमित किया जाए। 4 दिसंबर, 2022 का दिन दोनों राजनीतिक दलों के भविष्य के लिहाज से बड़ा होने वाला है क्योंकि इसी दिन दिल्ली की जनता अपने मताधिकार से छोटी सरकार का चयन करेगी।

दिसंबर में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव के शोर के बीच दिल्ली में छोटी सरकार का चुनाव राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। देश की राजधानी होने के चलते वैसे भी दिल्ली की राजनीति केंद्र में रहती है। बीते एक दशक से आम आदमी पार्टी ने भाजपा के गुजरात मॉडल की तर्ज पर दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को देशभर में प्रचारित कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है। जबकि दिल्ली नगर निगम में भाजपा पिछले 15 वर्षों से काबिज है।

चूंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव जनता की नब्ज पकड़कर राजधानी में सत्ता के मार्ग तक जाता है अत: आम आदमी पार्टी निगम में झाड़ू के जादू की आस में है तो भाजपा को मोदी मैजिक पर भरोसा है। हां, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी के पीछे पूरी कांग्रेस के जाने से दिल्ली में पार्टी की स्थिति अनाथ जैसी ही है। उसके बड़े नेता मैदान तो क्या मोहल्लों से भी नदारद हैं। ऐसे में इस बार निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों दिल्ली नगर निगम का चुनाव दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है? दिल्ली निगम चुनाव दोनों राजनीतिक दलों की भविष्य की राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगे?

दरअसल, दिल्ली नगर निगम चुनावों के महत्व का कारण इसका भारी-भरकम बजट है जो कई छोटे राज्यों के बजट से अधिक है। इस वर्ष के प्रारंभ में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एकीकृत कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ही आदेश पर दिल्ली नगर निगम के मौजूदा वार्डों का परिसीमन भी हुआ है। निगम के बजट की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू होती है किंतु तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद जुलाई में बजट पेश कर दिया गया था। बजट में 15,276 करोड़ रुपए के बजट अनुमान मंजूर किए गए थे जिसमें स्वच्छता के लिए 4,153 करोड़, शिक्षा के लिए 2,632.78 करोड़, सामान्य प्रशासन के लिए 3,225.35 करोड़, लोक निर्माण और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 1,732.15 करोड़ और सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत के लिए 1,570.25 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया।

निगम को 15 फरवरी, 2023 तक अगले वित्त वर्ष के लिए सभी कर तय करने हैं। हालांकि इस समय एकीकरण के बाद न तो सदन है, न ही स्थायी समिति। निगम की सभी शक्तियां विशेष अधिकारी के पास हैं। इस हिसाब से 1996 के बाद यह पहला मौका होगा जब पार्षदों के बिना ही बजट पेश कर दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के पास स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई, प्रॉपर्टी व प्रोफेशनल टैक्स कलेक्शन, श्मशान, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, ड्रेनेज सिस्टम, बाजारों की देख-रेख, पार्किंग, दिल्ली बार्डर पर टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम आदि की जिम्मेदारी है। प्राइमरी स्कूलों और अस्पतालों का कार्य भी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है। दिल्ली नगर निगम की आय का बड़ा स्रोत सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और टैक्स कलेक्शन से प्राप्त होता है।

हालांकि दिल्ली नगर निगम के पास ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें दिल्ली सरकार भी करती है। मसलन, सड़क और नाले की सफाई का काम दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों करवाते हैं किंतु इनके क्रियान्वयन में अंतर है। उदाहरण के लिए, दिल्ली सरकार 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों के मरम्मत का कार्य करती है जबकि इससे कम चौड़ी सड़कों का रखरखाव निगम द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वाहन लाइसेंस देने का कार्य भी दोनों करते हैं। दिल्ली सरकार मोटर वाहनों को लाइसेंस जारी करती है जबकि निगम छोटे वाहनों जैसे रिक्शा, हाथगाड़ी आदि को लाइसेंस देती है। जब दिल्ली के तीनों निगमों का एकीकरण किया गया था तो आप की ओर से यह दावा किया गया कि भाजपा को अपनी हार का डर सता रहा है इसलिए दिल्ली के निगमों को एक कर भाजपा मोदी मैजिक के सहारे पुन: निगम में काबिज होना चाहती है जबकि पिछले 15 वर्षों से भाजपा के राज में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ।

अभी एक माह पहले ही आप सरकार के मंत्रियों ने दिल्ली के चारों कोनों में कचरे के पहाड़ दिखाते हुए सफाई का मुद्दा उठाकर भाजपा को असहज कर दिया था तो भाजपा ने भी पलटवार करते हुए यमुना की सफाई का मुद्दा उठाकर आप को घेरा था। यह सही है कि भाजपा के विरुद्ध 15 वर्षों की एंटी-इनकम्बेंसी है पर आप को भी क्लीन चिट मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। भाजपा ने इस बार 4 मुस्लिम महिलाओं को टिकट देकर पसमांदा मुसलमानों को रिझाने का प्रयास किया है। वहीं जाति आधारित टिकट बांटकर वह सोशल इंजीनियरिंग के सहारे कदम बढ़ा रही है। आप में स्थिति थोड़ी अलग है। वहां विधायक गुलाब सिंह को आप कार्यकर्ताओं ने ही टिकट बेचने के आरोप लगाते हुए पीट दिया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। भाजपा ने आप से जुड़े कार्यकर्ताओं के कई स्टिंग किए हैं जिनमें टिकट बेचने की बात सामने आई है। हालांकि आप के नेता इसे नकारते हुए भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा जेल मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े विवाद राष्ट्रीय स्तर पर तो चर्चा में हैं ही, निगम चुनाव में भी आप की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।

● जय सिंह सेंधव

चेहरे बदल जाएंगे...!

> लोकसभा चुनाव में अभी भले ही डेढ़ साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी ताना-बाना बुना जाने लगा है। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बनने के लिए नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन बिखरे हुए विपक्ष की एकता का सूत्रधार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के केसीआर तक अपनी-अपनी कोशिशें कर रहे हैं तो कांग्रेस की भी अपनी दावेदारी है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलने के साथ ही अब विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है।

एनडीए से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए सबसे पहले दिल्ली आकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर पहला कदम उठाया। इन दोनों नेताओं के अतिरिक्त भी वह कई विपक्षी दलों के मुखिया से मिलकर उन्हें एकजुट करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में उनकी उपलब्धि क्या हुई है, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस प्रयास से विपक्षी एकता के लिए और एनडीए से आगामी चुनाव में दो-दो हाथ करने का विपक्षी दलों का मन बनता तो नजर आ रहा है।

कई विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार के इस प्रयास को सराहा भी है और कुछ के लिए वह आलोचना के पात्र बने हुए हैं। आलोचना तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हितकर है। इसमें नहले पर दहला यह हुआ कि कांग्रेस द्वारा अपने उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय के आधार पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया।

इस पदयात्रा को देखकर कहा जा रहा है कि यह सत्तारूढ़ दल के ऊपर कांग्रेस द्वारा गरम लोहे पर चोट देने जैसा है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल का अपने हाथ से सत्ता निकलने की संभावना देखकर बौखलाहट अनुचित नहीं है। राहुल गांधी का स्वागत जिस प्रकार दक्षिण भारत में किया जा रहा है और पदयात्रा में स्थानीय बच्चे, युवा और बुजुर्ग उन्हें गले लगा रहे हैं, इसमें लोगों का उत्साह तो कुछ और ही बेहतरीन संकेत दे रहे हैं। इसे देख उत्साहित जयराम रमेश कहते हैं कि अगर यह पदयात्रा (कन्याकुमारी से कश्मीर) सफल रही तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे।

भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में यह बात दर्ज है कि इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद हुए चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि, इंदिरा विरोधी नेताओं का यह गठजोड़ ज्यादा वक्त नहीं चल पाया और 1980 के चुनाव में उन्होंने मजबूती के साथ वापसी की। 23 मार्च, 1977 तक देश में आपातकाल चलता रहा। लोकनायक जेपी की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची और इंदिरा गांधी को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुए और कांग्रेस बुरी तरह हार गई। इंदिरा गांधी खुद राजनारायण से रायबरेली सीट से चुनाव हार गईं और कांग्रेस महज 153 सीटों पर सिमट गई।

23 मार्च, 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी भाई

विपक्ष को नेता की तलाश

भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनने की जंग है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और नीतीश कुमार तक कई नेता दावेदार हैं। विपक्षी दलों को ऐसे नेता की तलाश है, जिस पर सभी दल एकमत हो सकें। राहुल गांधी के नाम पर ममता, केजरीवाल और केसीआर तैयार नहीं हैं तो कांग्रेस भी इन तीनों में से किसी के नाम पर सहमत नहीं दिख रही है। अब बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एक करने की तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक नीतीश के नाम पर रजामंद हैं तो केसीआर भी साथ खड़े हैं। देवगौड़ा ने भी हरी झंडी दे दी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की ओर से एक मजबूत नेता की जो तलाश की जा रही है, उसकी भरपाई नीतीश कुमार के रूप में हो सकती है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनाने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर विपक्ष के ज्यादातर दल सहमत हो सकते हैं। नीतीश कुमार के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। नीतीश बिहार में 15 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नीतीश साफ-सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं, इस बात को भाजपा के नेता भी मानते हैं।

देसाई प्रधानमंत्री बने। यह आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार में जल्द ही उथल-पुथल मच गई और जनता पार्टी बिखर गई। इसके कारण जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी में बिखराव के बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विजय पताका लहराई। इंदिरा को आपातकाल के बाद जो झटका लगा था, उससे कहीं ज्यादा जनसमर्थन उन्हें इस चुनाव में हासिल हुआ। कांग्रेस ने इस चुनाव में 43 प्रतिशत वोट के साथ 353 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। जबकि जनता पार्टी और जनता पार्टी सेक्युलर 31 और 41 सीटों पर ही सिमट गईं।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी पराजय के बाद इस तरह निराश हुई कि उसके बाद लगभग जितने भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव हुए, हारती चली गई। उस पर भाजपा के आक्रामक रुख से यही अनुमान लगाया जाने लगा कि अब यह सरकार भारतीय जनता को काफी कुछ देने वाली है। जनता संतुष्ट होती गई और **सतारूढ़ दल अहंकारी** होता गया। जनता पार्टी भी जब 1977 में चुनाव जीतकर आई थी तो वह काल आज भी याद है। तब कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी और जनता पार्टी की सरकार से जुड़े लोग आम जनता पर इतने आक्रामक हो गए थे कि सामान्य जनता ने चार वर्ष चली उस जनता पार्टी की सरकार को 1980 में बुरी तरह हरा दिया। कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं।

आज तक अपने 8 वर्षीय कार्यकाल में एनडीए की सरकार ने कथित रूप से विकास तो किया, लेकिन जनता के प्रति नकारात्मक ही रही। इसलिए आज तमाम उपलब्धियों के बावजूद एनडीए को घोर असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके कई कारणों में बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख है, जो विकराल रूप धारण कर चुकी है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस द्वारा 'भारत जोड़ो यात्रा' ने प्रमाणित कर दिया है कि भाजपा या एनडीए के लिए निकट भविष्य में होने वाले चुनाव जीतना आसान नहीं होगा और यह भी हो सकता है कि यदि विपक्षी दल एकजुट हो गए तो कोई शक नहीं कि भाजपा को नाकों चने चबाने वाली स्थिति का सामना करना पड़ जाए। भाजपा का अहंकार यह हो गया कि सत्ता में आते ही उसने देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के लिए 'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा दिया और अभी हाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दंभ कि भाजपा राज्य स्तरीय सभी दलों को समाप्त कर देगी, का अच्छा संदेश आम जनता में नहीं गया। जनता यह भी आरोप लगा रही है कि अपने

तीसरे फ्रंट को भी एकजुट कर सकते हैं नीतीश

कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी एकजुटता होती नहीं दिख रही है। यह बात उपराष्ट्रपति के चुनाव में साफ हो चुकी है। ममता से लेकर मायावती, चंद्रबाबू नायडू तक साथ नहीं आए थे। 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की जिस तरह की क्षत्रपों द्वारा कोशिशें हो रही हैं, उसमें कांग्रेस को माइनेस रखा जा रहा है। इस तरह तीसरे मोर्चे की कवायद की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। नीतीश गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेसी सभी दलों को एक साथ लाने के मिशन पर हैं। इसी कड़ी में लेफ्ट पार्टियों से लेकर केजरीवाल तक से वो मिल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे दल हैं, जो कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्ष के साथ गलबहियां कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन बनता भी है तो भाजपा को देशभर में चुनौती नहीं दे पाएगा। विपक्ष में कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है, जिसका सियासी आधार देशभर में है।

विपक्षियों को भ्रष्टाचार के नाम पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से डराना-धमकाना, लोकतंत्र की आवाज को दबाना, झूठे आश्वासन देकर सामान्य लोगों को भ्रमित करना सत्तारूढ़ दल का काम नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार इस प्रकार के कार्य सरेआम झूठ बोल कर रही है।

नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वह यह प्रचारित कर रहे हैं कि कितना अधिक काम हो रहा है। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने के अभियान में भाजपा के विरूद्ध संभावित गठबंधन को मेन फ्रंट बता रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा है कि यदि विपक्षी एकता सफल हो गई, तो भाजपा को 50 सीटों पर सिमटा दिया जाएगा। यदि नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे विपक्षी एकता के प्रयास तथा साथ ही राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' सफल हो गई और आम लोगों की सुगबुगाहट को देखें तो ऐसा लगता है निकट भविष्य में जो होगा, वह अप्रत्याशित होगा। वह इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की छवि और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी केवल कांग्रेस ही है और छवि अब केवल राहुल गांधी की बनी है। नीतीश कुमार यदि अपने लोभ को त्याग दें और राहुल के लिए अपना मन बना लें तो प्रधानमंत्री की जो करिश्माई छवि है उसे डेंट किया जा सकता है और 2024 में नई सरकार की उम्मीद की जा सकती है।

ऐसा नहीं है कि भाजपा को इसकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए वह कांग्रेस और विपक्षियों के हमले का किस प्रकार काट करती है, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतनी बात तो है ही कि भाजपा के नीति-निर्धारकों ने निश्चित रूप से इस पर विचार किया ही होगा। क्योंकि, लंबे समय तक सत्ता पर काबिज हुए भाजपा इतनी आसानी से किसी को सत्ता सौंप देगी, यह इतना सहज नहीं है, जबकि सत्तारूढ़ दल का कहना है कि उसे वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहना है। देखना अब यह होगा कि इतनी बातों के घालमेल का परिणाम क्या निकलता है। मुख्य उद्देश्य चाहे सत्तारूढ़ दल हो या कांग्रेस या नीतीश कुमार के एका का प्रयास, सबकी सोच सत्तारूढ़ होना ही है। इसलिए, जोड़-घटाव कोई चाहे कितना ही कर ले और अपने को कोई कितना भी पारदर्शी कह ले, सच तो यही है कि किस प्रकार सत्ता पर काबिज किया जाए, सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसी उद्देश्य से साम-दाम-दंड-भेद की नीति का पालन किया जाता है।

● **विपिन कंधारी**

> अलग-अलग राजनीतिक मिजाज वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव देशभर में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। कारण है- इन राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का जुड़े होना। राजनीतिक रूप से इन राज्यों के नतीजे तीन प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भविष्य की राजनीति के लिए काफी अहम रहेंगे।

कसौटी पर लोकप्रियता

देश के दो राज्यों के विधानसभा चुनाव अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। कारण यह है कि इन चुनावों के संभावित नतीजों को लेकर भाजपा में चिंता पसरी है। हिमाचल प्रदेश में जहां 12 नवंबर को वोट पड़ गए, उसका चुनाव भाजपा को बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा है। जबकि गुजरात में उसने पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि वहां जीत का परचम लहराया जा सके। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमीन पर उसे टक्कर देते दिख रहे हैं। इस तरह हाल के चुनावों में मिली जीत के बावजूद भाजपा के लिए यह चुनाव जीतना बहुत जरूरी हो गया है।

इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने के कारण पार्टी की नाक का सवाल बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य होने के कारण। दोनों राज्यों में भले भाजपा विकास के लाख ढिंढोरे पीटे, मतों (वोटों) के लिए उसकी उम्मीद आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा ही है। मोदी ने दोनों राज्यों में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री होने की व्यस्तताओं के बावजूद काफी समय दिया है। लिहाजा हार-जीत के लिए उनकी लोकप्रियता भी कसौटी पर रहेगी।

गुजरात में भाजपा ने विशेष रणनीति बुनी है। उसने वहां जीत के लिए सब कुछ झोंक दिया है। अमित शाह लगातार चुनाव पर नजर रखे हुए हैं, जबकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में डटे हुए हैं। दोनों राज्य कितने महत्वपूर्ण बन गए हैं, यह इस बात से साबित हो जाता है कि भाजपा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 6 (हरेक में दो से तीन जनसभाएं) चुनाव दौरे किए, जबकि गुजरात तो वह पिछले तीन महीने से बार-बार गए हैं।

हिमाचल में कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी लगातार डटी रहीं, जबकि अशोक गहलोत जैसे दूसरे बड़े नेता भी आए। प्रियंका गांधी का चूंकि हिमाचल के शिमला जिले में घर भी है; इसलिए भी लोगों में उनके प्रति आकर्षण है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी 24 साल पहले हिमाचल में भाजपा के प्रभारी रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए गए। हालांकि बाद में पार्टी ने अपना पूरा ध्यान गुजरात पर लगा दिया।

यह दोनों विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह भाजपा के तीन बड़े नेताओं के गृह राज्य में हो रहे हैं। बल्कि इसलिए भी कि तीन बड़े दलों भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए यह अलग-अलग तरीके से अहम हैं। पहली बात भाजपा की जो लगातार चुनावों में जीत का स्वाद

गुजरात चुनाव में 2 ही बड़े मुद्दे

देखा जाए, तो चुनाव से पहले ही दो बड़े मुद्दे गुजरात में उभरे। इनमें एक था- बिलकिस बानो से दुष्कर्म के आरोपियों को गुजरात सरकार की तरफ से रिहा कर देना। इसके बाद मोरबी में पुल टूटने 136 लोगों की मौत का मामला भी काफी चर्चा में रहा। कई चीजों से साबित हुआ कि जिस कंपनी को इसकी मरम्मत का काम दिया गया था, उसमें नियमों को ताक पर रखा गया। गुजरात देश का ऐसा राज्य है, जहां बिजली की दरें देश में सर्वाधिक दरों में एक हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मुद्दे सामने आए हैं, जिन्हें जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं कह सकते लेकिन जिन पर चर्चा हो रही है। इनमें से एक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा कि उन्हें गुजरात चुनाव न लड़ने के बदले उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ केस दर्ज न करने का ऑफर दिया गया था। केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात गुजरात में कर रहे हैं।

चखती आ रही है। अब यदि उसे एक राज्य में भी हार का सामना करना पड़ता है, तो उसकी लय टूट सकती है। भाजपा आलाकमान किसी भी सूरत में हार नहीं देखना चाहते। लगातार जीत हासिल कर भाजपा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जो मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की है, उसका क्रम टूट जाएगा। भाजपा अपनी जीतों को जनता के बीच लगातार न सिर्फ अपने पक्ष में भुनाती रही है, बल्कि इसे कांग्रेस (या विपक्ष) के उसके मुकाबले बहुत कमजोर होने का संदेश देने के लिए भी इस्तेमाल करती रही है। उसे पता है कि चुनाव में जीत ही राजनीति में मजबूत बने रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। लोग चुनावी हार-जीत से प्रभावित होते हैं। हाल के वर्षों में भाजपा की जनता में मजबूत पार्टी होने की छवि में इन जीतों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके विपरीत कांग्रेस को इसका बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक नुकसान झेलना पड़ा है।

कांग्रेस की बात करें, तो मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए-नए अध्यक्ष बने हैं। हार से शुरुआत उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगी। बेशक उन्हें अध्यक्ष बनने के बाद संगठन और चुनाव फ्रंट पर कोई ज्यादा काम करने का समय अभी नहीं मिला है, एक भी जीत उन्हें ताकत देगी। यहां यह भी काबिल-ए-गौर है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार में वह अभी तक नहीं गए हैं। हो सकता है गुजरात जाएं, क्योंकि वहां मतदान अगले महीने के शुरू में है। लेकिन इसके बावजूद खड़गे दिल्ली में रहकर लगातार चुनाव रणनीति पर नजर रखे हैं।

गुजरात में अनुभवी नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के विशेष चुनाव प्रभारी हैं और वह लगातार खड़गे को फीडबैक देते हैं। कांग्रेस हाल के चुनावों में लगातार हारी है। पंजाब में भले वह दूसरे स्थान पर रही, लेकिन उसने सरकार गंवाई। उपचुनावों में उसे कुछ सीटों पर जीत हासिल हुई है; लेकिन एक पूरे राज्य में जीत उसके मनोबल को बढ़ा सकती है। कांग्रेस को पता है कि जमीन पर उसकी उपस्थिति अभी भी है। लेकिन चुनाव जीते बिना उसकी साख नहीं लौटेगी। राहुल गांधी ने इन चुनावों से दूरी बना रखी है। हालांकि प्रियंका गांधी लगातार प्रचार में दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के लिए यह चुनाव कुछ अलग तरह से महत्वपूर्ण हैं। उसकी लड़ाई साख की नहीं है। आप की नजर कांग्रेस का स्थान लेने पर है। आम आदमी पार्टी नेतृत्व का साफ लक्ष्य है- कांग्रेस की जगह भाजपा का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनना। दो राज्यों में उसकी सरकार है और यदि वह एक और राज्य जीतती है, तो उसकी सरकारें कांग्रेस के दो राज्यों के मुकाबले तीन राज्यों में हो जाएंगी। ऐसा होने की स्थिति में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश करेगी, भले उसका कांग्रेस जैसा देशव्यापी जनाधार अभी न हो। अरविंद केजरीवाल इन दोनों राज्यों, खासकर गुजरात में चतुराई से चुनाव अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के विपरीत हिंदुत्व कार्ड खेलने से भी परहेज नहीं किया है और भाजपा को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। इसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। लेकिन तमाम आरोपों, कि आप और केजरीवाल भाजपा की 'बी टीम' हैं; केजरीवाल इससे बेपरवाह अपने बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने पंजाब की तरह गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी खुलकर लोकलुभावन घोषणाए की हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसका लाभ उन्हें मिलता है या नहीं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट पड़ने के बाद अब सारा फोकस गुजरात पर चला गया है। वहां दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। जाहिर है तमाम बड़े नेता अब गुजरात में ही दिखेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का गुजरात जाना अभी तय नहीं हुआ है, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में वहां जमकर प्रचार किया था। प्रियंका गांधी जाएंगी, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। पार्टी के दो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी प्रचार में हैं। भाजपा के लिए मोदी और अमित शाह पहले से डटे हैं। उसके मुख्यमंत्री भी वहां जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सारे प्रचार का जिम्मा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर है, जो पूरी ताकत वहां झोंक रहे हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा कोई और नामी चेहरा आम आदमी पार्टी के पास नहीं है।

बेशक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण में इस तरह की रेवड़ियां बांटने पर सवाल उठाए थे। लेकिन खुद उनकी पार्टी इस तरह की लोकलुभावन घोषणाएं करने को मजबूर हुई है। केजरीवाल को गुजरात से बहुत उम्मीद है। हालांकि वह भी यह जानते हैं कि बिना जमीनी संगठन के आम आदमी पार्टी को आसानी से सत्ता नहीं मिलेगी। भाजपा चाहती है कि चुनाव तक आम आदमी पार्टी को मुकाबले में रखने का प्रचार जारी रहे, ताकि विपक्ष का वोट बंटे और कांग्रेस को इसका लाभ न हो। जितना ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी लेगी, भाजपा को लाभ और कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि यह एंटी-इंकम्बेंसी का वोट होगा। हालांकि एक मत यह भी है कि जिस तरह केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रहे हैं। भाजपा को भी इसका नुकसान हो सकता है। साथ ही आप की लोकलुभावन घोषणाएं भाजपा का वोट छीनकर आम आदमी पार्टी की झोली में डाल सकती हैं। एक बात साफ है कि इस चुनाव में तिकोना मुकाबला है और यदि सबके वोट बंटे, तो नतीजा किसी के भी पक्ष में जा सकता है और यदि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे, तो भाजपा की जीत तय हो जाएगी।

● इन्द्र कुमार

गुजरात में तिकोना मुकाबला

यह तीन महीने पहले की बात है। कुछ चुनाव सर्वे में तीसरे स्थान पर दिखाई जा रही कांग्रेस ने गुजरात के सभी विधानसभा हलकों में मतदाता तक एक चिट्ठी भेजने का काम शुरू कर दिया, जिसमें भाजपा सरकार की नाकामियों का जिक्र था। देखने में यह आम बात लगती थी, लेकिन चुनावी रणनीति के लिहाज से वास्तव में यह बड़ी बात थी। इतनी बड़ी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी कर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें कांग्रेस के इस अंडर ग्राउंड मिशन से सावधान रहने को कहना पड़ा। कांग्रेस ने अभी तक जमीनी प्रचार (डोर-टू-डोर अभियान) की रणनीति अपनाई है, और 17 नवंबर के बाद उसके बड़े नेता भी मैदान में उतरेंगे। चुनाव सर्वे गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत का लगातार जिक्र कर रहे हैं। उसकी लोकलुभावन घोषणाओं ने भाजपा को भी मजबूर किया है कि तत्काल चुनावी लाभ दे सकने वाली घोषणाएं की जाएं।

बघेल का सॉफ्ट हिंदुत्व

राज्य में चुनावी हलचल तेज

राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हो रही हलचल के बीच, भाजपा और आरएसएस अलग-अलग आक्रामक शैली और कार्यक्रमों के जरिए सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं हैं। हाल में झारखंड के रांची से सड़क मार्ग के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जशपुर पहुंचे। अगले दिन मोहन भागवत ने आदिवासी इलाके में हिंदुत्व जागरूकता के कामों से अपनी पहचान बनाने वाले और जशपुर राजपरिवार के प्रमुख दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। मोहन भागवत के दौरे और भाजपा के धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा उठाए जाने को लेकर बघेल ने कहा, भाजपा के पास कोई विषय नहीं है, न किसान का मुद्दा है, न मजदूरों का है, न आदिवासियों का है, न विकास का मुद्दा है, न मानव विकास के मुद्दे हैं, न भौतिक विकास के मुद्दे हैं। एक धर्मांतरण और एक सांप्रदायिकता ये दो ही हथियार हैं भाजपा के पास, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल भाजपा के कलेजे पर अंगार बिखेरने के उद्देश्य से तैयार की गई राम वन गमन योजना की कमान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभाल रखी है, जिनके नाम पर 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। तमाम रचना, योजना और क्रियान्वन के जरिए विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की पिच पर खेलने की तैयारी कर चुकी सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को वोटर कितना दिल से लगाते हैं, यही देखने की बात है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा चुनाव नरम हिंदुत्व की पिच पर खेलने की तैयारी कर ली है। भगवान राम के ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार ने राम की स्मृतियों को सहेजना शुरू किया। राम के सहारे सत्ताधारी कांग्रेस ने प्रदेशभर में भूपेश बघेल सरकार की लहर चलाना शुरू कर दिया है। वैसे तो राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। माना जाता है कि राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्ष से अधिक समय छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर बिताए थे। जनश्रुति के अनुसार राम वनवास काल में मांड नदी से चंद्रपुर और फिर महानदी मार्ग से शिवरीनारायण पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के भरतपुर तहसील में मवाई नदी से होकर जनकपुर नामक स्थान से लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित सीतामढ़ी-हरचौका नामक स्थान से राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। कहते हैं, त्रेता युग में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल और दंडकारण्य के रूप में विख्यात था। दंडकारण्य में राम के वनगमन यात्रा की पुष्टि वाल्मीकि रामायण से होती है। कहा जाता है कि राम छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के बाद दक्षिण भारत की ओर गए थे। अत: छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ भी कहा जाता है।

छत्तीसगढ़ में महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर बसा शिवरीनारायण धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। देश के चार प्रमुख धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के बाद इसे पांचवे धाम की संज्ञा दी गई है। यह स्थान भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान है इसलिए छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहां राम का नारायणी रूप गुप्त रूप से विराजमान है इसलिए यह गुप्त तीर्थधाम या गुप्त प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार ने राम के वनवास काल को लेकर न रुचि दिखाई न कुछ खास कर पाई। सत्ता में काबिज होते ही भूपेश बघेल ने राम वन गमन कॉन्सेप्ट प्लान बना डाला। इस प्लान के तहत राम के छत्तीसगढ़ में वनवास काल में भ्रमण से संबंधित 75 स्थानों को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। राम वन गमन मार्ग में आने वाले स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम रायपुर जिले के आरंग तहसील के गांव चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर से शुरू हुआ।

योजना के तहत सरकार ने प्रथम चरण में 9 स्थल चिन्हित कर वहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने का काम तेज गति से किया। चयनित स्थानों पर आवश्यकता अनुसार पहुंच मार्ग का उन्नयन, संकेत बोर्ड, पर्यटक सुविधा केंद्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर, वैदिक विलेज, पगोड़ा वेटिंग शेड, मूलभूत सुविधा, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, सिटिंग बेंच, रेस्तरां, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, विद्युतीकरण आदि कार्य को अंजाम भी दिया जा रहा है। 'राम वन गमन पथ' नाम की इस योजना के लिए 133 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने भगवान का सहारा लिया हो। जन्माष्टमी के मौके पर छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत हुई। योजना के माध्यम से 1.68 हेक्टेयर क्षेत्र में सांस्कृतिक और जीवनोपयोगी 383 वृक्षों का रोपण किया जाना तय हुआ है। योजना के तहत राज्य में नगरीय क्षेत्रों के 162 स्थानों में विकसित कृष्ण-कुंज में बरगद, पीपल, कदंब जैसे आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गुलर, पलास, अमरूद, सीताफल, बेल, आंवला के वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर राज्य में **कृष्ण कुंज योजना** की शुरुआत पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए बघेल ने कहा कि राम और कृष्ण सबके हैं और किसी का उन पर कॉपीराइट या पेटेंट नहीं है। कृष्ण के उपदेशों को कौन नहीं मानता, भाजपा सिर्फ वोट के लिए कृष्ण का नाम लेती है। कृष्ण के नाम से योजना शुरू करने से तिलमिलाई भाजपा में बघेल के इस बयान से चुप्पी-सी छा गई थी।

विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हो रही हलचल के बीच भूपेश बघेल हिंदुत्व के तमाम रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। समय-समय पर बघेल शिव, राम, कृष्ण को लेकर धार्मिक बयान भी देते नजर आते हैं। बीते दिनों उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था, शिव शिव हैं। पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोदेंगे तो शिव निकलेंगे, बाकी मूर्तियां बाद में प्रकट हुईं लेकिन भगवान शिव का वर्चस्व प्राचीन समय से ही रहा है, निर्णय तो बाबा (भगवान शिव) ही देंगे। विशेष शैली से अपनी विशेष जगह बनाने वाले बघेल हाल ही में राजधानी रायपुर के दही हांडी मैदान हनुमान मंदिर गुढ़ियारी में पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले के दौरे में डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के लालबहादुर नगर में पहुंचकर प्राचीन हनुमान मंदिर और साईं मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

महापुरूषों की राजनीति

राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान से उद्धव ठाकरे कैंप नाराज है। इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी को बीते कल की बात कहकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब महाराष्ट्र की राजनीति इन्हीं दो बयानों के चारों तरफ चक्कर लगाती नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे राहुल गांधी ने एक पत्र दिखाकर यह पूछा था कि सावरकर ने इसमें माफी क्यों मांगी थी और उन्हें अंग्रेजों से पेंशन क्यों मिलती थी। उनकी बातों का समर्थन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटोले ने भी किया है और कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि सावरकर को पेंशन क्यों मिलती थी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे खेमा ने इस बयान का विरोध किया है। इससे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठ गए है। जेल से बाहर निकले शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम में राहुल के बयान की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे बेतुके बयान से राहुल गांधी जनता के मन में जो विश्वास पैदा हो रहा था, उसे खुद ही तोड़ रहे हैं और भाजपा के लिए असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का रास्ता बना रहे हैं।

राउत ने अपनी बातों के समर्थन में पुस्तक का हवाला देते हुए कहा है कि लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले बयान से राहुल गांधी को बचना चाहिए क्योंकि इससे वह भाजपा का रास्ता साफ कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा था कि दरअसल हिंदुत्व का दावा करने वाली पार्टी स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ब्रिटिश सरकार के साथ थी। दूसरी तरफ राउत ने लिखा है कि वीर सावरकर ने अंडमान जेल में 10 साल बिताए हैं। इस बहस के जारी रहने के बीच ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नितिन गडकरी की तुलना छत्रपति शिवाजी से कर दी है। इससे नया विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने एक समारोह में कहा है कि महाराष्ट्र के लोगों से जब आजादी के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा तो अन्य लोगों के साथ ही वह छत्रपति शिवाजी का भी नाम लेंगे। लेकिन अब शिवाजी पुराने जमाने की बात है। अभी तो इस कतार में नितिन गडकरी जैसे लोग हैं। इस बयान के बाद विरोधी दलों ने शिवाजी महाराज विरोधी उनके बयान की वजह से उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी है। दूसरी तरफ भाजपा ने इस बयान पर अब तक कोई सफाई नहीं दी है।

कांग्रेस अपने सत्ता निर्वासन को समाप्त करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर है। जो कांग्रेस की तड़पन को दूर करने के लिए अपरिहार्य भी है। लेकिन कभी-कभी इस यात्रा के दौरान ऐसा भी लगने लगता है कि इसका मूल उद्देश्य भारतीय समाज को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि समाज में बिखराव पैदा करना ही है। अगर यात्रा का उद्देश्य वास्तव में ही समाज को जोड़ने के लिए होता तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कम से कम वीर सावरकर के बारे में अनुचित टिप्पणी करने से परहेज करते, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कांग्रेस के कौन से निहितार्थ हैं, यह कांग्रेस के नेता ही जानते होंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर निशाना साधने के कुछ मायने हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अध्ययन किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में वीर सावरकर के प्रति सम्मान कुछ ज्यादा ही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अंग्रेजों का नौकर बताने वाला बयान देना निश्चित ही महाराष्ट्र की जनता को उकसाने वाला ही था। कांग्रेस नेता संभवत: यही चाहते थे कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध हो और ठीकरा भाजपा-शिंदे सरकार पर फोड़ा जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यह राजनीतिक योजना पूरी तरह से विफल हो गई।

भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जो सपना देख रही है, वैसा हर राजनीतिक दल को भी देखना चाहिए। ऐसी यात्राओं के माध्यम से राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाने का अवसर प्राप्त होता है। जनता की समस्याओं को जानने का भी साक्षात्कार होता है। वास्तव में राजनीतिक दलों का मूल उद्देश्य भी यही होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जनता से सीधे जुड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता। वह जनता के समक्ष कांग्रेस के विचार को स्थापित करने में विफल ही हो रहे हैं। उनकी यात्रा के मूल में कांग्रेस कम, भाजपा का विरोध ज्यादा दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि विरोध की राजनीति करने से नकारात्मक भाव प्रादुर्भूत होता है। इसके साथ ही यह भी एक बड़ा सच है कि सामने वाले का जितना विरोध करेंगे, उसका उतना ही प्रचार होता जाएगा। आज वास्तविकता यही है कि भाजपा को बड़ा बनाने में जितना परिश्रम स्वयं भाजपा का नहीं, उससे कहीं ज्यादा विरोधी दलों का है। क्योंकि वर्तमान विरोधी दलों का कोई भी कार्यक्रम भाजपा विरोध के बिना अधूरा ही है। विपक्षी दल जब तक अपनी स्वयं की बात प्रभावी तरीके से नहीं रखेंगे, तब तक उनके स्वयं के विचार जनता तक नहीं पहुंच सकते। आज देश की राजनीति का स्तर केवल भाजपा समर्थन या भाजपा विरोध ही रह गया है।

● **बिन्दु माथुर**

महाराष्ट्र की राजनीति में दरार

राहुल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमा गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के एक धड़े के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल की टिप्पणी से पल्ला झाड़ लिया। उद्धव ने कहा कि उनकी पार्टी विनायक दामोदर सावरकर की बहुत इज्जत करती है। हमारे मन में वीर सावरकर के लिए बहुत सम्मान और विश्वास है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस अपरिपक्व बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में दरार पैदा होने लगी है। हालांकि दरार तो पहले से ही थी, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना नदी के ऐसे दो किनारे हैं जो एक-दूसरे से दूर रहकर भी साथ-साथ होने का दिखावा करते हैं। इस प्रकार की राजनीति से राजनीति दल अपने सिद्धांतों की बलि ही चढ़ाते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। यह कांग्रेस के लिए समय की मांग है।

आलाकमान के हाथ भाजपा की कमान

अंदरुनी कलह बार-बार उजागर

राजस्थान में भाजपा नेताओं की 'एकला चलो' की नीति और देवदर्शन, धार्मिक यात्रा के नाम पर खुद का स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम करवाने और जगह-जगह जन सभाएं करने की शिकायत पार्टी आलाकमान तक पहुंची है। प्रदेश में पार्टी को सूचना दिए बिना इस तरह की यात्राएं करने पर भाजपा संगठन में नाराजगी है। पार्टी के पहले से निर्धारित कार्यक्रमों मे भी सीनियर नेता नहीं पहुंच रहे हैं। पार्टी नेताओं को एकजुट होने की बार-बार नसीहत देने के बावजूद गुटबाजी और अंदरुनी कलह बार-बार उजागर हो रही है। ऐसे में पार्टी की मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने के लिए भाजपा आलाकमान को ही मैदान में उतरना होगा। जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानगढ़ धाम यात्रा से हो रही है। विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी को भाजपा के 12 विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा था। इसमें वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थीं। जबकि वह स्पीकर के आवास के ठीक सामने स्थित अपने बंगले पर मौजूद थीं। इस पर कटारिया ने स्वीकार किया कि उनको सूचना देने में उनसे चूक हुई है। जेपी नड्डा हर बार राजस्थान भाजपा नेताओं के साथ बैठक में गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल तैयार करने के निर्देश देते रहे हैं।

भाजपा आलाकमान के बार-बार चेताने के बावजूद राजस्थान के भाजपा नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में भाजपा संगठन को लेकर बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस को हरा पाना मुश्किल है। इसीलिए नड्डा स्वयं भी राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी लगातार राजस्थान भेज रहे हैं। ताकि राजस्थान में नेताओं के आपसी मतभेद समाप्त हो सकें। मगर नड्डा के प्रयास कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान के संगठन में सबसे अधिक बिखराव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण हो रहा है। वसुंधरा राजे पूरा प्रयास कर रही हैं कि उन्हें एक बार फिर नेता प्रोजेक्ट कर प्रदेश की कमान सौंप दी जाए। मगर भाजपा आलाकमान ऐसा करना नहीं चाहता है। भाजपा आलाकमान का मानना है कि प्रदेश में अब वसुंधरा राजे पहले की तरह लोकप्रिय नहीं है। इसीलिए पार्टी नए नेतृत्व को तैयार कर रही है। जो **आने वाले समय** में पार्टी की कमान संभाल सके। हालांकि वसुंधरा राजे अपने पक्ष में तर्क देती हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने प्रदेश में दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मगर उनके विरोधियों का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते वसुंधरा को दोनों ही बार चुनाव में मात भी खानी पड़ी थी।

यदि वह लोकप्रिय नेता होतीं तो उनके मुख्यमंत्री रहते पार्टी चुनाव क्यों हारती। पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ही राजस्थान में पार्टी की एक छत्र नेता थीं। मगर फिर भी पार्टी चुनाव हार गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में तो राजस्थान में भाजपा 163 सीटों से घटकर मात्र 73 सीटों पर आ गई थी। भाजपा को सीधे-सीधे 90 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। वसुंधरा सरकार की नाकामियों को भुनाकर कांग्रेस ने घर बैठे सत्ता हथिया ली थी। अपने मुख्यमंत्री के पिछले कार्यकाल में वसुंधरा राजे पर उनकी पार्टी के ही नेता चाटूकारों से घिरे रहने का आरोप लगाते हैं। वसुंधरा राजे की कार्यशैली से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी नाराज रहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई बार वसुंधरा सरकार को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने की चेतावनी भी दी थी। मगर वसुंधरा राजे ने किसी की एक नहीं सुनी थी। जिसके परिणाम स्वरूप ही राजस्थान में भाजपा को सत्ता गवांनी पड़ी थी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री यूनुस खान, कालीचरण सर्राफ, राजपाल सिंह शेखावत, प्रताप सिंह सिंघवी, भवानी सिंह राजावत, उनके विशेषाधिकारी धीरेंद्र कमठान जैसे लोग सत्ता के केंद्र बन गए थे। जिनकी सलाह पर ही वसुंधरा राजे फैसले लिया करती थीं।

वसुंधरा राजे आज भी अपनी उसी पुरानी चौकड़ी से घिरी नजर आती है। भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा वसुंधरा के हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जिसका पार्टी संगठन की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज कराया जाता है। मगर फिर भी वसुंधरा राजे अपनी चौकड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा विरोधी खेमे के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, सांसद किरोडी लाल मीणा, ओम माथुर, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी जैसे नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने पर पार्टी में किसी एक नेता की छाप नहीं होगी। इससे प्रदेश के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जिसके नतीजे भी सकारात्मक होने की आशा की जा सकती है। राजस्थान के भाजपा नेताओं में बढ़ती कलह को मिटाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलानी पड़ी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस बैठक में राजस्थान के नेताओं की जमकर क्लास ली।

सूत्रों के मुताबिक नड्डा और शाह ने पार्टी नेताओं को दो टूक शब्दो में कहा कि आपसी लड़ाई और टांग खिंचाई छोड़कर गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ो। 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक साल का समय बचा है। हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बड़े नेताओं द्वारा प्रदेश में अलग-अलग दौरे और यात्राएं की जा रही हैं। हमारे पास सभी की रिपोर्ट है। इसलिए फिर से समझाया जा रहा है कि पार्टी अनुशासन में रहकर एकजुटता से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करे। प्रदेश में भाजपा के आंदोलनों और कार्यक्रमों में सभी नेताओं की उपस्थिति अनिवार्य हो। अगर उपस्थित नहीं हो सकते तो पहले ही उचित कारण के साथ पार्टी को सूचना दी जाए। आगे से राजस्थान भाजपा के सभी सीनियर नेता प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लें। खबर है कि राजस्थान कोर कमेटी की बैठक में भाजपा नेतृत्व ने राजस्थान के नेताओं को साफ संदेश दिया है कि व्यक्तिगत एजेंडे को नहीं, पार्टी के एजेंडे को लेकर सभी मिलकर आगे बढ़ें। राजस्थान में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करना है तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व को पहले सूचना देकर और मंजूरी लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में भाजपा आगे बढ़ेगी। राजस्थान के नेता किसी भी कार्यक्रम को करने की मंजूरी संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी महासचिव से लें।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

उप्र में मुस्लिम राजनीति

उप्र भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। देश की कुल आबादी का 16.51 फीसदी यहीं बसता है। ये बात भी जगजाहिर है कि इस सूबे में चुनावों में हुई हार-जीत का गणित देश की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साल 2011 की जनगणना पर नजर डालें तो उप्र की कुल आबादी 19.98 करोड़ रही और इसमें 3.84 करोड़ मुस्लिम रहे। इस हिसाब से देखा जाए तो इस सूबे की कुल आबादी में 20.26 फीसदी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यहां विभिन्न राजनीतिक दलों की हार-जीत का दारोमदार मुस्लिम नेताओं पर रहता है। उप्र के यही मुस्लिम नेता अपने प्रभाव से इस समुदाय का वोट बैंक खींचते हैं। ऐसे कुछ असरदार और रौबदार नेताओं में आजम खान, मुख्तार अंसारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं तो इमरान मसूद शफीकुर्रहमान बर्क, नाहिद हसन, हाजी फजलुर्रहमान, एसटी हसन जैसे जनता के बीच मशहूर चेहरे भी शामिल हैं। इसमें दो राय नहीं कि लोकसभा 2024 के चुनावों में भी इन चेहरों पर दांव लगाकर राजनीतिक पार्टियां मुसलमान वोट पाने की कवायद करेंगी।

उप्र में मुसलमान नेताओं के असर की बात हो और इस कड़ी में आजम खान का नाम न लिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। सपा की रीढ़ कहे जाने वाले आजमखां का नाम उप्र के प्रभावशाली नेता के तौर पर सामने आता है। उप्र के मुसलमानों पर आजम खान के असर का अंदाजा लगाना हो तो ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। उसके लिए साल 2022 के उप्र विधानसभा चुनाव ही काफी है। मार्च 2022 में वो 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद थे, लेकिन इसके बावजूद सपा सांसद आजम खान ने जिले में सबसे अधिक वोट हासिल कर इतिहास रच डाला। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी उप्र में **मुस्लिम वोट बैंक** में खासा असर रखते हैं। उप्र में झांसी से आने वाले सिद्दीकी बसपा के पहले मुस्लिम विधायक थे। सिद्दीकी 1991 में बांदा से बसपा के पहले मुस्लिम विधायक बने थे। वक्त के साथ वो मायावती के बेहद खास होते गए। सूबे में 2007 में बसपा सरकार बनने पर उनका दर्जा मिनी मुख्यमंत्री जैसा रहा। 2010 के एमएलसी चुनाव में मायावती ने बांदा हमीरपुर से उनके बड़े भाई और पुराने बसपा नेता जमीरउद्दीन सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। इससे सिद्दीकी बसपा सुप्रीमो से नाराज हो गए। उन्होंने जमीरउद्दीन का टिकट काटकर इन चुनावों में अपनी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी को एमएलसी प्रत्याशी बना डाला।

मुख्तार अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं। उप्र के राजनीति में दबंग मुस्लिम नेता के तौर पर भी मुख्तार अंसारी को जाना जाता है। गाजीपुर के ही युसुफपुर-मुहम्मदाबाद में 1963 में जन्में मुख्तार का खानदान कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी का उप्र की राजनीति में अच्छा खासा दखल था। बड़े भाई अफजाल की हौसला अफजाई ने उन्हें राजनीति में उतारा। साल 1985 में गाजीपुर की मुहम्मदाबाद सीट से अफजाल पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक चुने गए। इसमें मुख्तार का खासा योगदान रहा। इसके बाद उनकी राजनीति के फलक पर छा जाने की चाह बढ़ती गई।

उप्र में लोकसभा-विधानसभा सीट

उप्र में 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा की सीट हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। 36 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर पूर्वी उप्र के कुछ हिस्सों में मुसलमान हैं तो पश्चिमी उप्र में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। पश्चिमी उप्र में 26.21 फीसदी आबादी मुसलमानों की है। पश्चिमी उप्र में 26 जिले आते हैं, जहां विधानसभा की 136 सीटें हैं। अगर साल 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 34 मुसलमान विधायक चुने गए। इसमें 21 विधायक अकेले पश्चिम उप्र से ही चुनकर आए थे। 6 सेंट्रल उप्र से तो 7 पूर्वांचल से जीते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में 24 मुसलमान विधायक चुने गए थे। साल 2014 में उप्र में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया था। साल 2019 में उप्र से 6 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। इसमें बसपा और सपा के 3-3 सांसद रहे। बसपा के कुंवर अली दानिश ने अमरोहा से तो अफजाल अंसारी ने गाजीपुर और सहारनपुर से हाजी फजर्लुरहमान ने जीत हासिल की थी। उधर सपा से रामपुर से कद्दावर नेता आजम खान ने, संभल से शफीकुर्रमान और मुरादाबाद सीट से डॉ. एसटी हसन जीते थे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत नेता काजी रशीद मसूद की 50 साल तक राजनीति में तूती बोलती थी। वे केवल पश्चिमी उप्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में खासा असर रखते थे। उनके संग साए में उनके भतीजे इमरान मसूद ने भी राजनीति के गुर सीखे। पश्चिमी उप्र में खासा दबदबा रखने वाले इमरान ने 20 अक्टूबर 2022 को समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा ज्वॉइन कर ली। दरअसल उप्र विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर सपा का दामन थामा था। उन्होंने अपना राजनीति का सफर 2006 में सहारनपुर के नगर परिषद के अध्यक्ष से शुरू किया। फिर साल 2007 में सहारनपुर जिले की मुजफ्फराबाद सीट (अब बेहट सीट) से विधायक बने। सपा के उन्हें टिकट देने से इंकार करने के बाद मसूद ने ये विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। इसमें उन्होंने जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक ताकत लोगों को दिखा दी।

उप्र के बलिया में जन्मे दानिश आजाद अंसारी उप्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। दानिश न ही विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य लेकिन उनके योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए जाने ने सबको हैरानी में डाल दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहने के दौरान ही वह भाजपा की स्टूडेंट विंग एबीवीपी में शामिल हो गए थे। वो भाजपा की विचारधारा को मुस्लिम युवाओं में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से उप्र सरकार ने उन्हें 29 अक्टूबर 2018 को उर्दू भाषा आयोग का सदस्य बनाया। बीते साल 2021 में योगी मंत्रिमंडल में उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश महामंत्री बनाया गया था। मुस्लिम ओबीसी के अंसारी समुदाय से आने वाले दानिश को मंत्री बनाकर भाजपा ने इस मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। वह लोकसभा 2024 में उप्र में भाजपा का चेहरा बन कर सामने आएंगे।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

फंदे में सरकार

ईडी की कार्रवाई के बहाने मुख्यमंत्री को टारगेट

आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दरवाजे पहुंच ही गया। उनके खिलाफ खुद के नाम खनन पट्टे का नवीकरण कर पद के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में चुनाव आयोग की राय दो महीने से राज्यपाल के पास लिफाफाबंद है। मई के पहले सप्ताह में राज्य की तत्कालीन खदान सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी के छापे के बाद ऐसा अनुमान नहीं था कि केंद्रीय एजेंसी इतनी जल्दी सोरेन के यहां दस्तक देगी। इससे लग रहा है चुनाव आयोग की राय हेमंत सोरेन के अनुकूल नहीं निकली। दीपावली से ठीक पहले रायपुर में एक चैनल से इंटरव्यू में राज्यपाल ने कहा था कि आयोग से सेकेंड ओपिनियन मांगी गई है। ईडी के समन के बाद सोरेन सरकार में सहयोगी कांग्रेस पार्टी के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव और बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह और उनके कुछ करीबी कारोबारियों के ठिकानों पर भी आयकर और ईडी का छापा पड़ा था। जाहिर है, इससे सर्दियों के मौसम में भी राज्य की राजनीतिक में गरमी बढ़ गई है।

अनूप सिंह ने सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की खरीद-फरोख्त (कोलकाता में तीन विधायक नकद के साथ पकड़े गए थे) के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यूपीए के नेता सोरेन के समन और विधायकों के यहां आयकर छापे को भाजपा की साजिश बता रहे हैं। ईडी के समन के खिलाफ रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली में हेमंत सोरेन ने ईडी को चुनौती देते हुए कहा, यदि अपराध किया है तो गिरफ्तार करो, समन क्यों भेजते हो। राज्यपाल की खिंचाई करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब एक लिफाफा लेकर घूम रहे हैं। मैं देश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री होऊंगा जिसने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो सजा दी है, सुना दें। मगर आज तक उनका लिफाफा नहीं खुल रहा। यह सब षड्यंत्र है। 3 नवंबर को हेमंत को जब समन आया, तो उनके सब्र का बांध टूट गया। अगले दिन साहिबगंज में वे आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। उधर जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री के 15 दिनों का कार्यक्रम जारी कर रहा था। हेमंत ईडी कार्यालय नहीं गए और संयम दिखाते हुए ईडी कार्यालय को पत्र भेजकर तीन सप्ताह की मोहलत मांग ली। साहिबगंज से लौटकर यूपीए के विधायकों, नेताओं के साथ बैठक कर उन्होंने एकजुटता दिखाई। बैठक में तय हुआ कि 5 नवंबर से चरणबद्ध तरीके से ईडी के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ऐसा हुआ भी। उधर, भाजपा ने हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार और विफलताओं को लेकर 7 नवंबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी। भाजपा लगातार हेमंत के कुनबे पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने फरवरी में माइनिंग पट्टे के खिलाफ शिकायत की थी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने 10-12 साल में सोरेन कुनबे पर करीब 250 करोड़ रुपए की 108 संपत्तियां अर्जित करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल कहते हैं कि आदिवासी होने के कारण हेमंत को राज्य को लूटने की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने राज्य को दलालों के हाथ गिरवी रख दिया है। सरकार को उखाड़ने तक हम शांत नहीं बैठने वाले।

पूजा सिंघल के ठिकानों पर देशभर में छापा पड़ा तो झामुमो की रांची इकाई ने भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि भाजपा ईडी की कार्रवाई के बहाने मुख्यमंत्री सोरेन को टारगेट कर रही है, हालांकि तत्काल बाद झामुमो के बड़े नेता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत किया। पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापा 12-14 साल पहले के 18 मनरेगा घोटालों को लेकर पड़ा था। तब सिंघल खूंटी जिला की कलेक्टर हुआ करती थीं। उनके सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। पूछताछ के बाद मामला अवैध खनन, शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला तक पहुंच गया। अफसरों से पूछताछ और मिले इनपुट के बाद जांच का दायरा बढ़ता गया। मई में ही मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के बिल्डर रिश्तेदार और सत्ता में पैठ रखने वाले निशित केसरी, विशाल चौधरी और सत्ता में गहरी पैठ रखने वाले अफसरों के तबादलों को लेकर ख्यात प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापा पड़ा।

3 नवंबर को रायपुर रवाना होने से पहले सोरेन जनता के बीच सब कुछ कह देना चाहते थे। वे बोले, 20 साल बाद राज्य सरकार राज्य के विकास में लगी है, सरकार गरीबों के दरवाजे पर जाकर उनकी समस्याएं दूर कर रही है। उन लोगों को यही खटकता है। वे अदालत, आयकर, सीबीआई और ईडी का चेहरा दिखाकर डराना चाहते हैं। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार को अस्थिर करने की गहरी साजिश रची जा रही है। जब राज्य का बकाया पैसा केंद्र से मांगते हैं, तो पैसे के बदले ईडी और सीबीआई को भेज दिया जाता है। ईडी और भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने पर उन्होंने कहा- इन्हें झारखंडियों से क्या डर लगता है। अभी तो हमने कुछ किया नहीं है। जब झारखंडी अपनी बातों पर उतर आएंगे तो वे दिन दूर नहीं जब आप लोगों को यहां सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी।

हेमंत 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे हैं। इसके लिए 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। लंबे समय से हेमंत की घेराबंदी चल रही थी। विधायकों की खरीद-फरोख्त और सरकार गिराने की साजिश को लेकर दो प्राथमिकियां भी दर्ज हुईं। इससे भी पहले कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने यह कहकर राजनीति गरमा दी थी कि कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों पर भाजपा डोरे डाल रही है। वे लोग विधायकों के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर माइनिंग पट्टे के खिलाफ फरवरी में भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और सोरेन की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया था। राज्यपाल ने आयोग को मंतव्य के लिए पत्र लिखा, तो आयोग ने 25 अगस्त को अपना मंतव्य विशेष दूत से राजभवन पहुंचा दिया। आज तक उस बंद लिफाफे का मजमून सामने नहीं आया है। इसे लेकर भी खूब राजनीति हुई। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल किया गया तो विधायकों को एकजुट रखने के लिए रायपुर तक घुमाया गया। इस मौके का फायदा उठाकर सोरेन ने चुनावी वादों और जनता को प्रभावित करने वाले नीतिगत फैसलों की बाढ़ ला दी। अब 12 अक्टूबर से आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले साल इस कार्यक्रम में 35.95 लाख लोगों के आवेदन आए थे, जिसमें 35.56 लाख आवेदनों का निपटारा किया गया। ताजा अभियान में करीब 30 लाख आवेदन आए हैं, जिसमें 18.40 लाख आवेदनों का निपटारा किया गया है।

● विनोद बक्सरी

गृह युद्ध के कगार पर पाक

जनता को रास्ता नहीं दिख रहा

पाकिस्तान की जनता और युवाओं में जो स्थिति आज बन रही है, वह मोहभंग होने जैसी है। उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन वह महसूस कर रहे हैं कि जब तक देश की राजनीति का ढर्रा नहीं बदलता, देश के हालात में बदलाव नहीं आ सकता। सत्ता में बैठे लोगों ने देश के लोगों में भारत के प्रति नफरत के बीज इतने गहरे बो दिए हैं कि उन्हें इससे बाहर निकलने में वक्त लगेगा। लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तानी युवा कुछ अलग दिशा में सोचने लगे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में जनता के बीच सेना का जो समर्थन एक दशक पहले तक था, वह अब नहीं रहा। जनता पहले यह सोचती थी कि भारत के खतरे से उन्हें सेना ही बचा सकती है, लेकिन अब लोग यह सवाल करने लगे हैं कि क्या वास्तव में भारत की तरफ से उन्हें खतरा है? या यह सिर्फ सेना और राजनीति के लोगों का खड़ा किया हौवा है?

दुनिया भर की निगाह इस बात पर टिकी है कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां की ताकतवर सेना में चल रही जंग में किसकी जीत होती है? हाल के दशकों में पाकिस्तान में यह नई तरह की राजनीतिक जंग है, जिसमें सेना के सामने मुश्किल चुनौती वाली स्थिति है। यह पहली बार दिखा है कि सेना की सत्ता पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही। नहीं तो यही होता रहा था कि सेना (एस्टेब्लिशमेंट) मौका मिलते ही सत्ता पर काबिज हो जाती थी। इमरान खान ने निश्चित ही यह ठान लिया लगता है कि वह सेना की सत्ता के सामने हथियार नहीं डालेंगे। बहुत-से लोगों को यह भी लगता है कि वर्तमान स्थितियां पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ धकेल सकती हैं। पाकिस्तान में इसी महीने सेना के ताकतवर जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान एक देश के रूप में कठिन दौर में है।

पाकिस्तान में हाल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले के बाद वहां की सियासत काफी गरमा गई है। इमरान खान हमले के बाद भी झुकने को तैयार नहीं और अपनी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का मार्च जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की राजनीति समझने से जाहिर होता है कि इमरान खान पर हमला आम हमला नहीं था और यह या तो उनकी जान लेने की कोशिश थी या उन्हें चेतावनी देने की कोशिश कि वह सेना-आईएसआई के खिलाफ अपनी जुबान बंद रखें। इस सारी स्थिति में सत्तारूढ़ शाहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएल (एन) और भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) अजब दुविधा में फंस गए हैं। कारण यह है कि सेना के दबदबे से यह दोनों पार्टियां भी छुटकारा पाना चाहती हैं; लेकिन उनके सामने फिलहाल सेना से बड़ी चुनौती इमरान खान बन गए हैं। इमरान के मार्च को जनता से मिल रहे समर्थन से शरीफ और भुट्टो दोनों हिले हुए हैं। पाकिस्तान की राजनीति के नब्ज समझने वाले जानकारों का कहना है कि यदि आज चुनाव हो जाएं, तो इमरान खान बाजी मार सकते हैं। यही कारण है कि इमरान खान लगातार देश में चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं।

सेना और सत्तारूढ़ दल की हाल की पीटीआई को तोड़ने की कोशिशें सफल नहीं हुई हैं और समर्थक नेता इमरान खान से जुड़े हुए हैं। इमरान खान की जनता के बीच चल रही रैलियां जिस तरह की भीड़ जुटा रही हैं, उनसे जाहिर हो जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री को अगला चुनाव जीतने का पक्का भरोसा है। इमरान खान के साथ लोगों के दिखने की एक बड़ी बजह यह भी है कि पीएमएल(एन)-पीपीपी-अन्य दलों की मिली जुली सरकार कई मोर्चों पर नाकाम साबित हुई है और जनता की अपेक्षाएं वैसी-की-वैसी ही हैं। इमरान खान इससे उत्साहित हैं। आज की तारीख में पीएमएल(एन)-पीपीपी की प्राथमिकता इमरान खान से निपटने की बन गई है। लिहाजा उन्हें सेना का साथ पड़ रहा है। वहां इसी महीने के आखिर में सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं और सत्तारूढ़ दल अपना समर्थक सेनाध्यक्ष बनाना चाहता है, ताकि इमरान खान को कमजोर किया जा सके। सेना के बीच भी एक बड़ा वर्ग इमरान खान से खफा है, क्योंकि सेना अपनी सत्ता को चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेना के बीच सभी इमरान खान के विरोधी ही हैं। सेना का एक वर्ग ऐसा भी है, जो इमरान खान का समर्थन करता है।

इसके अलावा पाकिस्तान की ताकतवर एजेंसी आईएसआई में भी पदों पर बैठे लोग इमरान खान से खफा हैं। इमरान खान ने तो नाम लेकर आरोप लगाया था कि हाल में उन पर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसके पीछे आईएसआई और सरकार के दो बड़े लोग शामिल थे। इन सभी ने इसका खंडन किया था; लेकिन यह तो पाकिस्तान में आम चर्चा है कि सेना इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जनता में सेना का जो रुतबा कभी था, वह अब कम हो चुका है। इमरान खान चतुर राजनीतिक साबित हुए हैं। वह सेना के राजनीतिक में दखल का विरोध करने के लिए भारत का सहारा लेते हैं। उन्हें पता है कि भारत की सेना बहुत अनुशासित है और यह बात पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोगों को पसंद है। इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भारत का दुनिया में डंका इसलिए बजता है कि वह ठोक-बजाकर अपनी बात कहता है। जबकि पाकिस्तान की छवि तो भीख मांगने वाले देश की बन गई है, जो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता फिरता है।

ऐसा कहकर इमरान खान पाकिस्तान की जनता के स्वाभिमान को जगाना चाहते हैं। साथ ही वह जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि सेना नहीं, चुनी हुई सरकार ही उनका कल्याण कर सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में सेना के प्रति जनता का वह भरोसा नहीं रह गया है, जो कभी होता था। कारण यह है कि युवा रोजगार चाहते हैं और देश-विदेश में अपनी प्रतिभा का डंका बजाना चाहते हैं। वह भारत के युवाओं से अपनी तुलना करते हैं और महसूस करते हैं कि सेना और सरकारों की भूख ने देश के युवाओं को बहुत पीछे धकेल दिया है, जबकि भारत के युवा दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। वह महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में सेना और राजनीति के लोग भारत-पाकिस्तान के बीच दुश्मनी दिखाकर उनकी भावनाओं से खेलते रहे हैं और हकीकत में उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है, न ही देश का इससे कुछ भला हुआ है।

● ऋतेन्द्र माथुर

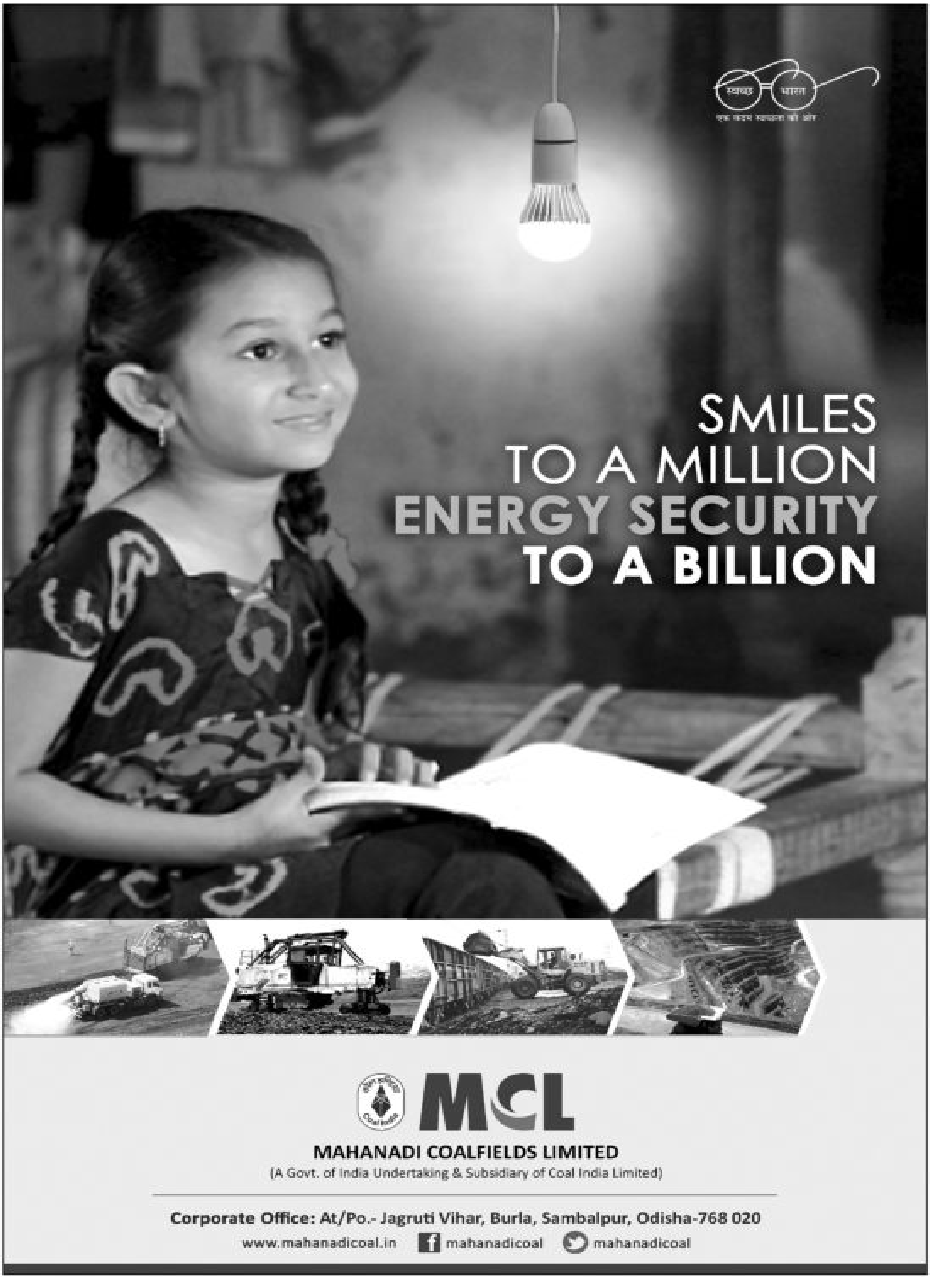
स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
SMILES
TO A MILLION
ENERGY SECURITY
TO A BILLION
MCL
MAHANADI COALFIELDS LIMITED
(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)
Corporate Office: At/Po.- Jagruti Vihar, Burla, Sambalpur, Odisha-768 020
www.mahanadicoal.in
mahanadicoal
mahanadicoal

जी-20 की बढ़ी महत्ता

इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी-20 देशों का हालिया सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण समय में आयोजित हुआ। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस साल फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के अभी तक थमने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। इसके कारण दुनिया में खाद्य वस्तुओं से लेकर ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति बिगड़ी है, जिससे पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। कोविड महामारी के बाद से ही सुधार की राह पर लौटने के लिए संघर्ष कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को इसने और झटका दिया है। इससे वैश्विक मंदी की आशंका गहरा गई है। मानो इतना ही काफी न हो, अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के दो महाबली देशों के बीच तनातनी बनी हुई है, जिसमें तमाम देशों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। चूंकि जी-20 विश्व की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है तो स्वाभाविक रूप से यह उसका दायित्व है कि वह आर्थिक परिदृश्य को सुधारने की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने की दिशा में प्रयास करे। इसलिए, हालिया सम्मेलन की महत्ता और बढ़ गई।

जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था और उसकी सबसे प्रमुख इकाई सुरक्षा परिषद में शामिल शक्तिशाली देशों में ही टकराव कायम है तो उस स्थिति में जी-20 जैसे संगठन से अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि वह विश्व का मार्गदर्शन करे। बाली सम्मेलन में जुटे वैश्विक नेताओं की भाव-भंगिमा तो सकारात्मक संदेश देने वाली रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां नेता अपने मतभेद किनारे करके संवाद के लिए आए हैं। यह बात सम्मेलन के घोषणापत्र में भी दिखी, जब यूक्रेन मसले पर रूस के मित्र भारत और चीन ने भी वैश्विक स्वर से स्वर मिलाए। इससे रूस को एक संदेश तो गया कि इस युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है।

भारत के दृष्टिकोण से तो यह घोषणापत्र और भी महत्व का रहा, क्योंकि इसमें 'यह युद्ध का समय नहीं' वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को समाहित किया गया, जो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया था। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मुखर होती आवाज का भी प्रतीक है कि दुनिया अब न केवल भारत की बात को सुनती है, बल्कि उसे मानकर तवज्जो भी देती है। जी-20 के मंच पर नेताओं के बीच व्यापार, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई, जिसकी आवश्यकता भी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिगड़े समीकरणों से व्यापार का तानाबाना प्रभावित हुआ है तो उसे पटरी पर लाना जरूरी है। विकसित और विकासशील देश दोनों इस संगठन के सदस्य हैं तो तकनीक का पहलू भी महत्वपूर्ण रहा। वहीं कोविड आपदा के बाद से ही चीन केंद्रित विनिर्माण इकाइयों के लिए विकल्प तलाशने की जो मुहिम शुरू हुई थी, उसे सही दिशा दिखाना भी समय की मांग है। यह जी-20 की ही जिम्मेदारी है कि वह इन मोर्चों पर विश्वास आधारित सहयोग को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वार्ता ने भी दुनिया को राहत के संकेत दिए हैं, क्योंकि इन दोनों की तनातनी में तमाम देश पिस रहे हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बतौर प्रधानमंत्री इस दौरान पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे तो उनकी मुलाकात भी चर्चा में रही। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीरें छाई रहीं, जिनमें अपनत्व और नजदीकी का भाव दिखा। इस सम्मेलन का एक ऐतिहासिक पड़ाव रहा भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलना। एक दिसंबर से भारत विधिवत जी-20 की अध्यक्षता संभाल लेगा। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि वह इसका इस्तेमाल अपने अंतरराष्ट्रीय कद को बढ़ाने के लिए करे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत को बेहद चुनौतीपूर्ण समय में यह मौका मिल रहा है, लेकिन भारत ने इस आयोजन से जुड़ी थीम, लोगो और वेबसाइट के माध्यम से जो संकेत दिए हैं, उनसे यही लगता है कि भारत इस मौके को पूरी तरह भुनाने के लिए कमर कसे हुए है।

'वसुधैव कुटुंबकम' के माध्यम से भारत विश्व को आश्वस्त करना चाहता है कि वह केवल अपना ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण की कामना करता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है। कोविड महामारी के दौरान भारत का अनुकरणीय आचरण इस थीम के संदेश से पूरा न्याय करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समय जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बनी हैं, उनमें चाहे पश्चिमी देश हों या उनका धुर विरोधी रूस और उनके टकराव से प्रभावित विकासशील देश, वे सभी भारत पर पूरा भरोसा करते हैं और इस समय यदि कोई देश दुनिया में स्थायित्व एवं शांति लाने में सबसे सार्थक भूमिका निभा सकता है तो वह भारत ही है।

● कुमार विनोद

भारत को मिली जी-20 की अध्यक्षता

भारत ने संकेत दिए हैं कि जी-20 अध्यक्षता के दौरान वह विकासशील देशों की आवाज को मुखरता से उठाएगा। वह ग्लोबल गवर्नेंस के लिए समाधान सुझाने में सक्रिय रहेगा। डिजिटल और डाटा के मोर्चे पर अपनी महारथ से दुनिया की मदद करेगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान तलाशने पर काम करेगा। भारत ने इस सिलसिले में काम भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी और चीनी तकनीक पर आश्रित दुनिया को उसने विकल्प देने की पहल की है। भारत के सफल डिजिटल भुगतान यूपीआई में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही स्वदेशी 5जी तकनीक भी कई देशों को लुभा रही है। वास्तव में भारत जी-20 की अध्यक्षता को बहुत गंभीरता से ले रहा है और उसने अपना एजेंडा बनाकर उसे अमल में लाना भी आरंभ कर दिया है। इसके माध्यम से भारत अपने विकास की गाथा दुनिया को दिखाकर वैश्विक ढांचे में और ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा। एक ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था महत्वपूर्ण मुद्दों पर मात्र मूकदर्शक बनकर रह गई हो तो जी-20 जैसे संगठन की भूमिका और अहम हो जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत के रूप में उसे उचित और वास्तविक नेतृत्वकर्ता भी मिला है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की आहट से परेशान है, तब भारत दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 'अंधेरे में उम्मीद की एकमात्र किरण' करार दिया है।

मैया मैं तौ जेल मंत्रि पद लैंहों

मैया मैं तो जेल मंत्रि पद लैंहों।
ईमानदार मैं कट्टर बनकर
घपले खूब बनैहों
मैया मैं तौ जेल मंत्रि पद लैंहों।

आठ किलो जब वजन बढ़ैगो
कोर्ट को अट्ठाईस कमहि बतैहों
न्यायिक सांच-झूंठ का जानै
तिन्हें पतली फोटो दिखेंहों
मैया मैं तौ जेल मंत्रि पद लैंहों।

बाहर की सुविधा सब खोटी
देखूं तो मम मंत्रालय की रोटी
जेल के अंदर बसेरा बनेंहों
मैया मैं तौ जेल मंत्रि पद लैंहों।

तूं चिंता मत करना माई, खूब मजे में तेरौ लाल
एसी टीवी अच्छा क्वाटर कैदी नौकर मोटा माल
मैं ही जेलर का मालिक हूं यहां और समय बितैहों
मैया मैं तौ जेल मंत्रि पद लैंहों।

भ्रष्ट काम कैसे होते थे, उनको कहते आए हम
और नए कैसे करना है उनको बतलाते हैं हम
थ्योरी योरी कुछ नहीं होती प्रैक्टीकल तोय बतैहों
मैया मैं तौ जेल मंत्रि पद लैंहों।

मसाज मलम्मत देखी होगी केवल पिक्चर मधि माई
कैसे करवाते छुटभैयों से बड़के कैदी 'भाई'
सीसीटीवी से पकड़ो जेंहों तो थैरेपी उसे बतैहों
मैया मैं तौ जेल मंत्रि पद लैंहों।

जांच वांच गर कोई होगी तो कोर्ट में अर्जी देंहों
फुटेज वे बाहर कैसे आगए दोषी को पकड़ेंहों
जेल कौ भ्रष्टाचार ठीक है, तिस दिखावो गलत बतेंहों
मैया मैं तौ जेल मंत्रि पद लैंहों।

कितना ही घोटाला करलूं फांसी न हो सकती
घर से ज्यादा जेल में मैया सरकारी सुविधा मिलती
लालू का चेला हूं माता उनहूं शिष्य बनाके दिखेंहों
मैया मैं तौ जेल मंत्रि पद लैंहों।

डॉ. महेन्द्रकुमार जैन
'मनुज', इन्दौर

तन्हाई

सृजना ऑफिस के लिए तैयार हो ही रही थी कि मां ने उसे पुकारा।

'मां जल्दी कहो क्या कहना है?'

'बेटा ललिता मौसी का फोन आया है। उन्हें क्या जवाब देना है?'

'मां आप समझती क्यों नहीं? आपसे पहले भी कई बार तो कह चुकी हूं। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी-अभी मैंने नौकरी ज्वाइन की है। आप हैं कि जब देखो शादी की रट लगाए रहती हैं।'

'बेटा कुछ तो खयाल करो तुम्हारे पापाजी का इसी साल रिटायरमेंट है। मैं चाहती हूं, रिटायर होने से पहले तुम्हारे हाथ पीले कर दूं।'

'तुम हो कि कुछ समझना ही नहीं चाहती हो।'

'ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी तो है? उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। हमें उसका भी तो ब्याह करना है।'

'मां! ये भी हो सकता है मेरे ससुराल वालों को मेरा नौकरी करना पसंद ही ना आए। मैं इस नौकरी को गंवाना नहीं चाहती। मुझे आजाद जिंदगी जीना पसंद है, बंधन में बंधना नहीं चाहती।'

'सृजना तुमने जब शादी नहीं करने का फैसला कर ही लिया है, तो ठीक है। मेरा तो यही ख्याल है कि सही उम्र में शादी-ब्याह के कार्य संपन्न हो जाए, बाकी तुम जैसा उचित समझो। ऐसा ना हो तुम्हे अपने इस निर्णय पर बाद पछताना पड़े। फिर न कहना समझाया नहीं था।'

'मां! सुनो आप मौसी को मना कर देना, मैं दफ्तर के लिए निकल रही हूं।'

'ठीक है, अपना ख्याल रखना।'

इसी तरह वक्त गुजारने लगा। पहले तो बहुत से रिश्ते मां ने सुझाए लेकिन सृजना को तरक्की की राह में शादी का बंधन रोड़ा ही लगा। वह हर रिश्ते को ठुकराती चली गई। उसके पापा रिटायर होने के बाद बीमार रहने लगे। छोटी बहन का ब्याह हो गया, वह पीहर कभी-कभी आती है। सृजना अपने कमरे में जब भी तनहा होती है यही सोचती है- मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई तो हो। मन करता है मुझे भी कोई चाहने वाला हो, लेकिन किससे कहूं? क्या पता था एक दिन अकेलापन काटने को दौड़ेगा? मैं अब अकेली अपनी ही तन्हाइयों से लड़ रही हूं।

- अर्विना गहलोत

महंगे-महंगे उपहारों का सच

मोनिका एप्पल कंपनी के आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स को हमेशा अपने हाथ में लिए रहती थी। उसे बड़ा गर्व था कि इतना महंगा फोन उसे गिफ्ट में उसके बॉयफ्रेंड विक्की ने दिया था।

मोनिका और विक्की की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं थी। मोनिका के सभी परिवारीजन मोनिका की प्रेमकथा से परिचित थे। आए दिन मोनिका कोई न कोई महंगा उपहार घर लाती ही रहती थी, जो उसे विक्की देता था।

एक दिन की बात है, मोनिका किसी काम से मार्केट गई थी। गर्मी व लू से बेहाल मोनिका अपना चेहरा दुपट्टे से ढके हुए थी। हाथ में फोन लिए वह एक दुकान के बाहर कुछ सामान देख रही थी कि तभी उसे जोर का धक्का सा लगा और दो लड़के टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल से महंगा फोन छीनकर फुर्र हो गए। पुलिस कंप्लेंट की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। एक वीडियो में वे लड़के साफ दिख रहे थे, उनके चेहरे पहचाने जा सकते थे। मोनिका ने जब वीडियो देखा तो वह दंग रह गई। मोबाइल फोन छीनने वाला कोई और नहीं उसका अपना विक्की था। अब महंगे-महंगे उपहारों का सच सभी को पता चल चुका था।

- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

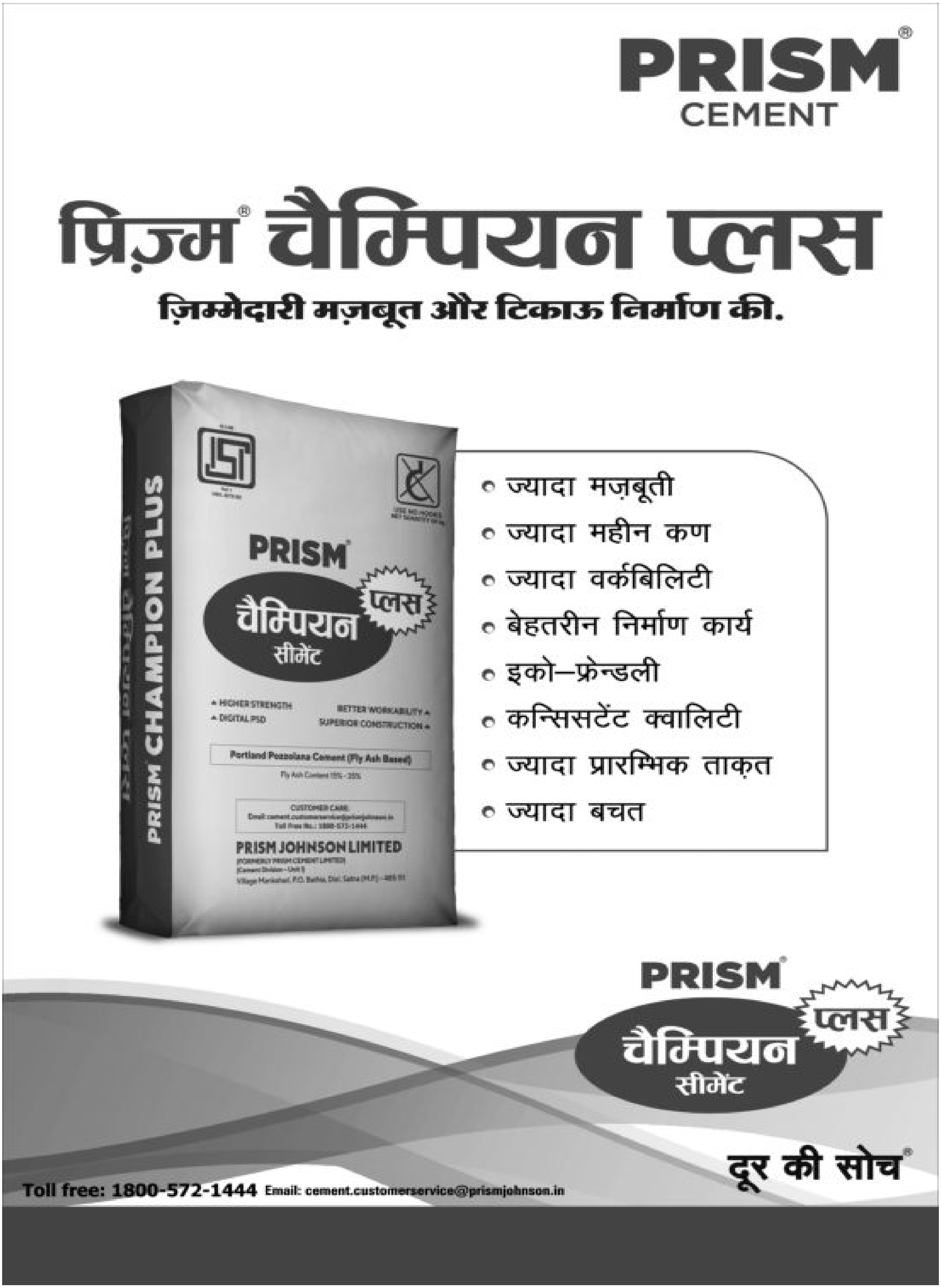
PRISM®
CEMENT
प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस
ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.
PRISM CHAMPION PLUS
PRISM
चैम्पियन प्लस
सीमेंट
HIGHER STRENGTH
DIGITAL PSD
BETTER WORKABILITY
SUPERIOR CONSTRUCTION
Portland Pozzolana Cement (Fly Ash Based)
PRISM JOHNSON LIMITED
ज्यादा मज़बूती
ज्यादा महीन कण
ज्यादा वर्कबिलिटी
बेहतरीन निर्माण कार्य
इको–फ्रेन्डली
कन्सिसटेंट क्वालिटी
ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
ज्यादा बचत
PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट
दूर की सोच®
Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

अब प्रयोग नहीं, स्थायी कप्तान की जरूरत

टीम को स्थाई कप्तान की जरूरत

बीसीसीआई को अब आगे प्रयोगों से बचते हुए नया स्थाई कप्तान नियुक्त करने की आवश्यकता है। भले वो हार्दिक हो या ऋषभ पंत। कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा के प्रदर्शन में भी गिरावट आई है। कप्तानी से मुक्त होने पर निश्चित ही रोहित दोबारा अपने पुराने रंग में दिखेंगे। बीसीसीआई को सीनियर खिलाड़ियों की गैर हाजिरी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी कई दौरों से गायब रहते हैं। कुछ चोटिल हो जाते हैं, जबकि इंडियम प्रीमियर लीग के दौरान उनकी उपस्थिति 100 प्रतिशत रहती है। इस बात की आलोचना अक्सर होती है और ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्डकप के दौरान इसे महसूस भी किया गया। जहां तक न्यूजीलैंड दौरे की बात है तो मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना हमेशा से मुश्किल रहता है। न्यूजीलैंड की पिच तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करती हैं। अत्यधिक ठंड होने के कारण भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि उन्हें ऐसे मौसम में खेलने की आदत नहीं होती।

ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और कप लेकर इंगलैंड की टीम घर लौट चुकी है, पर भारत की सेमीफाइनल में शर्मनाक हार के बाद सबकी नजरें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर हैं। कयास टीम इंडिया में अमूलचूल परिवर्तन के लगाए जा रहे हैं। खासकर निशाने पर कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिनका प्रदर्शन पूरे टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान बेहद दोयम दर्जे का रहा। रोहित शर्मा कोई भी बड़ी और जिताऊ पारी नहीं खेल सके। अब नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं तेज हो गई हैं।

बीसीसीआई लगातार प्लेइंग इलेवन को लेकर प्रयोग करता आ रहा है। शायद यह भी टी-20 वर्ल्ड कप में हार का कारण रहा है। बीसीसीआई लगातार शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत को आजमा रहा है। यह प्रयोग 18-30 नवंबर के बीच भारत-न्यूजीलैंड सीरीज में भी जारी रहा। बीसीसीआई से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उसकी क्या मजबूरी है, वो सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर कप्तान खोजो अभियान में जुटा है।

न्यूजीलैंड दौरे पर टी-20 और वनडे के लिए अलग-अलग कप्तान तय किए गए हैं। टी-20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे, जो एक हरफनमौला खिलाड़ी हैं। अपने आक्रामक क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक के नेतृत्व में जो टीम न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी, उसमें उप कप्तान ऋषभ पंत को बनाया गया है। ऋषभ भी बीसीसीआई की कप्तान प्रयोगशाला का हिस्सा हैं। हालांकि, उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली, जैसी उम्मीद की जा रही थी। कुछ लोग ऋषभ में भारत के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी खोजने लगते हैं, पर दोनों में तुलना नहीं हो सकती है। ऋषभ की उम्र अभी काफी कम है और उन्हें क्रिकेट में एक लंबा सफर तय करना है। न्यूजीलैंड के साथ खेल रही टीम में अधिकांश युवा चेहरे हैं। ऑलराउंडर दीपक हुड्डा व वॉशिंगटन सुंदर, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन व संजू सैमसंग, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, ओपनर शुभमन गिल, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, गेंदबाज यजुवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, उमरन मलिक को शामिल किया गया है।

वनडे टीम में शिखर कप्तान हैं और हार्दिक को आराम दे दिया गया है। शिखर के साथ उप कप्तान पंत समेत अधिकांश खिलाड़ी टी-20 टीम के हैं। दीपक चाहर, कुलदीप सेन, शाहबाज अहमद को वनडे टीम में शामिल किया गया, जबकि भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज को आराम दे दिया गया।

न्यूजीलैंड भेजी गई टीम को देखकर साफ लग रहा है कि बीसीसीआई भारत की टी-20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद सबक नहीं ले रही। आखिर टीम मैनेजेंट के आगे क्या मजबूरी है, जो अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पर चल रहे शिखर धवन को नेतृत्व दिया जा रहा है। क्या हार्दिक को वनडे की भी कमान नहीं सौंपी जा सकती? हार्दिक लंबे अर्से से बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। टी-20 वर्ल्डकप में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में टीम की जीत में उनकी भूमिका रही। सेमीफाइनल में उनके अर्द्धशतक की बदौलत टीम सम्मानजनक स्कोर बना सकी। हार्दिक की नेतृत्व क्षमता इंडियन प्रीमियर लीग और टीम इंडिया को लीड करने के जो मौके उन्हें मिले हैं, उसमें देखी जा चुकी है।

2019-20 में भारत ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था और टी-20 श्रृंखला को 5-0 से जीता था, जब न्यूजीलैंड 2021-22 में भारत आई थी, तब भी भारत 3-0 से विजयी रहा था। न्यूजीलैंड में 2019-20 में भारत को मेजबानों से 3-0 से शिकस्त मिली थी। वैसे, न्यूजीलैंड में कोच राहुल द्रविड़ को भी आराम दिया गया। द्रविड़ के पुराने साथी वीवीएस लक्ष्मण ने कोच की जिम्मेदारी निभाई। उम्मीद है कि न्यूजीलैंड में बीसीसीआई का कप्तानी को लेकर यह अंतिम प्रयोग होगा, इसके बाद टीम इंडिया को स्थायी कप्तान मिल जाएगा।

● आशीष नेमा

जब विक्रम गोखले के पास रहने को नहीं थी छत, तो सहारा बने थे अमिताभ बच्चन

वेटरन एक्टर विक्रम गोखले ने 77 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी भारी आवाज से मराठी थिएटर, हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में अपनी पहचान बनाने वाले विक्रम गोखले एक्टर चंद्रकांत गोखले के बेटे थे। उनकी दादी कमलाबाई गोखले भी इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल चाइल्ड आर्टिस्ट थीं।

फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद जब विक्रम गोखले ने बॉलीवुड डेब्यू किया था, तब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। उस वक्त अमिताभ बच्चन ही थे जो उनका सहारा बने थे। करीब 97 फिल्मों में नजर आ चुके विक्रम गोखले का ये सफर उतार-चढ़ाव से भरा था।

कैरियर के शुरुआती दिनों में विक्रम गोखले को मुंबई में काफी संघर्ष करना पड़ा था। उनके पास रहने के लिए न कोई घर था न ही किसी का आसरा। उनकी इस समस्या की जानकारी अमिताभ बच्चन को हुई थी, तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को विक्रम गोखले के आवास के लिए चिट्ठी लिखी थी। उनकी इसी चिट्ठी के आधार पर विक्रम गोखले को मुंबई में सरकारी आवास मिला था। अमिताभ बच्चन का ये एहसान वो कभी नहीं भूले थे। विक्रम जब भी अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बात करते, तो इस घटना का जिक्र जरूर करते।

ट्विंकल की वजह से बरसात फिल्म से बैकआउट हो गए थे अक्षय

2005 में रिलीज हुई फिल्म बरसात एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। फिल्म के लीड रोल में बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु नजर आए थे। शुरुआत में अक्षय कुमार को फिल्म के लीड रोल के लिए कास्ट किया गया था, यहां तक कि अक्षय ने प्रियंका के साथ एक गाना भी शूट कर लिया था लेकिन ट्विंकल खन्ना के ऑब्जेक्शन के बाद अक्षय फिल्म से बैक आउट हो गए। इसके बाद बॉबी देओल को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कास्ट किया गया।

अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने एक साथ काफी फिल्मों में काम किया है। 2003 से लेकर 2005 के बीच में दोनों ने अंदाज, मुझसे शादी करोगी और ऐतराज जैसी फिल्मों में काम किया। 2005 के बाद से ही दोनों किसी भी फिल्म में साथ नहीं दिखे। हालांकि दोनों का कैरियर अपनी-अपनी जगह सक्सेसफुल रहा है। दोनों की प्राइवेट

लाइफ भी सही है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को जहां 20 साल हो गए हैं वहीं प्रियंका चोपड़ा भी निक जोनस के साथ शादी करके सेटेल्ड हो गई हैं। निर्माता-निर्देशक सुनील दर्शन ने कहा- मुझे पता चला कि ट्विंकल को अक्षय और प्रियंका के एक साथ काम करने पर ऑब्जेक्शन था। ट्विंकल को प्रियंका चोपड़ा से काफी दिक्कत थी। इस प्रोफेशन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी व्यक्ति का अपना लाइफ स्टाइल प्रोफेशनल काम में दिक्कत पैदा कर देता है और मीडिया इन बातों को उड़ा देती है वो भी बिना सोचे कि एक फिल्ममेकर को इससे कितना नुकसान हो सकता है।

सिंगर नहीं बनना चाहते थे पापोन, एक्टिंग में भी आजमा चुके हैं हाथ

बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर पापोन ने हाल ही में अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट किया।

पापोन असम के रहने वाले हैं और 5 तरह की भाषाओं में गाना गाते हैं। वो कभी भी सिंगर नहीं बनना चाहते थे, पर किस्मत उन्हें वहीं खीच कर ले आई जिससे वो दूर भाग रहे थे। पापोन अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने के बाद आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन वहां रहते-रहते पापोन को समझ में आया कि उन्हें म्यूजिक में ही अपना कैरियर बनाना है।

फिर पापोन ने 26 साल की उम्र में सिंगर बनने का डिसीजन लिया। इसके बाद उन्होंने 2006 में फिल्म स्ट्रिंग्स-बाउंड बाय फेथ के सॉन्ग ओम मंत्र से बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत की। हालांकि उनको असली पहचान 2011 में आई फिल्म दम मारो दम के सॉन्ग जिएं क्यों से मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पापोन एक्टिंग में भी हाथ आजमा चुके हैं।

उन्होंने असम की फिल्म रोडोर सिथी से एक्टिंग डेब्यू भी किया है।

पापोन कहते हैं, हम जहां रहते हैं, वहां पर मंदिर नहीं होते हैं, कीर्तन घर होते हैं। प्रार्थना के नाम पर काफी म्यूजिक वहां होता है। मेरी फैमिली कई जनरेशन्स से उससे जुड़ी हुई है तो मेरे अंदर म्यूजिक वहां से आया होगा। फिर पिता जी फोक म्यूजिक में थे। उन्हें बिहू सम्राट बुलाया जाता था। मां क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ी हुई थीं। म्यूजिक तो था आसपास पर मैंने म्यूजिक बहुत लेट शुरू किया। उस समय मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छा गाऊंगा, तो लोग तो कहेंगे कि ये तो अच्छा गाएगा ही, क्योंकि ये इतने बड़े कलाकार का बेटा है। इन सारी चीजों की वजह से मैं डरता रहा और म्यूजिक छोड़ दिया था।

दो कानों की भी सुन लें

आपके साथ हर समय रहने वाले, सबकी अच्छी-बुरी सुनने वाले; हम आपके ही दो कान हैं। आप ये मत समझें कि हम आपके मेहमान हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमारा नहीं कोई मान-सम्मान है! हमारी भी अपनी एक पहचान है। हम आपके दिमाग के पड़ौसी भी हैं, इसलिए हमें भी तो कुछ ज्ञान है। हमारा भी कुछ न कुछ स्वाभिमान है। आपकी सब अच्छी-बुरी हरकतों; हरकतों नहीं, गतिविधियों का हमें पूरा-पूरा संज्ञान है।

हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। परंतु अपनी अनदेखी भी हमें सहन नहीं है। लगता है परमात्मा ने हमें किसी मृत्युभोज की बची हुई पूड़ियों में से उठाकर दो सूखी हुई पिचकी-सी पूड़ियां यहां गालों के दोनों ओर चिपका दीं। उन्होंने हमारे हित के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि नहाते-धोते समय या वर्षा में भीगते समय वर्षाजल सीधे हमारे भीतर न चला जाए इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा है। परंतु शिकायत तो मुझे आपसे है अर्थात् आदमी से है। वह यह है कि आपने हमें लोहे या लकड़ी की खूंटी समझ लिया है। किसी की नेत्र दृष्टि कमजोर हुई या धूप में चश्मे की डंडियों को लिया और हमारे ऊपर टेक दिया। कभी आंखों ने हमसे अनुमति ली या उसका आभार व्यक्त किया कि एक अनावश्यक बोझ हमारे ऊपर लाद दिया है? नारियों ने अपने श्रृंगार के लिए झुमके, बालियां, लोंगें हमें छेद-छेद कर हमारे ऊपर ही टांग डालीं! भला ये भी कोई बात हुई। सुंदरता में नाम हो मुखड़े का और हम दोनों लद्दू घोड़े की तरह लादे जाएं? हर मुखांग का इतना श्रृंगार कि कान तो अंधे और बहरे हैं! आंखों के लिए काजल, नाक के लिए नथुनिया या लोंग, होठों के लिए लिपिस्टिक, गालों के लिए गुलाबी रूज, पूरे मुखड़े पर पोतने के लिए क्रीम, जाड़े के अलग, गर्मी की अलग और हमारे ऊपर बोझ ही बोझ। भला यह कौन सा औचित्य है?

मिस्त्री साहब को घुसेड़ने के लिए कानों के छेद ही मिले, जो बचे हुए गुटके की गंदी और बदबूदार नशीली पुड़िया हमारे भीतर ही ठूंस डाली। टेलर मास्टर और बढ़ई को भी हमीं मिले और अपनी घिसी हुई पेंसिल का ठूंठ अटकाने के लिए हमारा ही हैंगर बना डाला! उधर आंख के अंधे नयन सुख नाई ने बाल काटते-काटते कैंची हमारे ही ऊपर चला डाली और हमें लहूलुहान कर डाला। भला ये भी कोई बात हुई? जब देखा तो थोड़ी सी डिटॉल की फुरहरी से हमें सहला दिया और च्च! च्च!! करते हुए अफसोस जाहिर करने का नाटक करने लगा। ग्राहक भी तिलमिलाया, पर क्या करता बेचारा, उसने भी भूल समझकर ज्यादा मुंह नहीं खोला।

पंडित जी ने भी अपने ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए हमें ही पाया। अपने तीन धागों के जनेऊ को हमारे ऊपर ही टांग दिया और लघु या दीर्घ शंका के समय हमारे ही ऊपर अंटा मार दिया। कभी-कभी तो लोहे और पीतल की चाबियों का गुच्छा ही हमारे ऊपर बोझ बना दिया, नाम जनेऊ का और बोझ से मरें हम कान! वाह रे स्वार्थी इंसान! क्या इसीलिए दिखाता है अपनी कोरी शान। कुछ स्वावलंबी भी बनना सीख। क्यों मांगता है हम कानों से मदद की भीख?

मिस्त्री साहब को घुसेड़ने के लिए कानों के छेद ही मिले, जो बचे हुए गुटके की गंदी और बदबूदार नशीली पुड़िया हमारे भीतर ही ठूंस डाली। टेलर मास्टर और बढ़ई को भी हमीं मिले और अपनी घिसी हुई पेंसिल का ठूंठ अटकाने के लिए हमारा ही हैंगर बना डाला! उधर आंख के अंधे नयन सुख नाई ने बाल काटते-काटते कैंची हमारे ही ऊपर चला डाली और हमें लहूलुहान कर डाला।

बचपन में मास्टर जी ने भी हमें सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कमजोर बच्चों के कान मरोड़कर ही उन्हें सदबुद्धि उलीच डाली। अब कहां तक कहें अपनी पीड़ा! गाली हो या ताली, गीत हो या पटाखों का विस्फोट! सब हमें ही सुनना है। हम तो जैसे किसी गाड़ी की कोई फालतू एक्सेसरीज हैं, जिन्हें खोलकर फेंक दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक बार भी क्या करके देखा? करके देखो तो पता लग जाए कि कान का भी कुछ महत्वपूर्ण काम है, उसके ऊपर क्यों लटका देते अनावश्यक झाम हैं? हमें तो आपके मुहावरों ने ही हमें कर रखा बदनाम है! कान का कच्चा होना, कान पकना, कान में तेल डालना, दीवारों के कान होना आदि आदि। अब आप ही सोचें कि यदि हम कच्चे होते आप एक बैलगाड़ी का बोझ हमारे ऊपर लादकर नहीं चलते! यदि पक जाते तो क्या आपके खाने से बच पाते? हमें केवल एक मशीन, श्रवण यंत्र मात्र समझ रखा है, देह का अंग नहीं समझा, इसलिए हममें तेल डालने की बात होती है। यदि दीवारों के कान हुआ करते तो हमारी ही क्या आवश्यकता रहती? ये सब सोचने की बातें हैं। पर सोचे कौन? बस अपना उल्लू सीधा हो जाए और क्या!

सुना है। आप ही लोगों के मुंह से सुना है कि कहकर मन हलका हो जाता है। पर हमारे पास तो न मुंह है और न ही मन। फिर भी अपनी बात, अपनी वेदना, अपनी शिकायत, आपकी शिकायत आपसे से करेंगे, कहीं जा भी तो नहीं सकते; आप से ही करेंगे। कर ली। यदि आप पर कुछ असर पड़ा हो, तो बताना। आपके पास तो एक अदद मुंह भी है। हम गूंगे अवश्य हैं, पर बहरे तो कदापि नहीं। जो कुछ कहा है, वह होगा भी सही। हम कान हैं कान, बात को धर लेना अपने ध्यान। दो भाई। जिन्होंने आज तक कभी भी एक-दूसरे को नहीं देखा। देखेंगे भी नहीं।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव
हम बच्चों का भविष्य संवारते हैं
इसलिए
कोयला निकालते हैं
KAYAKALP VATIKA CCL PPR
कोल इण्डिया
Coal India
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अनुषंगी कम्पनी
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CCLRanchi
CentralCoalfieldsLtd
centralcoalfieldsltd
Central Coalfields Limited
cclranchi

अल्ट्राटेक
देश का नं.1 सीमेंट
घर एक, मौक़ा एक,
इसीलिए सीमेंट भी
देश का नं. 1
UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice
INDIA'S NO.1 CEMENT
ultratechcement.com